Vol. 237
No. 02

Friday
27 November, 2015
06 Agrahayana, 1937 (Saka)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Member sworn (page 1)

Allocation of time for disposal of Government Legislative and other Business (pages 1-2)

Discussion on commitment to India's Constitution as part of the 125th Birth Anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar (pages 2-9 and 9-90)

Welcome to Parliamentary Delegation from Slovenia (pages 9)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE : ₹ **100.00**

Website : http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail : rsedit-e@sansad.nic.in

Published under Rule 260 of Rules of Procedure and Conduct of Business
in the Council of States (Rajya Sabha) and Printed by Printograph,
Karol Bagh, New Delhi-110005

RAJYA SABHA

Friday, the 27th November, 2015/6, Agrahayana, 1973 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

MEMBER SWORN

Shri N. Gokulakrishnan (Puducherry)

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 26th of November, 2015, allotted time for Government Legislative and other Business, as indicated below:-

Business	**Time Allotted**
1. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:-	
(a) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2015.	four hours
(b) The Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015.	one hour *(To be discussed together*
(c) The Repealing and Amending (Third) Bill, 2015.	
(d) The Whistle Blowers Protection (Amendment) Bill, 2015.	three hours
2. Further Consideration and passing of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2015, as passed by Lok Sabha.	four hours
3. Further Consideration and passing of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013.	three hours

Business Time	**Allotted**
4. Consideration and passing of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012.	four hours
5. Consideration and passing of the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015.	two hours
6. Further Consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Twenty Second Amendment) Bill, 2014, as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha.	four hours
7. Consideration and passing of the Real Estate (Regulation and Development) Bill, 2013, as reported by the Select Committee of Rajya Sabha.	two hours

The Committee also recommended that in view of the adjournment of the House for the day on Thursday, the 26th of November, 2015, as a mark of respect to the memory of Shri Khekiho Zhimomi, sitting Member, the Discussion on 'Commitment to India's Constitution as part of the 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar', previously scheduled for the 26th and 27th November, 2015, will now be taken up on Friday, the 27th of November and Monday, the 30th of November, 2015. Accordingly, there will be no Zero Hour, no Question Hour or any other Business on Monday, the 30th of November, 2015.

DISCUSSION ON COMMITMENT TO INDIA'S CONSTITUTION AS PART OF THE 125TH BIRTH ANNIVERSARY CELEBRATION OF DR. B.R. AMBEDKAR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as decided yesterday and in view of the adjournment of the House due to the passing away of a sitting Member, the discussion scheduled for November, 26th and 27th will now be held today and on Monday, the 30th.

Hon. Members will recall that in terms of the 'Oath or Affirmation' prescribed in the Third Schedule of the Constitution, they undertake to - and I quote: "bear true faith and allegiance to the Constitution of India". Our discussion today and on Monday will undoubtedly focus on the contribution of Dr. B.R. Ambedkar to the framing of the Constitution.

I now request the Leader of the House to initiate the discussion.

सभा के नेता (श्री अरुण जेटली) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। डा. भीमराव अम्बेडकर के जन्म का यह 125वाँ वर्ष है। इस देश में केवल संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में, रिफॉर्मर के रूप में उनका योगदान किसी अन्य से कम नहीं रहा। जिस परिस्थिति में वे पैदा हुए, बड़े हुए, जिस अन्याय का सामना उनको करना पड़ा, लोकतंत्र के दायरे में, लोकतंत्र की संस्थाओं में विश्वास रखते हुए उस अन्याय के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जा सकता है और समाज उस अन्याय की परिस्थिति से बाहर निकले, उसके क्या-क्या रास्ते तय कर सकते हैं, वह मार्ग उन्होंने इस देश को बताया है। जिस संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के वे अध्यक्ष थे, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम समय में, कुछ महीनों में उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी कार्रवाई पूरी की थी और उसके बाद जब वह संविधान सभा में जाता था, तो जो संविधान का एक-एक अंश होता था, उसके सम्बन्ध में उनकी जो टिप्पणी रहती थी, आज भी उस संविधान की मूल भावना को समझना और उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या तर्क रहे, डा. अम्बेडकर के संविधान सभा में जो वक्तव्य थे, वे आज भी समाज के लिए बहुत महत्व के हैं। आज उस संविधान को बने 65 वर्ष हो चुके हैं और जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं कि इस 65 वर्ष के युग में पूरी दुनिया के अन्दर कितने परिवर्तन आए, तो कितने ऐसे देश थे, जहाँ लोकतांत्रिक हुकूमतें समाप्त हो गईं, फौज ने हुकूमत सँभाल ली है; कितने ऐसे देश थे, जहाँ किसी व्यक्ति के आधार पर तानाशाही पैदा हो गई; कितने ऐसे देश थे, जहाँ धर्म के आधार पर कोई तानाशाही पैदा हो गई, लेकिन यह उस संविधान का एक योगदान था और इस देश में जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया गया, उसका एक योगदान था कि जब कभी हमारी किसी संस्था पर या लोकतंत्र पर खतरा भी मँडराया, तो समाज में इतनी ताकत थी कि हम उसके साथ निपट पाए और हर परिस्थिति के उपरांत इस देश का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएँ और मजबूत होकर बाहर निकली हैं। कई बार हमें यह सोचना पड़ेगा कि 1947 से पहले यह देश बहुत बड़ा था, 1947 में बँटवारा हुआ, एक ही प्रकार के लोग जब दो हिस्सों में बँट गए, तो क्या कारण था कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता चला गया, पर पड़ोस में ऐसी स्थिति नहीं थी और शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की और लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, उनको मजबूत किया, उनका भी अपना योगदान था। मैं कई बार सोचता हूँ कि कुछ अंतर ऐसे थे, जो स्पष्ट रहे। हमारा चुनाव आयोग ऐसा था, जो निष्पक्ष चुनाव करवाता था। हमारी न्यायपालिका ऐसी थी, जो स्वतंत्र थी, जो केवल सरकार क्या चाहती है उसको देखकर अपना निर्णय नहीं करती थी। हमारी सेना और फौज ऐसी थी, जो प्रोफेशनल थी, जिसने राजनीति के साथ जो एक फासला होना था, वह हमेशा बनाकर रखा और इन सब संस्थाओं का, जिनको हमारे निर्माताओं ने खड़ा किया, उनका एक योगदान रहा। आज हमारा भी दायित्व है कि एक बार मुड़कर इन सब संस्थाओं पर और जो संविधान डा. अम्बेडकर ने बनाया और हमें दिया, वह कैसे चला है, उसके ऊपर भी विचार कर लें।

सभापति जी, मैं तो स्वतंत्रता के साढ़े पांच, छह साल बाद पैदा हुआ और इसलिए स्वाभाविक है कि मुझ जैसे लोगों का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं था। मैं जिस राजनैतिक संगठन से आता हूँ, उसके जो प्रेरक थे डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे उस संविधान सभा के सदस्य थे और उनका भी योगदान अन्य संविधान सभा के महान नेताओं के बीच में एक सदस्य होने की वजह से रहा था। आज

[श्री अरुण जेटली]

एक अवसर है, इस संविधान का विश्लेषण कर लेने का और जहां-जहां हमें लगता है कि इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से गंभीरता से उन विषयों के ऊपर चिंतन कर लेने का। इस संविधान की जो मूल ताकत हैं, वे मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान निर्माताओं ने हमें दिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पंडित मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनी थी, जिसने एक चार्टर बनाया था, ये उसके ऊपर आधारित हैं। मैं मानता हूँ कि जो मूल भावना है, the core values of our Constitution are expressed in them, बराबरी का अधिकार, किसी के खिलाफ भेदभाव न हो, उसकी एक मूल भावना, अभिव्यक्ति का अधिकार, देश में कहीं रहने का अधिकार, जिस मज़हब या धर्म में विश्वास है उसको प्रचलित करने का अधिकार, ये संविधान की मूल भावनाएं हैं। कई बार आज इनके ऊपर भी संकट आया है और मैं दो विशेष उदाहरण देना चाहूंगा, जिसे मैं मानता हूँ किं सविधान सभा में जो यह बनाया गया, उसमें भी कई बार सुधार की आवश्यकता है। संविधान सभा ने यह लिखा था कि जब देश पर गहरा संकट आए, तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। उसकी एक बहुत बड़ी कीमत इस देश को अदा करनी पड़ी थी। जब 1977 में श्री मोरारजी भाई की सरकार बनी, तो उनकी सरकार का लक्ष्य एक बहुत बड़ा सुधार करने का था। The original Constitution provided for article 21 which speaks of life and liberty for every citizen, and that life and liberty cannot be denied to any one without a due process. The Constitution had used a different language, but the courts have interpreted it more liberally now. During the 1970s, one of the biggest challenges we faced was that article 21 was suspended, and the Government succeeded in convincing the Supreme Court that if article 21 was suspended -- because it was suspendable -- the citizens of India would lose the right to life and liberty. This was dictatorship at its worst. सबसे बड़ा अधिकार, जीने का अधिकार है। आज तो अगर कोई आदमी टेलिविज़न की स्क्रीन पर आकर ग़ैर-जिम्मेदाराना बयान दे दे, तो हम इसको इन्टॉलरेंस मान लेते हैं, लेकिन उस वक्त तो यह स्थिति थी कि अगर नाजायज़ तरीके से आपका जीवन भी छीन लिया जाए ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): There is no comparison.

SHRI ARUN JAITLEY: Of course, there is no comparison. The difference is between a mouse and a molehill. …*(Interruptions)*…

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उस समय उन्होंने...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Silence, please. ...*(Interruptions)*.... Silence please. ...*(Interruptions)*.... Please continue.

SHRI ARUN JAITLEY: So, the argument was that article 21 is suspendable; people lose the right to life; people lose the right to liberty. They can be jailed without reason; they can be killed without reason, and people will have no remedy. And those who now claim to swear by the Constitution supported this position. It goes to the credit of our Prime Minister, Shri Morarji Desai, and his Government… ...*(Interruptions)*....

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश) : अम्बेडकर जी के संविधान ने ...(**व्यवधान**)...

urdu matter page 5

श्री शान्ताराम नायक : सर, उस समय की बात ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*.... शान्ताराम जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. ...*(Interruptions)*.... Please sit down. ...*(Interruptions)*.... Please allow the discussion to continue. ...*(Interruptions)*.... आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... भाई, आप बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... Why are you wasting precious time? Please sit down. ...*(Interruptions)*.... Continue, please. ...*(Interruptions)*....

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (गुजरात) : उनको हटाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : आप मोरारजी देसाई जी की बात करते हैं, जवाहर लाल नेहरू जी की बात क्यों नहीं करते? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा, अभी आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... भाई, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please continue.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, it goes to the credit of the Government -- since that Government comprised mostly of people who had suffered because of the suspension of article 21 -- that they realized this great gap in the Constitution, that the Constitution was amended, and rightly so, and article 21 was made permanently non-suspendable. So, today we are far more safe and far more secure.

Sir, there was one more change. Normally, Fundamental Rights – and this is the wisdom of hindsight – should never so easily be interfered with, getting carried away with the economic policies of that time. Let us just remember – I am just flagging that point and leaving it at that – that one of the Fundamental Rights that the Constitution had given to every citizen was also the right to acquire and own property. It was a Fundamental Right. Since, we were then swayed by a different set of economic policies, there was a big campaign and the only Fundamental Right which has been repealed in India during the 1970s was the Right to Property, to own and acquire property. This was subsequently brought in as an ordinary Constitutional right under Article 300A. I am not advocating anything else. During the last few years, a debate over the Land Bill has taken place in this country. I would just urge all hon. Members and other thinkers in the Indian

†Transliteration in Urdu Script.

[Shri Arun Jaitley]

society to ponder over the fact, just as a part of transient economic thinking at any given point of time, that whether we should get so over-swayed and tinker with Fundamental Rights. I am just flagging this issue and since we are discussing the Constitution, which Dr. Ambedkar had drafted and he had put this as one of the rights, we thought it was progressive enough to repeal it and then forty years later, we came out with a contrarian argument in the Land Bill. I think it is about time that the last seventy-year debate on this issue, some of us must now try and revisit that shortsome vision in dealing with Constitutionalism which is not necessarily the correct perspective to have.

Sir, the other high point of the Constitution which we need to, today, analyze is the concept of federalism that Dr. Ambedkar envisaged. संघीय ढांचे के सम्बन्ध में कई प्रावधान किये गये हैं, लेकिन पहले 20-30 वर्षों में संघीय ढाँचे का इतना महत्व है, यह बात समझी नहीं गयी, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि शायद देश की एकता बरकरार रखनी है, sovereignty and unity is to be preserved और उसके लिए unitary style शायद बेहतर होगा। मैं जिस विचारधारा से सम्बन्ध रखता हूँ, मेरे भी नेताओं को उस वक्त शायद कभी यह विचार आता था, लेकिन जब वह खतरा टल गया, तो हर प्रांत के अन्दर मैं अपने प्रावधान को मजबूत करूँ, अपने क्षेत्र को मजबूत करूँ, यहाँ लोगों का विकास हो, so federal feelings in India have become real and genuine. And, therefore, it is a reality that we have to recognize. More financial power to the States is one high point which we have been evolving over the years. There is a second high point that how many times in the first forty years, when we almost had a one party rule at the Centre, Article 356 was used against the States. The moment we realize the high importance of federal politics and the federal character of India, you had coalition Governments; you had regional parties emerging; you had regional parties becoming extremely important part of Central Governments. This had led to the strengthening of federalism and that is why, we now proudly use words like 'cooperative federalism' and one great aspect of it has been that after misusing it several times during one party rule at the Centre, the misuse of Article 356 in India has gradually been phased out. And, therefore, these days the fears of Article 356 being violated repeatedly or repeatedly being used against the States have disappeared. There is hardly a regional party here.....

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): The Judiciary played a role.

SHRI ARUN JAITLEY: I think the Judiciary played an important role. I think the emergence of regional parties as part of the Central Government played a role, and the fact that this misuse is counterproductive, also played a role.

Sir, the important aspect, I think, we need to seriously introspect is also our strength

of democracy, the Constitution and the institution of free and fair elections. The Election Commission has become a very professional and a competent institution. The largest global election it can conduct with utmost ease. There was violence, there was booth capturing. The Election Commission has now devised methodologies to overcome it. Now for the last ten to fifteen years, we don't hear about booth capturing. But there is one challenge that we have to seriously introspect, that is, the excessive use of money power. That is the challenge to which we still have to find a solution.

This brings me to two important issues. One, relating to the separation of powers and the second relating to the independence of Judiciary. The separation of powers between the Executive, the Legislature and the Judiciary, I think, was one of the core ideas Dr. Ambedkar gave to us. Independence of Judiciary, I straightaway concede, as part of the basic structure is absolutely essential. But there are two points which need to be flagged. If there is a dilution of separation of powers which is taking place, the dilution is not coming from either the Executive or the Legislature; it is not coming from the Central Government; it is not coming from State Governments. In fact, what started as a positive note in terms of activism by courts, at times, a question is raised that does it cross the Lakshman rekha of separation of powers? The argument given is, if the Legislature and the Executive don't act, we have a power to interfere. Well you have a power to direct, but power to assume the function of the Legislature or the Executive, I think, is something which goes beyond the concept of what Dr. Ambedkar in the separation of powers envisaged. Therefore, today, as we pay our tributes to Dr. Ambedkar, we require judicial statesmanship, and an equal amount of statesmanship and vision by the Executive and the Legislature to maintain this delicate balance is required. No law can maintain this balance. It is an element of self-disciplining which is required to maintain this balance because once this delicate balance is upset, the constitutional balance itself will be upset. Therefore, I can count hundreds of illustrations and people who are more experienced than me in State Governments will give many more. How many calories are to be fed to the terrorists when a security operation is on? There are no judicially measurable standards by which it can be determined. It is for the security forces to decide. How many bullets are to be fired in an encounter, can't be determined by courts. How are our town planning schemes and clearances to be done? Are people going to be uprooted completely overnight? The social responsibility of looking after them also belongs to the States. These are factors in the separation of powers which we will have to keep in mind. I don't think there is any section of this House, which would ever say that independence of Judiciary is not a part of the basic structure. But, Sir, I have said it outside and I have

[Shri Arun Jaitley]

no hesitation in repeating it out. The spirit of the original Constitution in matters relating to the Judiciary, today, the absolute contrary of what Dr. Ambedkar had envisaged and stated, is happening. In respect of Articles 124 and 217, which deal with the appointment of Judges of the Supreme Court and the High Courts, Dr. Ambedkar, in his intervention, said, in the Constituent Assembly, "Is this power to be left to the Judiciary alone?" And, he said, the answer is 'No'. "Is it to be left exclusively? Is it the lastwordtobeoftheExecutive?"Theansweris'No'.Ithastobedonebyaconsultative process." And, therefore, the Constitution, that he framed clearly, said that President of India will appoint, in consultation with the Chief Justice. And today, we have reached a situation where the Chief Justice of the Collegium will appoint and everybody else is irrelevant. Can the Constitution ever be interpreted to mean the opposite of what the Constitution says? No principle of interpretation of law can ever justify that. Secondly, the rationale on which it is based is that independence of Judiciary is a part of the basic structure of the Constitution. Of course, it is. But then, Parliament is also a part of the basic structure and elected Council of Ministers and the Prime Minister are also a part of the basic structure. The Leader of the Opposition, expressing the alternate view in Parliament, is also a part of that basic structure. Now, to say only one basic structure will prevail and the others become irrelevant, again upsets the delicate constitutional balance that Dr. Ambedkar gave to this country. And, I think, it is extremely important, while we pay tribute to him, that we, certainly, discuss and ponder over these ideas that he gave, and to the extent that we have deviated away from them. Sir, improvement in the ideas was always welcome like, decentralized democracy, in terms of Panchayats and Municipalities and regional democracy evolved, an experiment which has served us well. I think the most important is the whole concept of affirmative action. Affirmative action was not creating a preferred class. संविधान ने यह कहा है कि सबको बराबरी का अधिकार है। जाति, धर्म, मजहब, कास्ट, क्रीड के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं या जो एससी या एसटी हैं, उनके लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे - यह संविधान ने कहा। And the object behind this was that whereas all human beings were created as equals, a social structure has made some as unequal and, therefore, affirmative action is required to bring them to the level of equality. That is the concept of Article 15(4) that he introduced and, I think, it is the spirit of that Article which we have to continue to honor and respect. Sir, a large part of the debate, -- I have read in the newspapers about what is being debated in the other House and elsewhere -- is also on this concept of the freedom of religion, the right to practice and propagate your religion. सैकुलरवाद क्या है, संविधान में था या नहीं, इसे लेकर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना विषय उठाना चाहता हूं किं सविधान में, चाहे इस

शब्द का प्रयोग वर्ष 1950 में हुआ या नहीं, कल्पना क्या थी, what the concept was. Article 14 said, "The State shall not discriminate against anyone". Article 15 went a step further and said that on the basis of caste, creed, religion, etc., you will not discriminate. And, I think, this was fundamental to the Constitution. Article 25 said, "Every man has the right to practise and propagate his religion". Articles 29 and 30 gave some special rights for minorities. What do we conclude from this? The Constitution, envisaged by Dr. Ambedkar, was not anti-religion or irreligion. It rejected theocracy. The State will have no religion; the State will not discriminate on the basis of religion; the State will have a non-discriminatory attitude, but everybody will have the right to propagate his religion. Now, let me tell you three or four illustrations how, in the last 65 years, we have somewhat subverted this whole thought.

MR. CHAIRMAN: Arunji, may I just take a minute?

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM SLOVENIA

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make. We have, with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from the Republic of Slovenia, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency, Dr. Milan Brglez, President of the National Assembly of the Republic of Slovenia.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the Delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and a fruitful stay in our country. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and the Republic of Slovenia. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of the Republic of Slovenia.

DISCUSSION ON COMMITMENT TO INDIA'S CONSTITUTION AS PART OF 125TH BIRTH ANNIVERSARY CELEBRATION OF DR. B.R. AMBEDKAR – *Contd.*

सभा के नेता (श्री अरुण जेटली): सर, अगर संविधान की religious freedom के बारे में यह कल्पना थी, तो पिछले 65 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है? मान लीजिए, आज यह सदन दुबारा

[श्री अरुण जेटली]

संविधान सभा बन गया होता और डा. अम्बेडकर इसमें खड़े होकर, उन्होंने 25 नवम्बर, 1949 को जो कहा, संविधान को प्रपोज करते और डा. अम्बेडकर इस संविधान सभा में, आज 2015 में कहते। आर्टीकल 44, यह कोई हम नहीं लाए हैं- "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India".So, if Dr. Ambedkar had today stood up and proposed this provision, how would this House have reacted? अगर डा. अम्बेडकर आर्टिकल 44 को 1950 के स्थान पर 2015 में प्रपोज़ करते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? अगर डा. अम्बेडकर ...(**व्यवधान**)...

SHRI SITARAM YECHURY(West Bengal): These are Directive Principles. You know as much as I know. These are Directive Principles. Do not stretch that argument to such a level.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Speaker continue.

SHRI ARUN JAITLEY: We will go beyond Directive Principles now. अगर डा. अम्बेडकर संविधान की धारा 48 को 2015 में प्रपोज़ करते, जिसमें लिखा है – मैं पढ़ देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे – "The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle." So if Dr. Ambedkar had proposed Article 44 and Article 48 today, how many of you would have accepted it, as Shri Sitaram Yechury says, even as a Directive Principle? और केवल यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं था। सीताराम येचुरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी भावना के तहत, जब पंडित जी प्रधान मंत्री थे, इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं, तब आर्टिकल 48 के तहत उन्होंने राज्यों को लिखा कि कानून बनाओ और पूर्वोत्तर बंगाल और केरल को छोड़कर इस देश के हर राज्य ने कानून बना दिया। ...(**व्यवधान**)... चूंकि सीताराम येचुरी जी बहुत प्रगतिशील हैं, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, मैं इससे दो कदम ...(**व्यवधान**)...

श्री सीताराम येचुरी : सर, मैंने नहीं कहा। यह कॉंस्टीट्यूशन कहता है।...(**व्यवधान**)...

श्री अरुण जेटली : इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। सर, मैं केवल 65 वर्ष की जो वैचारिक यात्रा हुई है, उसका जिक्र कर रहा हूं। मैं आपको एक बहुत सरल प्रावधान बतलाता हूं। डा. अम्बेडकर ने संविधान में एक प्रावधान डाला, जिसका बहुत कम जिक्र होता है, आर्टिकल – 13 और आर्टिकल 13 यह कहता है किं सविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, Fundamental Rights दिए गए हैं - Article 14-equality, Article 19-freedom, Article 21-liberty, life, dignity - ये सारे सर्वोच्च हैं, सुपीरियर हैं और इस देश का कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो इनका उल्लंघन कर सकता है। अगर कोई पुराना कानून है जो इनका उल्लंघन करता है तो वह कानून समाप्त हो जाएगा। Dr. Ambedkar gave primacy to equality, life, liberty and dignity, the Fundamental Rights.

SHRI SITARAM YECHURY: Mr. Jaitley, if you don't mind, I wish to make a point.

You see, you have quoted article 44. You just go to article 43A. It says, '...by suitable legislation...to secure the participation of workers in the management of undertakings,...' Has that been done?

Look at article 45. It says, 'The State shall endeavour to provide early childhood care and education...' Has that been done?

Then, go to article 46. It talks about promotion of educational and economic interests of SCs, STs and other weaker sections...*(Interruptions)*....But, you choose one article 44 and another article 48...*(Interruptions)*....What about providing special care? What about providing all these?

MR. CHAIRMAN: Sitaramji, please, do it when your turn comes. ...*(Interruptions)*....

SHRI SITARAM YECHURY: So, don't pick and choose. That is what I am saying... *(Interruptions)*....

SHRI ARUN JAITLEY: I think, I am glad that my friend Sitaram's best argument is that we must have equality in the matter of not following the law, because one provision has not been followed the other should not be followed.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am saying you should follow the entire law... *(Interruptions)*....No, you are not following the entire law. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: I would request all the concerned to allow the discussion... *(Interruptions)*....

SHRI SITARAM YECHURY: Why are you picking and choosing, Sir? That is my point*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You can speak when your turn comes. *(Interruptions)*... Mr. Tapan Sen, please.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, let me make a suggestion. I think, Mr. Yechury will agree with me on his last suggestion.

Dr. Ambedkar brought article 13 to say that no law can violate the Fundamental Rights. Let us forget article 44 and Uniform Civil Code for the time being. So, I am not going so far. We still have personal laws, across religions, which violate the Fundamental

[Shri Arun Jaitley]

Rights. Sir, sixty-five years after he framed the Constitution, all of us are ready to say that all personal laws must be compliant with the Constitution. My point, therefore, is look at the ideological journey that we have had in the last sixty-five years. What did the Constitution say? The Constitution says, 'no theocracy', 'no State religion', 'no discrimination on grounds of religion.' But, then, the Constitution says that there are certain aspects which may have either economic or social rationale will have to be preserved. The Constitution said that all laws must be compliant with the Constitution. And, because we have subverted our ideological thinking, we are embarrassed about article 44. We are embarrassed about personal laws being Constitutionally compliant. We are embarrassed about article 48. I will give you another illustration.

SHRI SITARAM YECHURY: No, no. I am saying what about others.

SHRI ARUN JAITLEY: I will give you another illustration. मैं चाहूंगा कि आपके साथ, जो हमारे साथी शरद यादव जी बैठे हुए हैं, बहन जी बैठी हैं, ये इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। यह बहुत गंभीर विषय है। संविधान में दो वर्गों को दो सुरक्षाएं दी गई हैं। एस.सी./एस.टी. को और socially, educationally backward को आर्टिकल 15 के तहत विशेष अधिकार मिले और उन विशेष अधिकारों का हम आदर करते हैं। ...(**व्यवधान**)... आर्टिकल 15 के तहत एक पैकेज एस.सी./एस.टी. और socially, educationally backward के लिए बना और socially, educationally backward में किसी भी धर्म के लोग आ सकते थे। एस.सी./एस.टी. का एक विशेष दर्जा था। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के लिए बना कि उनको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना धर्म, उसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करने का अधिकार है, अपने शैक्षणिक इंस्टिट्युशन्स को प्रिंजव करने का अधिकार है, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 के अधिकार के बारे में कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में कहा कि जो मॉइनारिटीज़ एजुकेशनल इंस्टिट्युशन्स चलाएंगी, वहां 50 परसेंट उनको अपने बच्चे दाखिल करने पड़ेंगे। इस तरह से दो अलग-अलग पैकेजिज दे दिए गए। आगे नई सोच आ गई कि एक वग को आर्टिकल 15 का प्रोटेक्शन मिलेगा, एक को आर्टिकल 29, 30 का मिलेगा। अब राजनीति की मजबूरी यह थी कि जो धर्म परिवतन कर ले, उसको आर्टिकल 15 का प्रोटेक्शन भी दे दो और आर्टिकल 30 का भी दे दो। I hope, I am clear in what I say. Article 15 was meant for SC/ST and educationally and socially backward classes, Article 29 and 30 were meant for minorities. So, you can choose which package you are in, but if you convert your religion, you are entitled to both! Justice Ranganath Misra Commission, which the UPA appointed said so. We have not been able to implement it. Was it ever Dr. Ambedkar's thinking that such a perversion in the Constitution process be brought about that you will create a category which takes the advantage of Article 15(4) reservation and Article 30 reservation, and hence incentivize the conversion and change the demographic

character of India without going into the seriousness? My point is, we stand for a Constitution where there is no State religion, where there is no theocracy, where there is no discrimination. But, please seriously introspect the subversion in the ideological thinking, which has been brought about in the last 65 years, which has actually brought these changes. As far as the thinking is concerned, 65 years later, we have to stand up and say that we honour the spirit of what Dr. Ambedkar drafted. We must honour every aspect of it.

Sir, one of the dangers...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I just seek a clarification. Justice Ranganath Misra Commission was asked to look into the social discrimination of the Dalits even after getting converted into Christianity. In that context, the recommendation was to make reservation religion-neutral as they had gone into empirical evidence where certain atrocities were committed on the Dalit Christians not based on their Christianity, but based on their social status. This is my first point. Secondly, even our friends from the Ruling Benches say that the reservation should not be based on religion. That is fine. But, when you are a Hindu, you get reservation and when you are a Dalit of another religion, you don't get reservation. In that context, Justice Ranganath Misra Commission...

MR. CHAIRMAN: You sought a clarification, let him give it.

SHRI JESUDASU SEELAM: It is not correct to say that you give both advantages. No, you don't. You give only one advantage and that is the social and economic backwardness.

MR. CHAIRMAN: You have made your point; thank you. आपका क्या पॉइंट है?

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : सर, आर्टिकल 341 पर 1950 में जो कैप लगाया गया, मूल संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो जो बाद में सिख भाइयों को भी उस में जोड़ा गया और बाद में वी0पी0 सिंह जी की सरकार के समय Neo Buddhists को जोड़ा गया - क्या आप इसे गलत मानते हैं?

श्री सभापति : आप अपनी बात, आपकी बारी आने पर कहिएगा। Please continue.

श्री अरुण जेटली : सर, आज इस देश में और पूरे विश्व में सब से बड़ी चुनौती, जो किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को है, वह आतंकवाद है और यह आतंकवाद सीमा पार से लोग आकर फैलाएं या देश के भीतर से हो, हमें उस चुनौती का सामना करना है। कई बार, वोट की राजनीति के लिए किस की कितनी निंदा की जाए, हम इस पर संकोच करते हैं। यह इन्हीं 65 वर्षों का एक परिणाम है। जिन्होंने संसद पर attack किया, जिन्होंने मुंबई में attack किया और यह तो एक विडम्बना है कि हमारा संविधान दिवस भी 26/11 को पड़ता है और मुंबई attack भी 26/11 को हुआ था। जिन्होंने ट्रेन पर attack किया, in Mumbai, a serial blast took place when the accused was being punished;

[Shri Arun Jaitley]

and, the manner in which some segments passed in, somebody who virtually massacred Mumbai, claiming him to be a martyr, what were...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please sit down...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, what would *(Interruptions)*...

श्री सभापतिः दलवई साहब, आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : आपने जो कहा, मैं उसको कबूल करता हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं यह जानना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... यह क्या बात है ? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. *(Interruptions)*... Please sit down. *(Interruptions)*... When your turn comes, speak. बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... दलवई साहब, जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा। दलवई साहब, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)... इस डिबेट के लिए बहुत समय है। Please continue.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, how would Dr. Ambedkar have reacted to this? Sir, one of his most important speeches...*(Interruptions)*.... Sir, one of his most important speeches...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please. Order in the house. ...*(Interruptions)*....

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, one of the most important speeches of Dr. Ambedkar is the one he delivered on 25th November, 1949 while proposing the Constitution document. It was quoted yesterday in the other House that the success of the Constitution, ultimately, depends on the men who administer the Constitution. He had also in the same speech said कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं बनेगी और ईक्विटी और न्याय नहीं आएगा तब तक purpose serve नहीं होगा। But there was a third thing that he said in that speech also, and I don't know why people leave out that third thing. And this is in the context of the point I was making, that is para two of his speech and I quote it: "My mind is so full of the future of our country that I feel I ought to take this occasion to give expression to some of my reflections thereon. On 26th January 1950, India will be an independent country." He actually meant republican -- the Constitution. "What would happen to her independence? Will she maintain her independence or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost her independence she had. Will she lose it a second time? It is this thought which makes

12.00 NOON

me the most anxious for the future. What perturbs me greatly is the fact that not only India has lost her independence, but she lost it by the infidelity and the treachery of some of her own people. In the invasion of Sindh by Muhammad-Bin-Qasim, the military commanders of King Dahar accepted bribes from the agents of Muhammad-Bin-Qasim and refused to fight on the side of their King. It was Jaichand who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithvi Raj and promised him to help of himself and the Solanki Kings. When Shivaji was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha noblemen and the Rajput kings were fighting the battle on the side of the Mughal emperors. When the British were trying to destroy the Sikh rulers, Gulab Singh, their principal commander sat silent and did not help to save the Sikh kingdom and it goes down." What do these views indicate? When countries are challenged, the countries have to speak in one voice and, therefore, those who seek to destroy sovereignties, the countries cannot be seen to be ever supporting them, and this country's history ...*(Interruptions)*.....

श्री सभापति : आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए।....**(व्यवधान)**... . Please, he is not conceding. .... All right...*(Interruptions)*....

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): He has yielded.

MR. CHAIRMAN: Okay; all right.

SHRI ANAND SHARMA : He has yielded. I would like the Finance Minister to please elaborate and be specific as to what he means by 'those who want to destroy the sovereignty of India.' Please inform this House and be clear about it.

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*.... Thank you. ...*(Interruptions)*.... Dr. Mungekar, please sit down ...*(Interruptions)*.... Please sit down. ...*(Interruptions)*....

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR(Nominated): Since he is elaborately quoting Dr. Ambedkar because Dr. Ambedkar is the hero of 27th and 30th of November, so far as the debate is concerned, whatever he was talking about, the danger of losing the independence, and whatever paragraph now the hon. Finance Minister has quoted, what is the relevance of that quotation in the context of the point he was making? ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: All right. Thank you. ...*(Interruptions)*.... Arunji, please resume.

SHRI ARUN JAITLEY: I think I have no hesitation in saying this. I think I was absolutely clear. I was referring to acts of terrorism. I was referring to acts of terrorism... ...*(Interruptions)*....

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: It was internal terrorism. ...*(Interruptions)*.... All he has... ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Okay; you will have your chance. ...*(Interruptions)*.... Dr. Mungekar, please.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I was referring to acts of terrorism when I referred to the attack on Parliament, I referred to the attack in Mumbai on 26/11. ...*(Interruptions)*.... And I said we should all be in one voice in condemning them. And you and me being on the same side in that, I have absolutely nothing to say in this regard. I was absolutely clear. It is in that context that nobody in this country should ever be seen as soft on that kind of terrorism which led to that situation. Therefore, I supplemented it by saying... ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*....

SHRI ANAND SHARMA: When the attack on Parliament took place, you were in power, and the House spoke in one voice.

SHRI ARUN JAITLEY: Of course, you did. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please allow the speaker to conclude. ...*(Interruptions)*.... Sharma Saheb, please allow.

श्री अरुण जेटली : आप ऐसे एतराज कर रहे हैं जैसे मैं इस हाउस में किसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। **...(व्यवधान)...** मेरा यह इरादा नहीं है। **...(व्यवधान)...** मैं आतंकवादियों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : प्लीज़ आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, I thought this is one issue on which probably the Congress Party and we have normally been on the same side. Therefore, I am supplementing my point and...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Sit down, please.

SHRI ARUN JAITLEY: I am supplementing my point against terrorism and what is happening all over the world by quoting Dr. Ambedkar. Therefore, this is one aspect of his important Speech of 25th... ...*(Interruptions)*....

SHRI ANAND SHARMA: Dr. Ambedkar did not refer to terrorism. ...*(Interruptions)*....

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, that takes me to one of the final points I wish to make. When we say that there are dangers to the Constitutional order, there can be. And dangers to the Constitutional order can come when constitutional systems are used in order to subvert the Constitution. It is not unknown that this has happened. You don't have to bring a military dictatorship; you don't have to bring an individual dictatorship. There are illustrations in history, and I think the most glaring example of the last century is what happened in the Third Reich in Germany in 1933. A Constitution and its provisions were used to subvert democracy, and show to the world the worst kind of dictatorship.

SHRI SITARAM YECHURY: That is our fear. ...*(Interruptions)*.... Thank you for reminding us. That is our fear. ...*(Interruptions)*....

SHRI ARUN JAITLEY: Sitaramji, if you...

SHRI SITARAM YECHURY: I am sharing it.

SHRI ARUN JAITLEY: If you save your remarks for the next five minutes, you will find yourself in bad company.

SHRI SITARAM YECHURY: I thought you were good company. Why should I be in bad company? ...*(Interruptions)*....

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU(TELANGANA): Mr. Chairman, Sir,...

MR. CHAIRMAN: No; I am sorry. You speak when your turn comes. ...*(Interruptions)*....

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I have nothing to add. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: No, please. ...*(Interruptions)*....

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: We could sit in a classroom in which Shri Arun Jaitley and Shri Sitaram Yechury were there.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Arunji, please conclude.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I think, and this would be our final tribute to Dr. Ambedkar and the Constitution that he drafted, that we block all systems by which Constitution can be used and Constitutional provisions can be used to subvert democracy. And, I said that the worst illustration of this, in the last century, was in 1933 in Germany.

[Shri Arun Jaitley]

What happened in Germany was that you had a coalition Government. The Government did not have a majority. The Government said that there was an attempt to set fire to the Reichstag in German Parliament. And, they said that it was a Communists' conspiracy to set buildings on fire. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: No; no, please. ...*(Interruptions)*.... No interjections, please. ...*(Interruptions)*.... Please allow the speaker to continue.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, using that pretext of a fire -- there was a provision for imposition of Emergency – the Emergency was proclaimed. That was step one. Step two was that you needed a vast majority to amend the Constitution to give all powers to Fuhrer Hitler. But you did not have that majority. So, you detained all the Opposition Members. That was the second step. The third step you took was that you imposed censorship on newspapers. The fourth step you took was that you said that all that was in the interest of Germany. So, you announced the Twenty-Five Point Economic Programme. ...*(Interruptions)*.... I think, we need to be reminded of our history. So, you imposed Emergency; you detained the Opposition Members; you amended the Constitution; you imposed censorship on newspapers; you announced a Twenty-Five Point Economic Programme. ...*(Interruptions)*....

AN HON. MEMBER: Twenty Point.

SHRI ARUN JAITLEY: Twenty-Five Point in Germany. ...*(Interruptions)*.... And, thereafter, you brought a law to say that no action taken by the Government is justiciable in court. So, the Constitution was also amended. And, then, you had an important part of the third Reich, called, who was the immediate advisor to Adolf Hitler, his name was Rudolf Hess. He delivered a great speech on 25th of February, 1934. It was titled 'The Oath to Adolf Hitler'. The speech ended with a sentence, "Adolf Hitler is Germany and Germany is Adolf Hitler." ...*(Interruptions)*.... "He who takes oath to Hitler, takes an Oath to Germany." ...*(Interruptions)*.... Now, probably, you have the most glaring example in the world in third Reich – and, I must say that I am only referring to what happened in 1933 – that you had a democratic Constitution being used in order to subvert the Constitution. What happened subsequently in other parts of the world, the Germans never claimed the copyright on that. ...*(Interruptions)*.... But you have these illustrations. ...*(Interruptions)*.... And, therefore, my final point is, when we re-affirm our faith in the Constitution and in the great document that Dr. Ambedkar had prepared, we must all be prepared to strengthen each of the institutions that have been created. And, as far as the Government is concerned, the Government would be one with you in

reaffirming the spirit of 1950, 25th and 26th of November, 1949, by which he proposed this great document and strengthened every aspect of it, which I have referred to in my speech today. I thank you very much.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : माननीय चेयरमैन सर, इससे पहले कि मैं आज के विषय "Commitment to India's Constitution as part of the 125th Birth Anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar" पर बोलूं, आज जो डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयन्ती मनाई जा रही है, इस अवसर पर मैं उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ , अपने देश के लिए क़ुरबानियां दीं, चाहे उनमें लीडर्स हों, वर्कर्स हों, किसान हों, मज़दूर हों, लेखक हों, अलग-अलग तरह के पत्रकार हों या नौजवान हों, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सलाम करता हूं। अगर आज हम इस सदन में लोकतन्त्र की बात कर रहे हैं, तो यह तभी संभव हो पाया है, जब उन्होंने इस देश के लिए बड़ी क़ुरबानियां दीं।

माननीय लीडर ऑफ दि हाउस ने अभी यहां भाषण दिया। वे बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन मैं एक सोशल वर्कर हूं, वकील नहीं हूं। जब हमारी इस तरफ की पार्टी और दूसरी पार्टियों के वकील साहेबान बोलेंगे, तब शायद वे उनकी बहुत सारी बातों का उत्तर देंगे, लेकिन मैं उनके एक घंटे के भाषण से यह समझ गया कि आज आपको बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी की याद क्यों आ गई। बाबा साहेब को आगे रखकर, ढाल बनाकर, आपको बराबर निशाने चलाने थे। कांग्रेस के खिलाफ, एक मूवमेंट के खिलाफ, आजादी से लेकर आज तक या पिछले एक-डेढ़ साल से जो निशाने बाहर चल रहे थे, वे आज अन्दर चलाए गए। फर्क इतना है कि बाबा साहेब को आगे ढाल बनाकर रखा गया और उनके कंधे से तीर चलाने की कोशिश की। मैं सोचता था कि अचानक परिवर्तन कैसे आ गया या आज कमिटमेंट कैसे हो गई? मेरे ख्याल में हमारी पार्टी और यहां के अधिकतर लोगों को, जो आजादी का हिस्सा रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं, आज कॉंस्टिट्यूशन के प्रति कमिटमेंट लेने की दोबारा जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के साथ उनकी कमिटमेंट तो उसी दिन से हो गई थी, जब हमारे लीडर्स ने पूरी जिन्दगी जेलों में गुजारी और सब कुछ त्याग दिया। मैं यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, आगे जब वक्त आएगा, तब लूंगा, लेकिन वे अच्छी-भली जिन्दगी को छोड़कर, अच्छा रहन-सहन छोड़कर, आजादी के लिए आगे बढ़े और उन्होंने जेलों में जिन्दगियां गुज़ार दीं। उनको आज कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। उनको आज commitment की जरूरत नहीं है। Commitment की जरूरत उनको है, जो हिन्दुस्तान की आज़ादी का हिस्सा नहीं थे। उनको commitment की जरूरत है।

हम जो इस सदन में बैठे हैं और उस तरफ भी हमारे साथी बैठे हैं, हम विधान सभाओं का इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। जब हम उस ऑफिसर के सामने फॉर्म भरते हैं, जो कहीं सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट होता है और कहीं डिप्टी कमिशनर होता है, तो फार्म भरते-भरते हमें कांस्टीट्यूशन की, संविधान की ओथ भी दिलायी जाती है। जब हम जीत कर आते हैं, तब भी हम संविधान के प्रति commitment दिखाते हैं। जब मंत्री और प्रधान मंत्री बनते हैं, तब दोबारा ऐसा करना पड़ता है। हम में से कई लोगों ने 20-20 या 30-30 दफे nomination फॉर्म भरते हुए, इलेक्ट होते हुए,

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

मंत्री बनते हुए, मुख्य मंत्री बनते हुए या यूनियन मिनिस्टर बनते हुए संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखायी है, लेकिन अच्छा है कुछ लोगों की श्रद्धा नहीं थी, कुछ लोगों को विश्वास नहीं था और स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोगों ने एक परिवार के प्रति, जो उसके अलग-अलग अंग हैं, उन लीडर्स ने कांस्टीट्यूशन की निंदा की, कांस्टीट्यूशन को ठीक नहीं ठहराया और तिरंगे को नहीं माना। तो उनके लिए जरूरी है, स्वाभाविक है कि अगर वे आज आज़ादी के 66 साल बाद भी संविधान के प्रति commitment दिखाते हैं, तो सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौटे, तो उसे भूला नहीं कहते। मैं कहता हूँ- देर आये, दुरुस्त आये।

मेरे जैसा एक सोशल वर्कर डा. बाबा साहेब अम्बेडकर साहब से बहुत ही प्रभावित हुआ। जैसा लीडर ऑफ दि हाउस ने बोला कि किस तरह से उनके बचपन की जिन्दगी गुजरी, किस तरह से उनको छुआछूत का सामना करना पड़ा, एक स्कूल से दूसरे स्कूल और दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल और एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाना पड़ा, लेकिन छुआछूत उनका पीछा करती रही और किस तरह स्कूल के बच्चों से उनको अलग रखा गया, किस तरह उनको और उनके दूसरे साथियों को, जो उस कम्युनिटी से सम्बन्ध रखते थे, उनको पानी जग से दिया जाता था, ऊपर से फेंका जाता था और वह भी चपरासी देता था। जिस दिन चपरासी absent रहता था, उस दिन उनको बगैर पानी के प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि दूसरा कोई अपर कास्ट का आदमी उनको जग से पानी देने के लिए या ऊपर से फेंकने के लिए भी तैयार नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में बाबा साहेब अम्बेडकर पले, बढ़े और शिक्षा प्राप्त की। मैं यह कह सकता हूँ कि शायद विदेश में जितने भी हमारे लीडर्स पढ़े हैं, शायद वे सभी लीडर्स, चाहे वे किसी पोलिटिकल पार्टी के हों, उन सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आदमी वे थे। इतनी पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्रियाँ शायद किसी के पास नहीं हैं, जितनी पीएचडी की डिग्रियाँ उन्होंने हासिल कीं, चाहे वह London School of Economics हो या Colombia University हो या वकालत हो। तो मैं उनकी हिम्मत को, उनकी बहादुरी को, उनके जज्बे को दाद देता हूँ कि वे केवल एक अच्छे वकील ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे टीचर भी थे, प्रोफेसर भी थे और इकोनॉमिस्ट भी थे और अगर मैं कहूँ, तो शायद महात्मा गांधी जी के बाद सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। बहुत से सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने लाए हैं। उस वक्त जिस तरह का आंदोलन उन्होंने पब्लिक में जाकर किया। Untouchability को खत्म करने के लिए, हमारे तो सभी लीडर्स -गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद एक तरीके के सोशल रिफॉर्मर ही तो थे, क्योंकि जिस तरह से संविधान बना है, लेकिन फील्ड में जाकर उन्होंने जो एक मूवमेंट चलाई, 1927 में untouchability के खिलाफ जो शुरुआत की, अपनी लेबर पार्टी बनाई, उससे इलेक्शन लड़ा, कांस्टीट्चुंट असेंबली के मेंबर बन गए। मैं अपने आपको बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि वे राज्य सभा के नॉमिनेटेड मेंबर भी बने। जिस सदन के आज हम मेंबर हैं, इसमें , बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी महान हस्ती भी राज्य सभा की मेंबर रही। वह इसी राज्य सभा के मेम्बर रहे ।

सर, मैं समझता हूं कि कोई भी पहलू हो उनकी जिंदगी का और समाज का, हर पहलू पर उनका व्यू था। चाइल्ड मैरिज के बारे में उनकी ओपिनियन थी, polygamy के बारे में उनकी अपनी ओपिनियन थी। मुस्लिम महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव होता था, उसके बारे में वे बहुत चिंतित थे। जब वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उस वक्त के चेयरमैन और इस देश के पहले

राष्ट्रपति ने यह कहा कि शायद उनसे बेहतर कोई भी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हो नहीं सकता। पूरे विश्व ने उनकी सराहना की कि किस तरह से उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से Civil liberties और individual citizens की freedom को प्राथमिकता दी। वे आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। उनके हिन्दू कोड बिल के बारे में अपने विचार थे। सोशल डेवलपमेंट के बारे में, शिक्षा के बारे में, पब्लिक हाईजीन के बारे में, कम्युनिटी हैल्थ के बारे में उनके अपने विचार थे। मेरे ख्याल से वे बहुत farsighted थे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें पिछली सरकारें, आज की सरकारें जूझ रही हैं नए कानून बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए, लेकिन वे जब कांस्टीट्यूशन बना रहे थे, उस वक्त उसकी बात कर रहे थे। फ्री इकॉनोमी की आज हम बात कर रहे हैं, उन्होंने फ्री इकॉनोमी और stable rupee की बात तब की। आज कई सालों से हम फैमिली प्लानिंग से जूझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने नेशनल पॉलिसी फॉर फैमिली प्लानिंग के बारे में तब बात की थी। हम ईक्वल राइट्स, अपनी बहनों के, औरतों के बारे में आज चर्चा करते हैं। उन्होंने खाली ईक्वल राइट्स की नहीं बल्कि इकॉनोमिक डेवलपमेंट ऑफ वूमैन की भी तब बात की थी। वे देश के बल्कि मैं यह कहूंगा कि विश्व के एक बहुत बड़े इकॉनोमिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें, इकॉनोमी को लेकर दीं। यह देश बहुत सौभाग्यशाली देश है कि इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा लीडर पैदा किया। और वे हमारे Constitution के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और भारत के पहले कानून मंत्री बने। अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है, उसको कम करने के लिए उन्होंने हमें संविधान दिया। Constitution के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रह कर उन्होंने संविधान बनाया। इस तरह से लोकतंत्र की स्थापना करने में उनका बहुत हाथ रहा। आखिरकार 26 नवंबर, 1949 को Constitution एडॉप्ट हुआ, 24 जनवरी, 1950 को लॉ सेशन हुआ और 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ।

माननीय चेयरमैन साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि बाबा साहेब अम्बेडकर Constitution के निर्माता थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के अलावा भी उनके अपने व्यूज़ थे, एक अच्छे वकील के नाते और समाज में किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि वे जूझ चुके थे, वे झेल चुके थे, उस संबंध में उनके अपने व्यूज़ थे। लेकिन, कितनी खुशी होती अगर आज सरकार की तरफ से और माननीय लीडर ऑफ दि हाउस की तरफ से उन तमाम लीडरों को भी याद किया जाता, जिन्होंने हिन्दुस्तान के संविधान को बनाने में मदद की, हिस्सा लिया या बुनियाद रखी। उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं हुआ। उनकी चर्चा कहीं नहीं हुई। हमने जर्मनी की बात की, हिटलर की बात की, क्योंकि नजर कहीं थी, निशाना कहीं और था, लेकिन हमने पंडित जवाहर लाल नेहरू की बात नहीं की, क्योंकि पिछले 60 साल से कोशिश की जा रही है और डेढ़ साल से विशेष तौर पर कोशिश की जा रही है, निरंतर कोशिश की जा रही है, आज तक वह सदन से बाहर हो रही थी, आज सदन के अंदर हो रही है कि किस तरह से नेता सुभाष चन्द्र बोस को, सरदार पटेल को, जवाहर लाल नेहरू को लड़ाया जाए। वे आज जिन्दा नहीं हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनको लड़ाना चाहते हैं। किस तरह से इनके नाम पर अलग-अलग राजनीति, ओनरशिप ली जा रही है। अपना तो ओनरशिप लेने के लिए कोई लीडर था नहीं, इसलिए अब चोरी की ओनरशिप लेने की कोशिश की जा रही है। अपना तो कोई पैदा नहीं कर पाए, अब दूसरों से छीनने की बात की जा रही है कि कैसे छीना जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, नेता सुभाष चन्द्र बोस हों, पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, राजेन्द्र प्रसाद हों, मौलाना आजाद हों, उनको कोई छीन नहीं सकता है, चाहे कितना ही प्रयास किया जाए। वह संपत्ति जिसकी है, उसी की है। ...(**व्यवधान**)...

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

†قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : مائنیے چیئرمین سر، اس سے پہلے کہ میں آج کے وشئے "Commitment to India's Constitution as part of the 125th Birth Anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar" پر بولوں، آج جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی125 ویں جنم جینتی منائی جا رہی ہے، اس موقع پر میں ان تمام سوتنتر سنگرام سینانیوں کو، جنہوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک، جب تک بھارت آزاد نہیں ہوا، اپنے دیش کے لئے قربانیاں دیں، چاہے ان میں لیڈرس ہوں، ورکرس ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، لیکھک ہوں، الگ الگ طرح کے پترکار ہوں یا نوجوان ہوں، میں ان سبھی کو شردھانجلی ارپت کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ اگر آج اس سدن میں لوک تنتر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تبھی ممکن ہو پایا ہے، جب انہوں نے اس دیش کے لئے بڑی قربانیاں دیں۔

مائنیے لیڈر آف دی ہاؤس نے ابھی یہاں بھاشن دیا۔ وہ بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن میں ایک سوشل ورکر ہوں، وکیل نہیں ہوں۔ جب ہماری اس طرف کی پارٹی اور دوسری پارٹیوں کے وکیل صاحبان بولیں گے، تب شاید وہ ان کی بہت ساری باتوں کا جواب دیں گے، لیکن میں ان کے ایک گھنٹے کے بھاشن سے سمجھ گیا کہ آج آپ کو بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر جی کی یاد کیوں آگئی۔ بابا صاحب کو آگے رکھ کر، ڈھال بناکر، آپ کو برابر نشانے چلانے تھے۔ کانگریس کے خلاف، ایک موومینٹ کے خلاف، آزادی سے لے کر آج تک یا پچھلے ایک-ڈیڑھ سال سے جو نشانے باہر چل رہے تھے، وہ آج اندر چلائے گئے۔ فرق اتنا ہے کہ بابا صاحب کو آگے ڈھال بناکر رکھا گیا اور ان کے کندھے سے تیر چلانے کی کوشش کی۔ میں سوچتا تھا کہ اچانک بدلاؤ کیسے آگیا آج کمٹمینٹ کیسے ہو گئی؟ میرے خیال میں ہماری پارٹی اور یہاں کے زیادہ تر لوگوں کو، جو آزادی کا حصہ رہے ہیں، فریڈم اسٹرگل کا حصہ رہے ہیں، آج کانسٹی ٹیوشن کے تئیں کمٹمینٹ لینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ بھارت کے آئین کے ساتھ ان کی کمٹمینٹ تو اسی دن سے ہو گئی تھی، جب ہمارے لیڈرس نے پوری زندگی جیلوں میں گزاری اور سب کچھ تیاگ دیا۔ میں یہاں پر کسی خاص آدمی کا نام نہیں لوں گا، آگے جب وقت آئے گا، تب لونگا، لیکن وہ اچھی بھلی زندگی کو چھوڑ کر، اچھا رہن سہن چھوڑ کر، آزادی کے لئے آگے بڑھے اور انہوں نے جیلوں میں زندگیاں گزار دیں۔ ان کو آج کمٹمینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔

کمٹمینٹ کی ضرورت ان کو ہے، جو ہندوستان کی آزادی کا حصہ نہیں تھے۔ ان کو کمٹمینٹ کی ضرورت ہے۔

ہم جو اس سدن میں بیٹھے ہیں اور اس طرف بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم ودھان سبھاؤں کا الیکشن لڑتے ہیں، پارلیمنٹ کا الیکشن لڑتے ہیں۔ جب ہم اس افیسر کے سامنے فارم بھرتے ہیں، جو کہیں سب-ڈویژنل مجسٹریٹ ہوتا ہے اور کہیں ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، تو فارم بھرتے بھرتے ہمیں کانسٹی ٹیوشن کی، سنودھان کی اوتھ بھی دلائی جاتی ہے۔ جب ہم جیت کر آتے ہیں، تب بھی ہم سنودھان کے تئیں کمٹمینٹ درشاتے ہیں۔ جب منتری اور پردھان منتری بنتے ہیں، تب دوبارہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم میں سے کئی لوگوں نے 20-20 یا 30-30 دفعہ nominationفارم بھرے ہیں، الیکٹ ہوتے ہوئے، منتری بنتے ہوئے، مکھیہ منتری بنتے ہوئے یا یونین منسٹر بنتے ہوئے سنودھان کے تئیں اپنی شردھا دکھائی ہے لیکن اچھا ہے کچھ لوگوں کی شردھا نہیں تھی، کچھ لوگوں کو وشواس نہیں تھا اور سوابھاوک ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک پریوار کے تئیں، جو اس کے الگ الگ انگ ہیں، ان لیڈرس نے کانسٹی ٹیوشن کی نندا کی، کانسٹی ٹیوشن کو ٹھیک نہیں ٹھہرایا اور ترنگے کو نہیں مانا۔ تو ان کے لئے ضروری ہے، کہ اگر وہ آج آزادی کے 66 سال بعد بھی سنودھان کے تئیں کمٹمینٹ دکھاتے ہیں، تو صبح کا بھولا اگرشام کو گھر واپس لوٹے، تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں کہتا ہوں دیر آئے، درست آئے۔

میرے جیسا ایک سوشل ورکر ڈاکٹر بابا امبیڈکر صاحب سے بہت ہی پربھاوت ہوا۔ جیسا لیڈر آف دی ہاؤس نے بولا کہ کس طرح سے ان کے بچپن کی زندگی گزری، کس طرح سے ان کو چھوا چھوت کا سامنا کرنا پڑا، ایک اسکول سے دوسرے اسکول سے تیسرے اسکول اور ایک پرانت سے دوسرے پرانت جانا پڑا، لیکن چھوا چھوت ان کا

پوچھا کرتی رہی اور کس طرح اسکول کے بچوں سے ان کو الگ رکھا گیا، کس طرح ان کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو، جو اس کمیونٹی سے سمبندھ رکھتے تھے، ان کو پانی جگ سے دیا جاتا تھا، اوپر سے پھینکا جاتا تھا اور وہ بھی چپراسی دیتا تھا۔ جس دن چپراسی غیر حاضر رہتا تھا، اس دن ان کو بغیر پانی کے پیاسا رہنا پڑتا تھا، کیوں کہ دوسرا کوئی اپر-کاسٹ کا آدمی ان کو جگ سے پانی دینے کے لئے یا اوپر سے پھینکنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی حالت میں، ایسے ماحول میں بابا صاحب امبیڈکر پلے، بڑھے اور تعلیم حاصل کی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ودیش میں جتنے بھی ہمارے لیڈرس پڑھے ہیں، شاید وہ سبھی لیڈرس، چاہے وہ کسی پالیٹکل پارٹی کے ہوں، ان سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی وہ تھے۔ اتنی پی۔ایچ۔ڈی۔ کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں شاید کسی کے پاس نہیں ہیں، جتنی پی۔ایچ۔ڈی۔ کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کیں، چاہے وہ' لندن اسکول آف اکانومکس 'ہو یا' کولمبیا یونیورسٹی 'ہو یا وکالت ہو۔ تو میں ان کی ہمت کو، ان کی بہادری کو، ان کے جذبے کو داد دیتا ہوں کہ وہ صرف ایک اچھے وکیل ہی نہیں تھے، بلکہ ایک اچھے ٹیچر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے اور اکانومسٹ بھی تھے اور اگر میں کہوں، تو شاید مہاتما گاندھی جی کے بعد ایک سب سے بڑے سوشل ریفارمر بھی تھے۔

انہوں نے بہت سے سوشل ریفارمس لائے۔ اس وقت، جس طرح کا آندولن انہوں نے پبلک میں جا کر کیا۔ 'چھوا چھوت 'کو ختم کرنے کے لئے، ہمارے تو سبھی لیڈرس گاندھی، نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد ایک طریقے کے سوشل ریفارمر ہی تو تھے، کیوں کہ جس طرح سے سنودھان بنا ہے، لیکن فیلڈ میں جاکر انہوں نے جو ایک موومینٹ چلائی، 1927 میں چھوا چھوت کے خلاف جو شروعات کی، اپنی لیبر پارٹی بنائی، اس سے الیکشن لڑا۔ کانسٹی ٹیوشن اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ راجیہ سبھا کے نامینیٹڈ ممبر بھی بنے۔ جس سدن کے آج ہم ممبر ہیں، اس میں اتنی مہان شکتی، بابا صاحب امبیڈکر جیسی شکتی بھی راجیہ سبھا کی ممبر رہی۔

سر، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پہلو ہو ان کی زندگی کا اور سماج کا، ہر پہلو پر ان کا' نظریہ 'تھا۔ چائلڈ میریج کے بارے میں ان کی اوپینئن تھی، polygamy کے بارے میں ان کی اپنی اوپینئن تھی، مسلم مہیلاؤں کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ ہوتا تھا، اس کے بارے میں وہ بہت چنتت تھے۔ جب وہ ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے، اس وقت کے چیئرمین اور اس دیش کے پہلے راشٹرپتی نے یہ کہا کہ شاید ان سے بہتر کوئی بھی ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین ہو نہیں سکتا۔ پوری دنیا نے ان کی سراہنا کی، کہ کس طرح سے انہوں نے ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے Civil liberties اور individual citizens کی freedom کو پراتھمکتا دی۔ وہ آرٹیکل 370 کے خلاف تھے۔ ان کے ہندو کوڈ بل کے بارے میں اپنے وچار تھے۔ سوشل ڈیولپمینٹ کے بارے میں شکشا کے بارے میں، پبلک ہائی-جین کے بارے میں، کمیونٹی ہیلتھ کے بارے میں اپنے وچار تھے، میرے خیال سے بہت farsightedتھے بہت سارے ایسے وشئے ہیں، جن میں پچھلی سرکاریں، آج کی سرکاریں جوجھ رہی ہیں نئے قانون بنانے کے لئے، ان کو لاگو کرنے کے لئے، لیکن وہ جب کانسٹی ٹیوشن بنا رہے تھے، اس وقت اس کی بات کر رہے تھے۔ فری اکانومی کی آج ہم بات کر رہے ہیں، انہوں فری اکانومی اور stable rupee کی بات تک کی۔ آج کئی سالوں سے ہم فیملی پلاننگ سے جوجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے نیشنل پالیسی فار فیملی پلاننگ کے بارے میں تب بات کی تھی۔ ہم ایکول رائٹس، اپنی بہنوں کے، وومین کے بارے میں آج چرچا کرتے ہیں۔ انہوں نے خالی ایکول رائٹس کی نہیں بلکہ اکانومک ڈیولپمینٹ آف وومین کی بھی تب بات کی تھی۔ وہ دیش کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے ایک بہت بڑے اکانومسٹ تھے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں، اکانومی کو لے کر دیں۔ یہ دیش بہت سوبھاگیہ شالی دیش ہے کہ اس دیش نے بابا صاحب امبیڈکر جیسا لیڈر پیدا کیا۔

اور وہ ہمارے کانسٹی ٹیوشن کے ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین بنے اور بھارت کے پہلے قانون منتری بنے۔ امیر اور غریب کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، اس کو کم کرنے کے لئے انہوں نے ہمیں سنودھان دیا۔ کانسٹی ٹیوشن کے ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین رہ کر انہوں نے سنودھان بنایا۔ اس طرح سے لوک-تنتر کی استھاپنا کرنے میں ان کا بہت ہاتھ رہا۔ آخر کار 26 نومبر، 1949 کو کانسٹی ٹیوشن اڈوپٹ ہوا، 24 جنوری، 1950 کو لاء سیشن ہوا اور 26 جنوری، 1950 سے سنودھان لاگو ہوا۔

اس صاحب، چیئرمین مانئے

علاوہ کے چیئرمین کے کمیٹی ڈرافٹنگ تھے، نرماتا کے ٹیوشن کانسٹی امبیڈکر صاحب بابا کہ نہیں شک کوئی میں بات

وہ کہ کیوں چاہئے، ہونا بدلاؤ کا طرح کس میں سماج اور ناطے کے وکیل اچھے ایک تھے، ویوز اپنے کے ان بھی آج اگر ہوتی خوشی کتنی لیکن، تھے۔ ویوز اپنے کے ان میں سمبندھ اس تھے، چکے جھیل وہ تھے، چکے جوجھ نے جنہوں جاتا، کیا یاد بھی کو لیڈروں تمام ان سے طرف کی ہاؤس دی آف لیڈر مانئے اور سے طرف کی سرکار چرچا کی ان ہوا۔ نہیں ذکر کہیں کا نام کے ان رکھی، بنیاد یا لیا حصہ کی، مدد میں بنانے کو سنودھان کے ہندوستان نے ہم لیکن تھا، کہیں اور نشانہ تھی، کہیں نظر کہ کیوں کی، بات کی ہٹلر کی، بات کی جرمنی نے ہم ہوئی۔ نہیں کہیں خاص سے سال ڈیڑھ اور ہے رہی جا کی کوشش سے سال 60 پچھلے کیونکہ کی۔ نہیں بات کی نہرو لال جواہر پنڈت سدنکے اندر آج تھی، رہی ہو باہر سے سدن وہ تک آج ہے، رہی جا کی کوشش لگاتار ہے، رہی جا کی کوشش پر طور ہو رہی ہے کہ کس طرح سے نیتا سبھاش چندر بوس کو، سردار پٹیل کو، جواہر لال نہرو کو لڑایا جائے۔ وہ آج زندہ نہیں ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی ان کو لڑانا چاہتے ہیں۔ کس طرح سے ان کے نام پر الگ الگ راجنیتی، آنرشپ لی جا رہی ہے۔ اپنی تو آنرشپ لینے کے لئے کوئی لیڈر تھا نہیں، اس لئے اب چوری کی آنرشپ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا تو کوئی پیدا نہیں کر پائے، اب دوسروں سے چھیننے کی بات کی جا رہی ہے کہ کیسے چھینا جائے۔ بابا صاحب امبیڈکر ہوں، سردار پٹیل ہوں، نیتا سبھاش چندر بوس ہوں، پنڈت جواہر لال نہرو ہوں، راجندر پرساد ہوں، مولانا آزاد ہوں، ان کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، چاہے کتنا ہی پریاس کیا جائے۔ وہ سمپتی جس کی ہے، اسی کی ہے--(مداخلت)...

कुछ माननीय सदस्यः वह देश की संपत्ति है। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ादः वह देश की संपत्ति है। ...(**व्यवधान**)... काश, अगर आप यह कहते कि वह देश की संपत्ति है, तो झगड़ा ही खत्म हो जाता। ...(**व्यवधान**)... यही तो मुसीबत है कि 'डिवाइड एण्ड रूल', जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उसी पर आज आप चल रहे हैं। आप उस policy पर चल रहे हैं। आप 'Divide and Rule' की policy पर चल रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? जब वे चेयरमैन बने ...(**व्यवधान**)... हमने बहुत चुप होकर आपको सुना। आप तीर चलाते गए और हम सहते गए। हम तो तीर नहीं चलाते।

महोदय, कांस्टीट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वह 9 दिसम्बर, 1946 से शुरू हुई। किस तरह का कांस्टीट्यूशन होना चाहिए, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसकी नींव कैसी होनी चाहिए, बुनियाद कैसी होनी चाहिए और क्या उसकी रेत की बुनियाद होनी चाहिए, क्या उसकी कच्ची मिट्टी की बुनियाद होनी चाहिए या फौलादी सीमेंट और पत्थर की बनी बुनियाद होनी चाहिए, जिस पर हम कांस्टीट्यूशन की बड़ी इमारत खड़ी करें और जिस पर हिन्दुस्तान और विश्व की एक बड़ी डैमोक्रेसी खड़ी हो सके।

जब कांस्टीट्यूशन बना और जिसकी बुनियाद खड़ी करने के लिए यह तय किया गया कि objective क्या होगा, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम ने एक घंटे तक माननीय लीडर ऑफ दि हाउस को सुना और जब वे भारत के संविधान की बात करते हैं, तो उस resolution की बात नहीं करते, जो 13 दिसम्बर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने objectives के बारे में resolution रखा था कि हमारा कांस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ड्राफ्ट तो बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, बुनियाद कैसी होनी चाहिए and, I would like, Mr. Chairman, to read the Resolution of 13th December, 1946, moved by no less than Pandit Jawaharlal Nehru, "The objectives of the Indian Constitution should be:

1. To propagate the ideals and values of the Indian Constitution.
2. To facilitate the practice of the ideals and values of the Indian Constitution in all spheres of life, both public and private, including that of individuals.
3. To further the objectives and goals of the constitutionalism, unity in diversity, social justice and substantive equality.
4. To introduce and implement Constitutional Governance according to the ideals and principles of the Indian Constitution both in public and private sector, including all realms of personal, social, economic and public life.
5. To uphold and live by the values of Secularism -- I repeat, to uphold and live by the values of Secularism -- Democracy, Socialism, Republicanism and Responsible Independence, by which people would secure to themselves and others: Justice - social, economic and political; liberty of thought, expression,

belief, faith and worship; equality of status and opportunity, and would promote among all fraternity assuring the dignity of the individual, and unity and integrity of the nations, groups and societies.

6. To endeavour that the human rights declared by the Indian Constitution as Fundamental Rights shall be respected and enforced even in the non-governmental and non-state institutions and spheres, including individuals, families, groups and corporate bodies."

माननीय सभापति जी, पं. जवाहर लाल नेहरू ने objective resolution move कर के संविधान की रुपरेखा के बारे में नक्शा खींचा। और यह अब आप पढ़िए। जो हमारा Preamble बना, उस Preamble में सिर्फ पहला पैरा छोड़कर, वही है, सिर्फ इतना ही फर्क है। हमारे कॉंस्टीट्यूशन का Preamble बना -- We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens: (i) Justice, social, economic and political – it is from Pt. Jawaharlal Nehru's Objectives of Indian Constitution; (ii) Liberty of thought, expression, belief, faith and worship – it is from Pt. Jawaharlal Nehru's Objectives of Indian Constitution; (iii) Equality of status and opportunity to all – it is from Pt. Nehru's Objectives of Indian Constitution; (iv) Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation – it is from Pt. Nehru's Objectives of Indian Constitution. तो कॉंस्टीट्यूशन में जो आपका Preamble बना, उस Preamble की जो शुरुआत होती है - हिन्दी में आप श्रीगणेश कहते हैं और हमारे यहां बिसमिल्लाह कहते हैं - जहां से आप शुरुआत करते हैं, वह पंडित नेहरू के ऑब्जेक्टिव्ज़ resolution से शुरू हो रहा है और आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते हैं! यह कैसे हो सकता है कि हिन्दुस्तान के संविधान पर भारत की पार्लियामेंट में चर्चा हो, उसमें ऑब्जेक्टिव्ज़ resolution की बात न हो और पंडित नेहरू की बात न हो? सर, इसी को intolerance कहते हैं, इसी को ...(**व्यवधान**)...

The intolerance flows from the top and this intolerance is percolating down to the streets. The intolerance is that we are not able to recognize the contribution of the first Prime Minister of India as a freedom fighter on the occasion when the Constitution of India is being debated and discussed in the Indian Parliament. His 125th birth anniversary has just been celebrated about 14 days ago, and, we do not mention anything about him and his contribution. Sir, this is intolerance. *...(Interruptions)....* This is intolerance. *...(Interruptions)....*

सभापति महोदय, माननीय लीडर ऑफ दि हाउस ने बताया कि जब चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी की आखिरी स्पीच हो रही थी तो उन्होंने बता दिया था कि from 26th January, 1950, India will be an independent country, and, from 26th January, 1950, India would be a democratic country in the sense that India from that day would have a Government of the People, by the People and for the People, इसका मतलब है कि उन्होंने तय कर दिया था कि 26 जनवरी

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

को गणतंत्र दिवस होगा और उस दिन से कॉंस्टीट्यूशन लागू होगा, उस दिन से 'of the people, by the people, for the people' गवर्नमेंट होगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, बाबा साहेब अम्बेडकर बोल रहे हैं। सर, माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं यह 26 नवम्बर की जो नयी डेट आयी है, यह कहां से आ गयी? 26 नवम्बर को आने वाले वक्त में हर साल छुट्टी होगी और हर साल इसे मनाया जाएगा? यह न तो "Independence Day" है और न ही यह "Republic Day" है। 15 अगस्त, 1947 का दिन "Independence Day" के रूप में तय हुआ है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनको हम आज का Constitution नज़र कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि 26 जनवरी "गणतंत्र दिवस" होगा और उस दिन से Constitution लागू होगा। ...(**व्यवधान**)... आप अपने जवाब में बता दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

جناب غلام نبی آزاد : وہ دیش کی سمپتّی ہے ...(مداخلت)... کاش، اگر آپ یہ کہتے کہ وہ دیش کی سمپتّی ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ...(مداخلت)... یہی تو مصیبت ہے کہ 'ٹیوائڈ اینڈ رول'، جو انگریزوں کی پالیسی تھی، اسی پر آج آپ چل رہے ہیں۔

آپ اس پالیسی پر چل رہے ہیں۔ آپ 'ٹیوائڈ اینڈ رول' کی پالیسی پر چل رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ چیئرمین بنے ...(مداخلت)... ہم نے بہت چپ ہوکر آپ کو سنا۔ آپ تیر چلاتے گئے اور ہم سہتے گئے۔ ہم تو تیر نہیں چلاتے۔

مہودے، کانسٹی ٹیوشن بنانے کی جو پرکریا شروع ہوئی، وہ 9 دسمبر، 1946 سے شروع ہوئی۔ کس طرح کا کانسٹی ٹیوشن ہونا چاہئے، اس کی پری بھاشا کیا ہونی چاہئے، اس کی نیو کیسی ہونی چاہئے، بنیاد کیسی ہونی چاہئے، اور کیا اس کی ریت کی بنیاد ہونی چاہئے، کیا اس کی کچی مٹّی کی بنیاد ہونی چاہئے یا فولادی سمینٹ اور پتھر کی بنی بنیاد ہونی چاہئے، جس پر ہم کانسٹی ٹیوشن کی بڑی عمارت کھڑی کریں اور جس پر ہندوستان اور دنیا کی ایک بڑی ڈیموکریسی کھڑی ہو سکے۔

جب کانسٹی ٹیوشن بنا اور جس کی بنیاد کھڑی کرنے کے لئے وہ طے کیا گیا کہ آبجیکٹیو کیا ہوگا، تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک گھنٹے تک ماتنے لیٹراف دی ہاؤس کو سنا اور جب وہ بھارت کے سنودھان کی بات کرتے ہیں، تو اس ریزولیوشن کی بات نہیں کرتے، جو 13 دسمبر، 1946 کو پنڈت جواہر لال نہرو نے آبجیکٹیو کے بارے میں ریزولیوشن رکھا تھا کہ ہمارا کانسٹی ٹیوشن کیسا ہونا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرافٹ تو بنائیں گے، لیکن اس میں کیا ہونا چاہئے، بنیاد کیسی ہونی چاہئے

and, I would like, Mr. Chairman, to read the Resolution of 13th December, 1946, moved by no less than Pandit Jawaharlal Nehru, "The objective of the Indian Constitution should be:

1. To propagate the ideals and values of the Indian Constitution.
2. To facilitate the practice of the ideals and values of the Indian Constitution in all spheres of life, both public and private, including that of individuals.
3. To further the objectives and goals of the constitutionalism, unity in diversity, social justice and substantive equality.
4. To introduce and implement Constitutional Governance according to the ideals and principles of the Indian Constitution both in public and private sector, including all realms of personal, social, economic and public life.

5. To uphold and live by the values of Secularism – I repeat, to uphold and live by the values of Secularism – Democracy, Socialism, Republicanism and Responsible Independence, by which people would secure to themselves and others: Justice - social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and opportunity, and would promote among all fraternity assuring the dignity of the individual, and unity and integrity of the nations, groups and societies.

6. To endeavour that the human rights declared by the Indian Constitution as Fundamental Rights shall be respected and enforced even in the non-Governmental and non-State institutions and spheres, including individuals, families, groups and corporate bodies."

٭ماننیے سبھا پتی جی، پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ آبجیکٹو تھا جب انہوں نے آبجیکٹیو موو کئے کہ کس طرح کا ہمارے دیش کا سنودھان ہونا چاہئے۔

اور یہ اب آپ پڑھئیے۔ جو ہمارا 'پریمبل' بنا، اس 'پریمبل' میں صرف پہلا پیرا چھوڑ کر، وہی ہے، صرف اتنا ہی فرق ہے۔ ہمارے کانسٹی ٹیوشن کا 'پریمبل' بنا۔

We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens: (i) Justice, social, economic and political – it is from Pt. Jawaharlal Nehru's Objectives of Indian Constitution; ii) Liberty of thought, expression, belief, faith and worship – it is from Pt. Jawaharlal Nehru's Objectives of Indian Constitution; iii) Equality of status and opportunity to all – it is from Pt. Nehru's Objectives of Indian Constitution; iv) Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation – it is from Pt. Nehru's Objectives of Indian Constitution.

تو کانسٹی ٹیوشن میں جو آپ کا 'پریمبل' بنا، اس 'پریمبل' کی جو شروعات ہوتی ہے، ہندی میں آپ شری گنیش کہتے ہیں اور ہمارے یہاں بسم اللہ کہتے ہیں۔ جہاں سے آپ شروعات کرتے ہیں، وہ پنڈت نہرو کے ابجیکٹو سے شروع ہو رہا

ہے اور آپ پنڈت نہرو کا نام نہیں لیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے آئین پر بھارت کی پارلیمنٹ میں چرچا ہو، اس میں آبجیکٹو کی بات نہ ہو اور پنڈت نہرو کی بات نہ ہو؟ سر، اسی کو intolerance کہتے ہیں، اسی کو۔۔مداخلت۔۔۔

The intolerance flows from the top and this intolerance is percolating down to the streets. The intolerance is that we are not able to recognize the contribution of the first Prime Minister of India as a freedom fighter on the occasion when the Constitution of India is being debated and discussed in the Indian Parliament. His 125th birth anniversary has just been celebrated about 14 days ago, and, we do not mention anything about him and his contribution. Sir, this is intolerance. ...*(Interruptions)*.... This is intolerance. ...*(Interruptions)*....

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

سبھا پتی مہودے، مائنے لیٹر آف باؤس نے بتایا کہ جب چیئرمین، ڈرافٹنگ کمیٹی کی آخری اسپیچ تو انہوں نے بتا دیا

from 26th January, 1950, India will be an independent country, and, from 26th January, 1950, India would be a democratic country in the sense that India from that day would have a Government of the People, by the People and for the People,

اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے طے کر دیا تھا کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ ہوگا اور اس دن سے کانسٹی ٹیوشن لاگو ہوگا، اس دن سے 'of the people, by the people, for the people' گورنمینٹ ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین، بابا صاحب امبیڈکر بول رہے ہیں۔ سر، مائنے پردھان منتری جی یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آج ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ 26 نومبر کی جو نئی ڈیٹ آئی ہے، یہ کہاں سے آگئی؟ 26 نومبر کو آنے والے وقت میں ہر سال چھٹی ہوگی اور ہر سال اسے منایا جائے گا؟

یہ نہ تو "Independence Day" ہے اور نہ ہی "Republic Day" ہے۔ 15اگست 1947 کا دن "Independence Day" کے روپ میں طے ہوا ہے۔ ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین، جن کو ہم آج کا کانسٹی ٹیوشن نذر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ 26جنوری یوم جمہوریہ ہوگا اور اس دن سے کانسٹی ٹیوشن لاگو ہوگا۔ ...(مداخلت)... آپ اپنے جواب میں بتادیجیئے گا۔ ...(مداخلت)...

MR. CHAIRMAN: All right. ...*(Interruptions)*... One minute, one minute. ...*(Interruptions)*... Please, one minute. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Sit down, please. ...*(Interruptions)*...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि माननीय लीडर ऑफ दि अपोजिशन ने कहा कि 26 नवम्बर को छुट्टी होगी, यह सरकार ने कहां फैसला किया है? ...(**व्यवधान**)... ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा किसने कह दिया? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: बाबा साहेब के जन्म दिन पर छुट्टी होती है। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام نبی آزاد**: بابا صاحب کے جنم دن پر چھٹی ہوتی ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

MR. CHAIRMAN: Silence please. ....*(Interruptions)*...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि "गणतंत्र दिवस" 26 जनवरी को होगा। यह है कि नहीं, यह उनकी स्पीच में है कि नहीं? हम 66 साल से मना रहे हैं कि नहीं? ...(**व्यवधान**)... आज यह बताया है कि इस दिन "कांस्टींट्युशन डे" होगा, "संविधान दिवस" होगा। मैं यह पूछता हूं कि यह कहां से आया, नम्बर वन ? यह "संविधान दिवस" का

†Transliteration in Urdu Script.

विचार कहां से आया? यह कहां पर आप फिट करेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताया है कि 26 जनवरी को हमारा "गणतंत्र दिवस" होगा, वह कहां चला गया? मैं समझता हूं कि यह सरकार हिस्टरी को रि-राइट करना चाहती है। हमें यह मालूम है, यह कोई नई बात नहीं है। 26 नवम्बर, 1949 को जब कांस्टीट्युशन पारित हुआ, तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366 ...(**व्यवधान**)...

جناب غلام نبی آزاد: میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ یوم جمہوریہ 26 جنوری کو ہوگا۔ یہ ہے کہ نہیں، یہ ان کی تقریر میں ہے کہ نہیں؟ ہم 66 سال سے منا رہے ہیں کہ نہیں؟ ...(مداخلت)... آج یہ بتایا ہے کہ اس دن کانسٹی ٹیوشن ڈے ہوگا، سمودھان دیوس ہوگا۔ میں یہ پوچھنا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا، نمبر ون؟ یہ سمودھان دیوس کا وچار کہاں سے آیا؟ یہ کہاں پر آپ فٹ کریں گے؟ بابا صاحب امبیڈکر جی نے بتایا ہے کہ 26 جنوری کو ہمارا یوم جمہوریہ ہوگا، وہ کہاں چلا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار ہسٹری کو ری۔رائیٹ کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 26 نومبر 1949 کو جب کانسٹی ٹیوشن پاس ہوا، تو آرٹیکل 5,6,7,8,9,60,324,366 ...(مداخلت)...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : सर, मैं बताना चाहता हूं कि 26 नवम्बर को "लॉ डे" होता है। ...(**व्यवधान**)... इसको सुप्रीम कोर्ट भी मनाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ादः और आर्टिकल 379 ये उसी दिन से, 26 नवम्बर, 1949 से लागू हुए और जो remaining 395 आर्टिकल से ये 9, 10, 11 निकालिए, बाकी 383, 384 आर्टिकल्स हैं, यह उस दिन अनाउंस किया गया कि ये 26 जनवरी, 1950 से लागू होंगे, तो आपका कांस्टीट्युशन 26 जनवरी, 1950 से लागू हो गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या "गणतंत्र दिवस" 26 जनवरी से हटाकर 26 नवम्बर को लाने की कोई बात है ? ...(**व्यवधान**)... इसका स्टेटस क्या होगा, यह मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो इससे जुड़ा हुआ है, वह यह है माननीय प्रधान मंत्री जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके मुम्बई के भाषण से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे लीडर ऑफ दि हाउस और एक वकील के नाते भी लीडर ऑफ दि हाउस, अच्छी तरह जानते हैं कि Allocation of Business Rules में national festivals या Constitution के संबंध में लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ही बात करती है, फिर यह Ministry of Social Justice कहां से आ गयी? इस बारे में मेरे पास Ministry of Social Justice and Empowerment का नोटिफिकेशन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस Social Justice Ministry को किसने empower किया? यह कांस्टीट्यूशन में क्लिअर है कि वह इसे नहीं कर सकती। अगर इसे करना है तो होम मिनिस्ट्री को करना है। तो Social Justice Ministry यह क्यों कर रही है? उसे किस ने पॉवर दी कि वह नोटिफिकेशन जारी करे? Therefore, this is a null and void *ab initio*. Social Justice Minister has no powers whatsoever in the Constitution under the Allocation of Rules of Business. He is nobody; he or she. माननीय प्रधान मंत्री जी, आप यह नोटिफिकेशन देखिए जो 19 नवम्बर, 2015 को इश्यू होती है। अब दूसरी विडम्बना देखिए, जिस में शिक्षा मंत्रालय, 10 नवम्बर यानी 9 दिन पहले एक दूसरा मंत्रालय देश की तमाम Central Institutions के लिए Celebration of the Constitution Day, 2015 के बारे में ऑर्डर निकालता है।

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

माननीय प्रधान मंत्री जी, यह क्या हो रहा है? Ministry of Education 10 नवम्बर को ऑर्डर निकालती है कि तमाम educational institutios इसे celebrate करें और उसके 9 दिन बाद Social Justice Ministry notification निकालती है। तो इस नए Constitution के बारे में भी चर्चा की जाए या इस तरह का कोई amendment लाया जा रहा है, तो वह भी हमें बताया जाए कि नोटिफिकेशन जिस मिनिस्ट्री को निकालना चाहिए, उस के बजाय दूसरी मिनिस्ट्री क्यों निकालती है? इस नोटिफिकेशन से पहले तीसरी मिनिस्ट्री celebration के लिए और Government holiday के लिए नोटिफिकेशन निकालती है। माननीय प्रधान मंत्री जी, यह हमें समझने की जरूरत है। अगर आपके पास यह नोटिफिकेशन नहीं है, तो मैं वह दिखा सकता हूं। ...(**व्यवधान**)...

جناب غلام نبی آزاد: اور آرٹیکل 379 یہ اسی دن سے، 26 نومبر 1949سے لاگو ہونے اور جو آرٹیکل سے یہ 9,10,11 نکالئیے، باقی 383, 384 آرٹیکل ہیں، یہ اس دن اعلان کیا گیا کہ یہ 26 جنوری 1950 سے لاگو ہونگے، تو آپ کا کانسٹی ٹیوشن 26 جنوری 1950 سے لاگو ہوگیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یوم جمہوریہ 26 جنوری سے ہٹاکر 26 نومبر کولانے کی کوئی بات ہے؟ ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال جو اس سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے مانئیے پردھان منتری، کیوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ممبئی کے بھاشن سے اس کی شروعات ہوئی ہے.

ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس اور ایک وکیل کے ناطے بھی لیڈر آف دی ہاؤس اچھی طرح جانتے ہیں کہ Allocation of Business Rules national festivals یا Constitution کے سمبندھ میں لا منسٹری، ہوم منسٹری ہی بات کرتی ہے، پھر یہ Ministry of Social Justice کہاں سے آگئی؟ اس بارے میں میرے پاس Ministry of Social Justice and Empowerment نوٹیفکیشن ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس Social Justice Ministry کو کس نے Empower کیا؟ یہ کانسٹی ٹیوشن میں کلئیر ہے کہ وہ اسے نہیں کرسکتی. اگر اسے کرنا ہے تو ہوم منسٹری کو کرنا ہے. تو Social Justice Ministry یہ کیوں کررہی ہے؟ اسے کس نے پاور دی کہ وہ نوٹیفکیشن جاری کرے؟ So, this is a null and void. Social Welfare Minister has no powers whatsoever in the Constitution under the Allocation of Rules of Business. He is nobody; he or she. مانئیے پردھان منتری جی، آپ یہ نوٹیفکیشن دیکھئیے جو 19 نومبر 2015 کو ایشو ہوتا ہے. اب دوسری وڈمبنا دیکھئیے، جس میں شکشا منترالیہ، 10نومبر یعنی9 دن پہلے ایک دوسرا منترالیہ دیش کی تمام Central Institutions کے لئے Celebration of the Constitution Day, 2015 کے بارے میں آرڈر نکالتا ہے. مانئیے پردھان منتری جی، یہ کیا ہورہا ہے؟ Ministry of Education دس نومبر کوآرڈر نکالتی ہے کہ تمام educational institutions اسے celebrate کریں اور اس کے نو دن بعد Social Justice Ministry آرڈر نکالتی ہے. تو اس نئے کانسٹی ٹیوشن کے بارے میں بھی چرچہ کی جائے یا اس طرح کا کوئی Amendment لایا جارہا ہے، تو وہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ نوٹیفکیشن جس منسٹری کو نکالنا چاہئیے، اس کے بجائے دوسری منسٹری کیوں نکالتی ہے؟ اس نوٹیفکیشن سے پہلے تیسری منسٹری Celebration کے لئے اور government holiday کے لئے نوٹیفکیشن نکالتی ہے. مانئیے پردھان منتری جی، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس یہ نوٹیفکیشن نہیں ہے، تو میں وہ دکھاسکتا ہوں. ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

श्री विजय गोयल (राजस्थान) : सर, मैं आप से जानना चाहता हूं कि इस से नुकसान क्या हो रहा है?

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। Please continue. *...(Interruptions)....*

श्री गुलाम नबी आज़ाद : यह कानून में व्यवस्था है और आप यह क्या कर रहे हैं? ये तो गैर-कानूनी चीजें हो रही हैं।

جناب غلام نبی آزاد: یہ قانون میں ویوستھا ہے اور آپ یہ کیا کررہے ہیں؟ یہ تو غیرقانونی چیزیں ہورہی ہیں۔

श्री विजय गोयल : इस में गैर-कानूनी क्या है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : Allocation of Business Rules के तहत यह उनका काम नहीं है। आप सोचिए, Social Justice Minister अगर होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर करेगा, तो आप उसे गैर-कानूनी मानेंगे या नहीं? यह तो हद हो गयी!

جناب غلام نبی آزاد: Allocation of Business Rules کے تحت یہ ان کا کام نہیں ہے۔ آپ سوچئے، Social Justice Minister اگر ہوم منسٹری کے آرڈر کرے گا، تو آپ اسے غیرقانونی مانیں گے یا نہیں؟ یہ تو حد ہوگئی۔

MR. CHAIRMAN : One minute Ghulam Nabi *Sahab*.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the hon. Leader of the Opposition, संविधान के बारे में जिसे भी क्रेडिट देना चाहते हैं दें, लेकिन आज जब डा. अम्बेडकर की 125वीं anniversary मना रहे हैं तो why is this grudging feeling about Dr. Ambedkar? *...(Interruptions)....* आप नेहरू जी की चर्चा करो, ...(**व्यवधान**)... आप इसे क्यों मना रहे हो? इसे मनाने का आपका नोटिफिकेशन गलत है, Why is this grudging feeling? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप लोग बैठ जाइए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैंने शुरू में ही कहा था कि, "चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से न जाए।" उसके लिए ये कहते हैं कि, "जब जिंदा थे तब उनको लड़ाने की कोशिश करते थे और अब वे जिंदा नहीं हैं, तब भी लड़ाने की कोशिश करते हैं। यह हमारी सम्पत्ति है, यह आपकी सम्पत्ति नहीं बन सकती। यह देश की सम्पत्ति है। आप जब कांस्टिट्यूशन पर बात करें, तो नाज़ी जर्मनी तक की बात करें, हम अपने पूर्व प्रधान मंत्री जी तक की भी बात न करें। वाह! यही intolerance है Sir कि आप जर्मन के डिक्टेटर की बात कर सकते हैं, वहां के कांस्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं और हम हिन्दुस्तान के फ्रीडम फाइटर प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... यही विचार है कि आप अम्बेडकर जी पर चर्चा करने के लिए दुनिया के डिक्टेटरों की चर्चा करेंगे और आप अपने देश के प्रधान मंत्री जी का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं। हमारे लिए यह शर्म की बात है। ...(**व्यवधान**)... माननीय चेयरमैन साहब, मैं आखिर में दो मिनट और लूंगा।

شری سبھاپتی : آپ لوگ بیٹھ جائیے۔

جناب غلام نبی آزاد: میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ، ''چور چوری سے جائے، ہیراپھیری سے نہ جائے''۔ اس کے لئے یہ کہتے ہیں کہ، ''جب زندہ تھے تب ان کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے اور اب وہ زندہ نہیں ہیں، تب بھی لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

یہ ہماری سمپتی ہے، یہ آپ کی سمپتی نہیں بن سکتی۔ یہ دیش کی سمپتی ہے۔ آپ جب کانسٹی ٹیوشن پر بات کریں، تو نازی و جرمنی تک کی بات کریں، ہم اپنے سابق پردھان منتری جی تک کی بھی بات نہ کریں۔ واہ، یہی intolerance ہے سر کہ آپ جرمن کے ڈکٹیٹر کی بات کرسکتے ہیں، وہاں کے کانسٹی ٹیوشن کی بات کرسکتے ہیں اور ہم ہندستان کے فرسٹ فائیٹر پرائم منسٹر کی بات نہیں کرسکتے ہیں ---(مداخلت)--- یہی سوچ ہے کہ آپ امبیڈکر جی پر چرچہ کرنے کے لئے دنیا کے ڈکٹیٹروں کی چرچہ کریں گے اور آپ اپنے دیش کے پردھان منتری جی کا نام لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے لئے یہ شرم کی بات ہے ---(مداخلت)--- مائینے چیئرمین صاحب، میں آخر میں دو منٹ اور لونگا۔

श्री सभापति : प्लीज़।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि ठीक है, कांस्टिट्यूशन तो बन गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हो गई, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी कब और कैसे लागू होगी? हमें सोशल डेमोक्रेसी की तरफ ध्यान देना होगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 1956 में कहा था कि ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी गरीब और अमीर के बीच का फासला कम करने में मदद करेगी, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी के बारे में क्या होगा? यहां introspection करने की जरूरत है। आज यहां introspection शुरू हो । हमारे संविधान में क्या कमियां और कमजोरियां हैं, आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहां इकट्ठे नहीं हुए हैं। संविधान ने जो पास किया है, क्या आज उस भारतीय संविधान के अनुसार हम इस देश में समाज के हर वर्ग को सोशल जस्टिस दे रहे हैं, यह जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज expression और faith की बात हो रही है। क्या आज हर आदमी को इबादत व पूजा करने की आज़ादी मिल रही है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक, डेढ़ साल से देश में जो वातावरण पैदा हो गया है, यह हमारे कांस्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है, यह हमारे देश के preamble के खिलाफ है। ...(**व्यवधान**)... माननीय लीडर ऑफ दि हाउस ने कहा कि intolerance manufactured है, जनता की तरफ से भी intolerance manufacture की जा रही है और from the ruling party, आज आप देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और यूपी में किसी की नाक काट दी जाती है, किसी का हाथ काट दिया जाता है कि उसने अपर कास्ट के साथ खाना खा लिया। एक लड़के का हाथ इसलिए काट दिया गया कि उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी।...(**व्यवधान**)...

جناب غلام نبی آزاد: جس طرح سے بابا صاحب امبیڈکر جی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، کانسٹی ٹیوشن تو بن گیا، پالیٹیکل ڈیموکریسی تو ہوگئی، لیکن سوشل ڈیموکریسی کب اور کیسے لاگو ہوگی؟ ہمیں سوشل ڈیموکریسی کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ پنڈت جواہرلعل نہرو جی نے 1956 میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے پالیٹیکل ڈیموکریسی غریب اور امیر کے بیچ کا فاصلہ کم کرنے میں مدد کریگی، لیکن سوشل ڈیموکریسی کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہاں retrospection کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں retrospection شروع ہورہا ہے۔ ہمارے آئین میں کیا کمیاں اور کمزوریاں ہیں، آج ہم اس پر چرچہ کرنے کے لئے یہاں اکھٹےنہیں ہوئے ہیں۔ سمودھان نے جو پاس کیا ہے، کیا آج اس بھارتیہ سمودھان کے مطابق ہم اس ملک میں سماج کے ہر طبقے کو سوشل جسٹس دے رہے ہیں، یہ جاننے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج expression اور faith کی بات ہورہی ہے۔ کیا آج ہر آدمی کو عبادت و پوجا کرنے کی Opportunity مل رہی ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ڈیڑھ سال سے ملک میں جو حالات پیدا ہوگئے ہیں، یہ ہمارے کانسٹی ٹیوشن کے بلکل خلاف ہے، یہ ہمارے ملک کے Preamble کے خلاف ہے ---(مداخلت)--- آج مائینے لیڈر اف دی ہاؤس نے کہا کہ intolerance manufactured ہے، جنتا کی طرف سے بھی intolerance manufacture کی جارہی ہے اور from the ruling party آج آپ دیکھیئے کہ کس طرح سے مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹر میں، ہریانہ میں اور یوپی میں کسی کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے آپرکاسٹ کے ساتھ کھانا کھالیا۔ ایک لڑکے کا ہاتھ اس لئے کاٹ دیا گیا کہ اس نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی ---(مداخلت)---

श्री सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : एक लड़के का हाथ इसलिए काट दिया गया कि उसने बाबा साहेब अम्बेडकर जी ...(**व्यवधान**)...

جناب غلام نبی آزاد: ایک لڑکے کا ہاتھ اس لئے کاٹ دیا گیا کہ اس نے بابا صاحب امبیڈکر جی ....(مداخلت)...

श्री सभापति : प्लीज़! बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसी से तो पता चलता है कि अगर आपका स्वभाव यहां ऐसा है, तो नीचे क्या होगा? आप tolerate नहीं कर पा रहे हैं, आप समाज को tolerate नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ मिसाल है कि जब पेड़ पर फल लगता है, तो वह पूरा नीचे झुक जाता है। अगर पेड़ पर फल लगा हो और वह नीचे न झुके, तो इसका मतलब यह है कि उसके DNA में कोई कसूर है। यहाँ पेड़ झुकता नहीं है, बल्कि और ऊँचा होता है। अगर वह पेड़ नीचे नहीं झुके, जो पावर होती है, वह उस पेड़ की तरह होती है, जो फलों से लदा हुआ हो, तो वह ठीक नहीं है। उसका सिर झुका होना चाहिए, जमीन की तरफ होना चाहिए, आसमान की तरफ नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ और बधाई देता हूँ समाज के उन लोगों को। आजादी से पहले भी हमारे देश में नेताओं के अलावा कई पत्रकार, कई लेखक, कई शायर, चाहे वे हिन्दी के हों या उर्दू के हों, चाहे दूसरी भाषाओं के हों, वे समाज में अन्याय के खिलाफ उठे थे। आज मैं उन लेखकों को, उन राइटर्स को, उन बुद्धिजीवियों को, उन कलाकारों को, शायद मैंने एकाध का नाम सुना हो, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन बधाई देता हूँ। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस वाला कोई नहीं है। कांग्रेस मैन्यूफैक्चर नहीं करती, इसे मैन्यूफैक्चर करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम प्यार को मैन्यूफैक्चर करते हैं, हम लड़ाई और नफरत को मैन्यूफैक्चर नहीं करते हैं। हम जिन इंसानों को मानने वाले हैं - गाँधी, नेहरू, अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस - उन्होंने हमें लड़ाई नहीं सिखाई है, लड़ाई की मैन्यूफैक्चरिंग नहीं सिखाई है, हमें प्यार सिखाया है, हर धर्म से, हर मजहब से, हर भाषा से, अपने देश से। ...(**व्यवधान**)... यहाँ माननीय ...(**व्यवधान**)... आपको क्या तकलीफ हो रही है? ...(**व्यवधान**)... क्योंकि आपकी पार्टी भी पंजाब में, मैं ही इंचार्ज था, जब मैं उन लोगों का भोग अटेंड करता था, जिनको मिलिटेंट्स ने मारा और आप उनके भोग अटेंड करते थे, जो मिलिटेंट्स थे। आप मुझे क्या दिखाएँगे? 6 साल में मुझ पर पंजाब में 26 अटैक्स हुए, तब आप कहाँ थे? आप विदेश में थे। ...(**व्यवधान**)... आप हमें क्या सुनाएँगे? मैंने शुरू किया ...(**व्यवधान**)... फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, 1986 से लेकर 1991 तक। आप क्या बात करते हैं? आप किस दुनिया में रहते थे? आपका रास्ता और जिनको आप सपोर्ट करते हैं, वे कहीं दूसरे रास्ते थे। आप लोग कब आए? आप पावर के लिए आए। आप पावर के लिए, कुर्सी के लिए आए।

आज हमारे लीडर ऑफ दि हाउस ने कहा कि जब यहाँ पार्लियामेंट पर आतंकवादियों की तरफ से हमला हुआ, मुम्बई में हमला हुआ, होटल्स पर हुआ, गाड़ियों पर हुआ, ट्रेन्स पर हुआ, तो कुछ लोग आतंकवादियों का एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समर्थन करते थे या उनको हीरो

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

1.00 P,M.

मानते थे। मैं समझता हूँ कि वह आतंकवादी अन्दर का हो या बाहर का हो, आप सबसे ज्यादा हमने उसे झेला है। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी और अभी भी हम उनको झेलते हैं, उनसे लड़ते हैं। मैंने क्या-क्या किया, वह यहाँ नहीं कह सकता हूँ, आप जानते हैं। यह तो खुदा की रहमत है, किस्मत है कि अभी जिंदा हैं, वरना जो अन्दर वाले आतंकवादी हैं, अपने ही स्टेट के, हम पर उनके कहीं ज्यादा हमले हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ इस सदन में या किसी पार्टी का कोई लीडर पार्लियामेंट के अटैक को या अटैकर्स को अच्छा मानता हो। उनको फाँसी दी गई, दी जानी चाहिए। अगर कोई बचा है, तो उसको भी फाँसी दी जानी चाहिए। जम्मू-कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैंने अपनी पहली ही प्रेस कांफ्रेंस में कहा, जिसको मैंने 2.5-3 साल हर पब्लिक मीटिंग में कश्मीर के अन्दर कहा, सोपोर के अन्दर कहा कि जो भी हमारी रियासत में, हमारे देश में, वह अन्दर वाला आतंकवादी हो या बाहर वाला आतंकवादी हो, अगर बंदूक लेकर हमारे किसी भी इंसान को मारने आएगा, तो उसकी लाश वापस जानी चाहिए।

ऐसा गुलाम नबी आज़ाद ने, मैंने कहा था। मैं आज भी यह कहता हूँ, मैंने तब भी कहा था, उस मीटिंग में भी कहा था।

جناب غلام نبی آزاد: اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا سوبھاؤ یہاں ایسا ہے، تو نیچے کیا ہوگا؟ آپ tolerate نہیں کرپارہے ہیں، آپ سماج کو tolerate نہیں کررہے ہیں۔ ہماری مثل ہے کہ جب پیڑ پر پھل لگتا ہے، تو وہ پورا نیچے جھک جاتا ہے۔ اگر پیڑ پر پھل لگا ہو اور وہ نیچے نہ جھکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے DNA میں کوئی قصور ہے۔

یہاں پیڑ جھکتا نہیں ہے، بلکہ اور اونچا ہوتا ہے۔ اگر وہ پیڑ نیچے نہیں جھکے جو پاور ہوئی ہے، وہ اس پیڑ کی طرح ہوتی ہے، جو پھلوں سے لدا ہوا ہو، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا سر جھکا ہونا چاہئے، زمین کی طرف ہونا چاہئے، آسمان کی طرف نہیں۔ اس لئے میں نویدن کرتا ہوں اور بدھائی دیتا ہوں سماج کے ان لوگوں کو۔ آزادی سے پہلے بھی ہمارے دیش میں نیتاؤں کے علاوہ کئی پترکار، کئی لیکھک، کئی شاعر، چاہے وہ ہندی کے ہوں یا اردو کے ہوں، چاہے دوسری بھاشاؤں کے ہوں، وہ سماج میں انیائے کے خلاف اٹھے تھے۔ آج میں ان لیکھکوں کو، ان رائیٹرس کو، ان بڈی جیویوں کو، ان کلاکاروں کو، شاید میں نے ایک آدھ کا نام سنا ہو، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی سمبندھ نہیں ہے، لیکن بدھائی دیتا ہوں ...(مداخلت)... کانگریس والا کوئی نہیں ہے۔ کانگریس مینیوفیکچر نہیں کرتی ، اسے مینیوفیکچر کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم پیار کو مینیوفیکچر کرتے ہیں، ہم لڑائی اور نفرت کو مینیوفیکچرنہیں کرتے ہیں۔ ہم جن انسانوں کو مانتے والے ہیں۔ گاندھی، نہرو، امبیڈکر، مولانا آزاد، سردار پٹیل اور نیتاجی سبھاش چندر بوس، انہوں نے ہمیں لڑائی نہیں سکھائی ہے، لڑائی کی مینیوفیکچرنگ نہیں سکھائی ہے، ہمیں پیار سکھایا ہے، ہر دھرم سے، ہر مذہب سے، ہر بھاشا ، اپنے دیش سے ...(مداخلت)... یہاں ماتینے ...(مداخلت)... آپ کو کیا تکلیف ہورہی ہے؟ ...(مداخلت)... کیوں کہ آپ کی پارٹی بھی پنجاب میں، میں ہی انچارج تھا، جب میں ان لوگوں کا بھوگ اٹینڈ کرتا تھا، جن کو ملی ٹینٹس نے مارا اور آپ ان کے بھوگ اٹینڈ کرتے تھے، جو ملیٹینٹس تھے۔ آپ مجھے کیا دکھائیں گے؟ چھ سال میں مجھ پر پنجاب میں 26 اٹیکس ہوئے، تب آپ کہاں تھے؟ آپ ودیش میں تھے۔ ...(مداخلت)...آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں نے شروع کیا ...(مداخلت)... فرسٹ پیج، سیکنڈ پیج، تھرڈ پیج، فورتھ پیج، ففتھ پیج، 1986 سے لیکر 1991تک۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کس دنیا میں رہتے تھے۔ آپ کا راستہ اور جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہیں دوسرے راستے تھے۔ آپ لوگ کب آئے۔ آپ پاور کے لئے آئے۔ آپ پاور کے لئے، کرسی کے لئے آئے۔

آج ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس نے کہا کہ جب یہاں پارلیمنٹ پر آتنک وادیوں کی طرف سے حملہ ہوا، ممبئی میں حملہ ہوا، بوٹلس پر ہوا، گاڑیوں پر ہوا، ٹرینس پر ہوا، تو کچھ لوگ آتنک وادیوں کا ایک طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سمرتھن کرتے تھے یا ان کو ہیرو مانتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آتنک وادی اندر کا ہو یا باہر کا ہو، آپ سب سے زیادہ ہم نے اسے جھیلا ہے۔ چیف منسٹر بننے سے پہلے بھی، چیف منسٹر بننے کے بعد بھی اور ابھی بھی ہم ان کو جھیلتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ میں نے کہا۔ کیا کیا۔ وہ یہاں نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ یہ تو خدا کی رحمت ہے، قسمت ہے کہ ابھی زندہ ہیں، ورنہ جو اندر والے آتنک وادی ہیں اپنے ہی اسٹیٹ کے، ہم پر ان کے کہیں زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس سدن میں یا کسی پارٹی کا کوئی لیڈر پارلیمنٹ کے اٹیک کو یا اٹیکرس کو اچھا مانتا ہو۔ ان کو پھانسی دی گئی، دی جانی چاہئے۔ اگر کوئی بچا ہے، تو اس کو بھی پھانسی دی جانی چاہئے۔ جموں وکشمیر کا چیف منسٹر بننے کے بعد میں نے اپنی پہلی ہی پریس کانفرنس میں کہا، جس کو میں نے ڈھائی تین سال ہر پبلک میٹنگ میں کشمیر کے اندر کہا، سوپور کے اندر کہا کہ جو بھی ہماری ریاست میں، ہمارے دیش میں، وہ اندر والا آتنک وادی ہو یا باہر والا آتنک وادی ہو، اگر بندوق لیکر ہمارے کسی بھی انسان کی مارنے آئے گا، تو اس کی لاش واپس جانی چاہئے۔

ایسا غلام نبی آزاد نے، میں نے کہا تھا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، میں نے تب بھی یہ کہا تھا، اس میٹنگ میں بھی کہا تھا۔

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): इसको हम एप्रीशिएट करते हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: आप एप्रीशिएट करते हैं, लेकिन मैं तब एप्रीशिएट करूंगा, जब समझौता एक्सप्रेस के लोगों पर भी एक्शन लिया जाए, न कि गवर्नमेंट कहे कि सेंट्रल एजेन्सीज को स्लो-डाउन करो। यह मालेगांव है, हैदराबाद है, और भी जगह-जगह जो हुआ है। इसमें कोई परिभाषा नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी कोई कहीं इन्वॉल्व हो, उसके साथ आतंकवादी का सलूक किया जाना चाहिए। उसमें धर्म नहीं आना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

وزیر برائے ذرائع ابلاغ (جناب روی شنکر پرساد): اس کو ہم اپریشئیٹ کرتے ہیں۔

جناب غلام نبی آزاد : آپ اپریشئیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں تب اپریشئیٹ کروں گا، جب سمجھوتا ایکسپریس کے لوگوں پر بھی ایکشن لیا جائے، نا کہ گوورنمینٹ کو کہا جائے کہ سینٹرل ایجنسیز کو سلو-ڈاؤن کرو۔ یہ مالےگاؤں ہے، حیدرآباد ہے، اور بھی جگہ جگہ جو ہوا ہے۔ اس میں کوئی پریبھاشا نہیں ہونی چاہئے۔ آتنک-وادی ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، جو بھی کوئی، کہیں انوولو ہو، اس کے ساتھ آتنک وادی کا سلوک کیا جانا چاہئے، اس میں دھرم نہیں آنا چاہئے ...(مداخلت)...

श्री बलविंदर सिंह भुंडर(पंजाब) : देश में कत्लेआम हो सकता है. उसमें कोई सजा नहीं। ...(**व्यवधान**)... 30 साल हो गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बैठ जाइए, प्लीज। On your time, please. ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: जो चीजें अदालतों में चल रही हैं, उनमें अदालत चाहे जिनको सजा दे, हम कभी बीच में नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

شری سبھا پتی : بیٹھ جائیے، پلیز۔ On your time, please ...(مداخلت)...

جناب غلام نبی آزاد : دو چیزیں عدالتوں میں چل رہی ہیں، ان میں عدالت چاہے جن کو سزا دے، ہم کبھی بیچ میں نہیں ہیں ...(مداخلت)...

श्री बलविंदर सिंह भुंडर: 30 साल हो गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: अदालतों में जो भी निर्णय हो रहे हैं, उनमें कोई बीच में नहीं है। इस देश की अदालतें इसीलिए बनी हैं। ...(**व्यवधान**)... इनकी, किसी भी व्यक्ति की हमारी पार्टी ने सहायता नहीं की, मदद नहीं की। अदालतों ने अपने फैसले लिए हैं, अदालतों को कभी रोका नहीं गया। अदालतों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर फैसले सुनाए हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, लीडर ऑफ दि हाउस से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि फांसी दीजिए, जो मुंबई में अटैक करता है, या कहीं भी अटैक करता है, लेकिन चुन कर मत कीजिए कि कहीं स्लो डाउन हो, कहीं जल्दी हो, क्योंकि उससे देश में एक बड़ी निराशा पैदा होती है।

सभापति जी, आखिर में, आप प्यार और मोहब्बत करें। मैं यही कहूंगा कि -

"हिंदुस्तान में खैर से उनकी कमी नहीं,
लब पर है जो खुलूस का दफ्तर लिए हुए।
कहते हैं भाई भाई हैं अहले वतन तमाम,
फिरते हैं आस्तीनों में खंजर लिए हुए।"

इसलिए हम आस्तीनों में खंजर न ले लें। हम जुबां में भी, पीठ पीछे भी और सामने भी एक ही भाषा रखें, देश के साथ चलें। इस देश में जो वातावरण है, आपने ठीक कहा कि आज कमिटमेंट का दिन है। शायद जिन लोगों में, जैसा मैंने कहा है कि कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन आज के बाद जिन लोगों की कंस्टीट्यूशन पर कमिटमेंट नहीं थी, वे कमिटमेंट करें और आने वाले वक्त में उसको लेकर चलें। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यह कंस्टीट्यशून दिखाया है, सरकार चलाने का और सरकारें चलाने का जो रास्ता दिखाया है, चाहे वह नेशनल सरकार हो, अगर हम संविधान के तहत चलेंगे, तो मेरे ख्याल से यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा साहेब अम्बेडकर को होगी कि हम इस देश से यह नफरत खत्म कर दें, जो हमें आपस में बांटती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

جناب غلام نبی آزاد : عدالتوں میں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، ان میں کوئی بیچ میں نہیں ہے۔ اس دیش کی عدالتیں اسی لئے بنی ہیں ---(مداخلت)-- ان کی، کسی بھی آدمی کی ہماری پارٹی نے سہائتہ نہیں کی، مدد نہیں کی۔ عدالتوں نے اپنے فیصلے کئے ہیں، عدالتوں کو کبھی روکا نہیں گیا۔ عدالتوں نے دھرم اور ذات سے اوپر اٹھہ کر فیصلے سنائے ہیں۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، لیڈر آپ دی ہاؤس سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پھانسی دیجئے، جو ممبئی میں اٹیک کرتا ہے، یا کہیں بھی اٹیک کرتا ہے، لیکن چن کر مت کیجئے کہ کہیں سلو -ڈاؤن ہو، کہیں جلدی ہو، کیوں کہ اس سے دیش میں ایک بڑا ناامیدی پیدا ہوتی ہے۔

سبھا پتی جی، آخر میں، آپ پیار اور محبت کریں میں یہیں کہوں گا کہ ---
ہندوستان میں خیر سے ان کی کمی نہیں،
لب پر ہے جو خلوص کا دفتر لئے ہوئے،
کہتے ہیں بھائی بھائی اہل وطن تمام،
پھرے ہیں آستینوں میں خنجر لئے ہوئے۔

اس لئے ہم آستینوں میں خنجر نہ لے لیں۔ ہم زبان میں بھی، پیچھے بھی اور آگے بھی ایک ہی بھاشا رکھیں، دیش کے ساتھہ چلیں۔ اس دیش میں جو ماحول ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ آج کمٹمینٹ کا دن ہے۔ شاید جن لوگوں میں، جیسا میں نے کہا ہے کہ کمٹمینٹ نہیں تھی، لیکن آج کے بعد جن لوگوں کی کانسٹی ٹیوشن پر کمٹمینٹ نہیں تھی، وہ کمٹمینٹ کریں اور آنے والے وقت میں اس کو لے کر چلیں۔ جب بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں یہ کانسٹی ٹیوشن دکھایا ہے، سرکار چلانے کا اور سرکاریں چلانے کا جو راستہ دکھایا ہے، چاہے وہ نیشنل سرکار ہو، اگر ہم سنودھان کے تحت چلیں گے، تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی شردھانجلی بابا صاحب امبیڈکر کو ہوگی کہ ہم اس دیش سے یہ نفرت ختم کر دیں گے، جو ہمیں آپس میں بانٹتی ہے۔ بہت بہت دھنیواد۔ جے ہند۔

†Transliteration in Urdu Script.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. The House is adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Ram Gopal Yadav we will continue the discussion.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, श्रीमन्। 26 नवम्बर, 1949 के दिन हमारी संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था, स्वीकृत किया था, आत्मार्पित किया था। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में सदन में यह चर्चा हो रही है। प्रश्न यह है कि जब से संविधान लागू हुआ, तब से अब तक क्या हम संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुकूल चले हैं? किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए एक रास्ता बताता है कि हमें किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है, देश की सरकार कैसे बनेगी, सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्या होंगे, उनके आपसी रिश्ते कैसे होंगे, जनता और सरकार के बीच किस तरह के रिश्ते होने चाहिए और किस तरह से उनको इम्प्लिमेंट किया जाए। ये सारी चीज़ें संविधान निर्माताओं के दिमाग में भी रही होंगी और उसी दृष्टि से भारत का एक शानदार संविधान बना।

यह सही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियां थीं। कई कमेटियों के चेयरमैन पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे, कुछ कमेटियों के चेयरमैन सरदार पटेल थे और अध्यक्ष होते हुए, कुछ कमेटियों के चेयरमैन बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी स्वयं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, डा. भीमराव अम्बेडकर थे।

जब-जब हम संविधान की चर्चा करते हैं, तो हम एक नाम हमेशा भूल जाते हैं, जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह अन्याय होगा। श्री बी.एन. राव हमारी संविधान सभा के कॉंस्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे और संविधान के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान था। 26 नवम्बर, 1949 को, जिस दिन संविधान बना, उस दिन भी डा. राजेन्द्र प्रसाद ने उनके विशेष योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया था। श्री बी.एन. राव जी ने न केवल संविधान का ओरिजनल ड्राफ्ट तैयार किया था, बल्कि जब-जब भी संविधान सभा के सदस्यों को सम्बन्धित मेटीरियल की आवश्यकता पड़ती थी, वह मेटीरियल भी उन्होंने ही उपलब्ध कराया था, ताकि वे संविधान के निर्माण की तैयारी कर सकें, सवाल पूछ सकें, संशोधन कर सकें और बहस में हिस्सा ले सकें। स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी कमेटी के सामने जब उस ड्राफ्ट को रखा, तो यह कहा कि हम इस ड्राफ्ट को आपके विचार के लिए इसलिए रख रहे हैं, ताकि हम इसको स्क्रूटनाइज़ कर सकें और अगर जरूरत पड़े तो संशोधन कर सकें एवं और अधिक परिमार्जित कर सकें। इसके बाद उसको संविधान सभा में रखा गया, उस पर लम्बी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद 26 नवम्बर, 1949 को उसे पारित किया गया। अब असली समस्या यह थी कि संविधान बन गया है और जब यह इम्प्लीमेंट होगा, धरातल पर उतरेगा, तो स्थिति कैसी होगी, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू में ही कहा था कि हमने यह संविधान, यह जो लोकतंत्र का महल खड़ा

[प्रो. राम गोपाल यादव]

किया है, इसकी नींव बहुत ही अलोकतांत्रिक है। जिस तरह की सामंतवादी, जातिवादी और अन्य किस्म की ताकतें हैं, वे आम लोगों को उनके अधिकारों को देने में अड़चनें पैदा कर सकती हैं, इस बात की आशंका उनको हमेशा थी। यह जो आशंका थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उनको बेवजह ही यह आशंका हो, क्योंकि स्वयं अम्बेडकर साहब ने इस बात को झेला था। जब वे पढ़-लिख चुके थे और जब एक टीचर होने के बाद बम्बई पढ़ाने के लिए गये, तो हम सब ने पढ़ा है कि वहाँ किस तरह से कुर्सी को धोया गया, उन सड़कों को धोया गया जहाँ से अम्बेडकर निकले कि कुर्सी अपवित्र हो गयी, वे सड़कें अपवित्र हो गयीं। यह तो उस वक्त की बात थी। मुझे तो कभी-कभी अजीब लगता है कि बाबू जगजीवन राम बनारस में एक मूर्ति का अनावरण कर आये, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाई श्री करुणापति त्रिपाठी ने, कमलापति त्रिपाठी जी के भाई ने, उस मूर्ति को गंगाजल से धुलवाया कि यह अपवित्र हो गयी। तो अम्बेडकर साहब यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने यह कहा था कि हमने यह जो लोकतंत्र का महल खड़ा कर दिया है, इसकी नींव बड़ी कमज़ोर है, इसलिए अगर इस संविधान को सही तरीके से लागू करना है, तो देश के हर समझदार नागरिक को बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। संविधान लागू होने के कुछ दिनों बाद ही समस्याएँ शुरू हो गईं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ने जमींदारियाँ खत्म कीं। मामला कोर्ट में गया। रविं शकर प्रसाद जी यहाँ बैठे हुए हैं। कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था, जिसको रद्द कर दिया। जमींदारी उन्मूलन विधेयक जो आया, वह रद्द हो गया और यह कहा गया कि चूँकि आर्टिकल 13 में यह लिखा हुआ है और मौलिक अधिकारों का जो तीसरा चैप्टर है, उससे किसी भी रूप में अगर छेड़छाड़ की जायेगी या उसको छीनने की कोशिश की जायेगी, तो वह कानून उसी सीमा तक अवैध होगा। इसके बाद संविधान में संशोधन लाना पड़ा। तब पंडित नेहरु जी ने गुस्से में इसी दूसरे सदन में एक बात कही थी। जब संशोधन लाया गया, तो संशोधन करने में दिक्कतें न हों, उन्होंने कहा कि अगर न्यायालय का यही रवैया रहा, then haves will remain haves and have nots, have nots. अमीर अमीर बने रहेंगे और गरीब गरीब बने रहेंगे, क्योंकि मुआवजे के नाम पर हम सौ करोड़ की सम्पत्ति लेंगे और सौ करोड़ का मुआवजा देंगे, तो फर्क क्या पड़ा? यहाँ बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं और बहुत बड़े-बड़े लॉयर्स भी हैं। सब जानते हैं कि किस तरह से कम्पेंसेशन को लेकर इस देश में कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट से लेकर संसद के अन्दर तक उस पर चर्चा हुई और तरीके सोचे गये कि किस तरह से इसको ठीक रास्ते पर लाया जाये। तो कम्पेंसेशन को अमाउंट किया गया कि कम्पेंसेशन एक डेविएटेड शब्द है और अगर आप किसी की सौ करोड़ की सम्पत्ति लेते हैं, तो उसके मुआवजे का मतलब है- सौ करोड़ देना, तो उससे काम नहीं चलेगा, इसलिए amount indefinite कर दीजिए। शंकरी प्रसाद वाले केस में आगे रास्ता ठीक भी हो गया और न्यायालय को कोई ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद एक ऐसा मसला आया, एक ऐसा केस आया, जिसमें बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में यह फैसला कर दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई हक नहीं है। यह 1967 की बात है। यह पंजाब स्टेट का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट में आया था तथा उस पर यहां फैसला हुआ। यह एक ऐसा फैसला था जिसके बाद अगर संसद कोई प्रगतिशील कानून बनाए तो मुश्किल था। उसी के बाद हम लोग जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वह भी इसी आधार पर रद्द हो गया। मैं आज कुछ बातें यहां रखना चाहता हूं। केवल यही नहीं

कि कहां न्यायपालिका ने क्या किया, कार्यपालिका ने कहां पर गलती की और विधायिका से कहां गलती हुई, इन सारी चीजों को बहुत संक्षेप में मैं यहां रखना चाहता हूं, क्योंकिं सविधान पर चर्चा हो रही है तो इस पूरे रास्ते में हम कहां-कहां भटके, कहां गलतियां हुईं, उनकी चर्चा होगी, इसलिए इसे कोई अपनी आलोचना न समझे। मैं तो बिल्कुल तथ्यात्मक ढंग से, बिल्कुल नॉन-पोलिटिकल व्यक्ति की तरह से आज बात करने जा रहा हूं। तो गोलकनाथ केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला किया किं ससद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई हक नहीं है तो जब इन्दिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उसको भी इसी आधार पर रद्द कर दिया गया। तब एक 24वां संविधान संशोधन आया। उस संविधान संशोधन के बारे में 13 जजों की बेंच थी, जिसने मान तो लिया किं ससद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन कुछ डॉयरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए, सब को नहीं, कुछ डॉयरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कुछ सीमा तक कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है या छीना जा सकता है। लेकिन उसका एक परिणाम यह हुआ कि जिन 6 जजेज़ ने उस फैसले पर दस्तखत नहीं किए थे, उसी में कोई बेसिक स्ट्रक्चर वाला मामला आ गया। 24वें संविधान संशोधन को जब केशवानन्द भारती के केस में चेलेंज किया गया तो उसने यह कहा और उसमें भी कुछ जजों ने दस्तखत नहीं किए थे, उन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेज़ को सुपरसीड करके एक जज को चीफ जस्टिस बनाया गया, जिसकी बड़ी आलोचना हुई। जस्टिस शेलत, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े, इन तीन जजों को सुपरसीड करके ए. एन. रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये वे जज थे, जिन्होंने उस फैसले पर दस्तखत नहीं किए थे। तो यहां से शुरू होता है कि किस तरह से कई बार कार्यपालिका ने भी न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप किया। हम सब जानते हैं कि एक स्थिति ऐसी आई जब हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से इस देश में आपातकाल लगाना पड़ा। उस आपातकाल के दौरान जिस तरह से मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया, छीना गया, वह किसी से छिपा नहीं है। मुझे याद है कि जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय निरेन डे, हिन्दुस्तान के अटॉर्नी जनरल थे, तब उनसे यह सवाल पूछा गया कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति का चेहरा पसंद नहीं है और कलक्टर यह लिख दे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह लिख दे कि इमर्जेंसी को लागू करने में इस व्यक्ति के चेहरे की वजह से बाधा पड़ सकती है, तो क्या आप उसके जीवन को ले सकते हैं? इस पर हिन्दुस्तान के अटॉर्नी जनरल का जवाब 'हां' में था। Just imagine कि जिस संविधान को लोगों ने बहुत सोच-समझ कर बनाया, उस संविधान को लागू करते वक्त कभी किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह दिन भी आ सकता है, जब यह कहा जाए कि इमर्जेंसी को लागू करने के लिए, to maintain internal security of the country, 'मीसा' जो था, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसी की जान को भी लिया जाए, तो लिया जा सकता है, वह वैलिड है। यह हिन्दुस्तान के अटॉर्नी जनरल का कहना था। It is on record. ऐसा नहीं है कि मैं यह ऐसे ही कह रहा हूँ। निरेन डे ने इसके जवाब में 'हां' कहा था, जब उनसे पूछा गया था। यह स्थिति रही, लेकिन केवल कार्यपालिका ने ही नहीं, कई ऐसे अवसर आए हैं, जब न्यापालिका ने भी अपने दायरे से हट कर ऐसे निर्णय दिए, जो अव्यावहारिक थे, जिनसे दिक्कतें आने वाली थीं, जिनकी वजह से दिक्कतें आईं। आपकी जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका ने जब अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया, तो वह मामला और बिगड़ता चला गया। संविधान में यह अपेक्षा की

[प्रो. राम गोपाल यादव]

गई थी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सब अपने-अपने क्षेत्रों का काम करेंगे, अनावश्यक किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जितना जरूरी है, उतना ही करेंगे, लेकिन संसद के सदस्य होने के नाते, सदन का सदस्य होने के नाते मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि इस और उस सदन को भी बहुत विषम परिस्थितियों में जिस कर्त्तव्य का निर्वाह करना चाहिए था, वह नहीं किया।

हमें याद है कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले के बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी थी, तो संसद के अंदर संविधान में एक संशोधन लाया गया और वह संशोधन यह था कि देश के राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और प्रधान मंत्री के खिलाफ चुनाव से संबंधित कोई पिटीशन नहीं हो सकती और अगर पिटीशन होती भी है या पेंडिंग है, तो वह null and void समझी जाएगी। अगर इस पिटीशन पर फैसला भी हो गया है, तो वह फैसला भी निरस्त समझा जाएगा। यह संविधान संशोधन विधेयक इसी संसद में आया, पारित हुआ और न केवल पारित हुआ, बल्कि आज एक सदन ने पारित किया, कल दूसरे सदन ने पारित किया, परसों हिन्दुस्तान की आधे से ज्यादा विधान सभाओं ने उसका रेटिफिकेशन कर दिया, क्योंकि उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे की डेट थी। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, वह फैसला संसद ने कर दिया। यह संसद का एक ऐसा फैसला था किं जब-जब ससद की गरिमा की बात की जाएगी, जब-जब संसद की निष्पक्षता और ठीक तरीके से काम करने की बात की जाएगी, तो यह मामला उठेगा और इस पर अंगुली उठेगी कि हमें जो काम करना चाहिए था, वह सही तरीके से नहीं किया। ऐसा हुआ, लेकिन यह नहीं किं ससद अगर चाहे, तो जो कमियां हैं, उन्हें दूर न कर सके, चाहे फिर वे कार्यपालिका की हों या न्यायपालिका की हों, उन्हें rectify कर सकती है। यदिं ससद चाहे, तो उन कमियों को rectify कर सकती है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि व्यवस्थापिका या विधायिका अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहती है, तो कैसे कर सकती है। नवम्बर, 1964 में उत्तर प्रदेश की असैम्बली में एक घटना हुई। कुछ लड़कों ने पैम्फलेट छापकर एक एम.एल.ए. के खिलाफ, जब वे जा रहे थे, तो लॉबी में बांटे। उनमें से दो लड़कों को अरैस्ट कर लिया गया और विधान सभा के सामने लाया गया और उन्हें reprimand किया गया और फिर छोड़ दिया गया। एक लड़का केशव सिंह नहीं आया। उसे बाद में गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। उसने स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि आपका यह जो फरमान है, वह नादिरशाही फरमान है।

मान्यवर, विधान सभा ने इसे अपनी अवमानना माना और उस समय की उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी के प्रस्ताव पर उसे सात दिन की पनिशमेंट की सजा देकर लखनऊ जेल भेज दिया गया। यह बात नवम्बर 1964 की है। इस मामले को एक वकील, श्री सोलोमन, दिनांक 19 नवम्बर, 1964 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ले गए और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसे बेल-आउट कर दिया, जबकि सजा पूरी होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। उस समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा सैशन में थी। विधान सभा में यह मामला उठा। विधान सभा ने फिर न्यायालय का रुख लिया और यह कहा कि जिस जज ने बेल दी है और जो वकील इस प्रकरण में एपीयर हुए, उन्हें

गिरफ्तार कर के सदन के सामने लाया जाए। यह आदेश स्पीकर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लखनऊ को दिया।

मान्यवर, जैसे ही यह आदेश हुआ, तो हाई कोर्ट बेंच, लखनऊ के जो जज थे, जिन्होंने उसे बेल आउट किया, वे हाई कोर्ट इलाहाबाद की डिवीजन बेंच में चले गए और वहां से anticipatory bail ले ली। जब वहां से उन्होंने anticipatory bail ले ली, तो फिर विधान सभा बैठी और उसने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के जज और लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के जज को गिरफ्तार कर के सदन के सामने लाया जाए।

मान्यवर, वह इतना संगीन मामला हो गया कि राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं अपनी तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को रैफर कर दिया कि क्या इस तरह का मामला बन सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी राय दे दी कि हाई कोर्ट बेल दे सकती है, लेकिन मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा। एक साल के बाद, यानी 19 नवम्बर, 1965 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जब विधान सभा ने जनरल वॉरंट के तहत, स्पीकर ने अपनी सील के तहत किसी को पनिश करके सजा दी है तो किसी भी न्यायालय में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता और कलेक्टर, लखनऊ को आदेश दिया कि केशव सिंह की एक दिन की जो सजा रह गयी है, उसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ जेल भेजा जाए। इस प्रकार विधान सभाओं में जब विधायिका यह काम कर सकती है तो संसद भी यह काम कर सकती है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि Judicial Accountability Bill सर्वसम्मति से दोनों सदनों ने पारित किया, लेकिन हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया और हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की असेंबली से मैं यह कहना चाहूंगा, अपने सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि केशव सिंह वाले केस से, उत्तर प्रदेश की असेंबली से कुछ तो सीखें कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती कि यह संसद जो है वह जनता की प्रतिनिधि होती है और संसद हिन्दुस्तान की जनता की collective will को represent करती है। जिस संसद के दोनों सदन, सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर पहुंचे हों, वह देश की सामूहिक इच्छा का प्रदर्शन था और देश की सामूहिक इच्छा के प्रदर्शन के खिलाफ न्यायपालिका से फैसला आए, न्यायपालिका से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि जनता की इच्छा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा, पूरे देश की एकमत इच्छा के खिलाफ करेगा। संसद के दोनों सदनों की सर्वसम्मति, यानी देश की इच्छा के खिलाफ कोई फैसला करे, यह उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए इस सबंध में हमें सोचना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट के डील लेजिस्लेशन को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और दोबारा कानून बनाए - मंदी को निपटने के लिए कानून बनाए गए थे - तो लोगों ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई काम नहीं करने दे रहा है और लगता है कि राष्ट्रपति 1936 का चुनाव हार जाएंगे। उस वक्त रूज़वेल्ट ने गुस्से में कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का यही रवैया रहा तो हम सर्वोच्च न्यायालय को अपने लोगों से पैक कर देंगे। हालांकि सीनेट ने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, न ऐसा कभी हुआ, लेकिन 1936 से लेकर आज तक अमेरिका की न्यायपालिका ने कभी राष्ट्रपति से लड़ने वाला कोई फैसला नहीं किया है। आज तक कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ कि ऐसा हुआ हो कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच कोई विवाद पैदा हुआ हो। न्यायपालिका का काम कानून

[प्रो. राम गोपाल यादव]

3.00 P.M.

तोड़ने वालों को दंडित करना और जरूरत पड़ने पर कानून की व्याख्या करना है, लेकिन यहां तो न्यायपालिका appointments करने लगी, न्यायपालिका ट्रांसफर करने लगी, न्यायपालिका, नगर पालिका में कैसे सफाई हो, इसके लिए आदेश देने लगी। जब न्यायपालिका यह काम करने लगेगी, जब सारा काम न्यायपालिका करने लगेगी तो यह संसद किसलिए है और यह सरकार और मंत्री, जो बैठे हुए हैं, वे किस काम के हैं?

यह सही है कि जब बहस होती है कि कौन सर्वोच्च है, तो हम यही कहते हैं किं सविधान सर्वोच्च है। संविधान ने ही तो यह इच्छा व्यक्त की है। जो संविधान बनाने वाले थे, क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, जब इस संसद की सर्वोच्च, एकमत इच्छा के खिलाफ भी फैसला न्यायपालिका दे देगी और कहेगी कि तुम्हारा यह काम गलत था? संविधान निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा होगा। हम अम्बेडकर साहेब की 125वीं जयंती मना रहे हैं। अम्बेडकर साहेब की आत्मा भी करवटें ले रही होगी कि हमने जो संविधान बनाया था, उसका लोग किस तरह से इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, उसकी कदम-कदम पर किस तरह की व्याख्या हो रही है! मैं यही कहना चाहता हूं कि अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, जो काम हुए हैं, उनसे सीखने की जरूरत है और स्ट्राँगली जो हमारी संसद का क्षेत्राधिकार है, उसमें कोई अनावश्यक रूप से एनक्रोचमेंट न हो, इसको रोकने की भी जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकती है। जब भी गवर्नमेंट काम करेगी, तो बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए हम लोग नोटिस देने वाले हैं कि ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल पर जो फैसला हुआ है, उस पर यहां हाउस में चर्चा होनी चाहिए। पहले आप लोग भी सहमत थे, परन्तु अब पता नहीं है कि आपका क्या रुख है? अगर रुख बदल गया है, तो सदन की गरिमा कैसे बचे, इसके बारे में सोचिए, इस पर हम सब को सोचना पड़ेगा। हम संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं। हम संविधान से इतर होकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम संविधान की इच्छा के अनुकूल ही काम कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने जो सोचा, जो चाहा, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, इतना flexible संविधान हमारा है कि हम हर सेशन में एकाध संशोधन कर देते हैं। अमेरिका का संविधान 1789 में बना था, उसमें अभी तक 25 संशोधन हुए हैं। अमेरिका के संविधान में इतने लम्बे अरसे तक केवल 25 संशोधन हुए हैं और हमारे यहां सौ से अधिक संविधान में संशोधन हो चुके हैं, हमारे यहां सैंचुरी पूरी हो चुकी है। नेता सदन बैठे हुए हैं, तो सैंचुरी पूरी हो चुकी है, इसलिए इसको थोड़ा-सा rigid भी बनाइए। जो कानून आपने बनाए हैं, अगर उन कानूनों को लागू नहीं करने दिया जाएगा, अगर उनको रद्द कर दिया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि न्यायपालिका स्वयं न्यायपालिका के लोगों को नियुक्त करती हो। सभी जगह पर कार्यपालिका ही न्यायपालिका में नियुक्ति करती है। इग्लैंड में तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। हालांकि उसमें विधि सदस्य ही बैठते हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि The House is in Session. जो लॉ लॉर्ड्स होते हैं, वे ही केवल बैठते हैं। वहां पर यह परम्परा है, लेकिन वह अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका में राष्ट्रपति appoint करता है, सीनेट जजों का एप्रूवल करती है। और यहां आपने इतना बढ़िया कानून बनाया था कि उसकी निष्पक्षता के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता था

कि पक्षपातपूर्ण तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। उसे भी अवैध घोषित कर दिया, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अब हम इसे कैसे define करेंगे? माननीय नेता सदन यहां नहीं थे, मैं कह रहा हूं कि कार्यपालिका से भी गलतियां हुई हैं और वह वक्त ऐसा था जब न्यायपालिका ने कुछ नहीं किया। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को संसद ने बदल दिया, तो न्यायपालिका ने चुपचाप उसी के आधार पर without any comment फैसला दे दिया। उस समय न्यायपालिका कुछ नहीं बोली जबकि आज न्यायपलिका कदम-कदम पर किसी भी काम का विरोध करती है। उस समय वह बिल्कुल शांत थी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य के एक स्पीकर के खिलाफ एक विधायक की सदस्यता रद्द करने का मामला था। उन्होंने उसकी सदस्यता रद्द कर दी थी, तब हमने ही कानून में लिखा कि स्पीकर का फैसला अंतिम होगा और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन स्पीकर ने उसे मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को contempt का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उन्होंने दोबारा नोटिस देकर personally हाजिर होने के लिए बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। तीसरी बार नोटिस दिया, वे तब भी नहीं आए। तो सुप्रीम कोर्ट को केन्द्र सरकार से मध्यस्थता करने के लिए कहना पड़ा कि स्पीकर केवल आएं और वापस चले जाएं क्योंकि न्यायपालिका की इज्जत किसी तरीके से बच जाए। आप बताइए कि अगर इस तरह की नौबत आ जाएगी, तो क्या होगा? अब जिस तरह की गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अगर इस तरह की बातें दूसरे लोग करने लगेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए दिल्ली में आपकी सरकार है, राज्यों में भी आपकी सरकारें हैं और सुप्रीम कोर्ट मनमाने तरीके से कोई फैसला दे और आप कहें कि हम नहीं मानते, तब क्या स्थिति बनेगी? उसके फैसले को implement कराने वाली एजेंसी तो कार्यपालिका है and if कार्यपालिका refuses to do it, then, तब तो वही स्थिति बनेगी जोकि उस समय स्पीकर वाले मामले में बनी थी।

इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करे। वैसे आप कहते हैं किं ससद सर्वोच्च है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत संसद को constituent powers मिली हुई हैं। संसद चाहे तो इस के कुछ हिस्से को छोड़कर, जिसे अब basic structure कह दिया गया है, पूरे विधान को दोबारा संविधान सभा का रूप लेकर re-write कर सकती है except some basic structure. हालांकि उसे कभी किसी न्यायालय ने explain नहीं किया है। उसने कभी एक पॉइंट पर या दूसरे पॉइंट पर इसे explain कर दिया है, लेकिन वास्तव में क्या बेसिक structure है, इसे सही तरीके से explain नहीं किया है। इस की शुरुआत जस्टिस एच. आर. खन्ना ने की थी, लेकिन उसके बाद बार-बार ये बातें उठती रही हैं। इस संविधान को सही तरीके से लागू करने के लिए, मेरी सदन से और सदन के सभी लोगों से यह गुजारिश है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की महत्ता बनी रहे और सदन द्वारा बनाए गए कानूनों का जब चाहे तब, मन चाहे तरीके से गलत interpretation न किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकिं सविधान निर्माताओं की मन्शा की इज्जत बनी रहे, उसके अनुकूल काम हो और इससे बड़ी श्रद्धांजलि अम्बेडकर साहेब को या अन्य संविधान निर्माताओं को, जिनका संविधान निर्माण में बड़ा योगदान था, कोई हो नहीं सकती। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : शरद यादव जी, आपका नाम नेक्स्ट है, लेकिन येचुरी जी has requested कि इनकी फ्लाइट है और चार बजे इनको जाना है।

श्री शरद यादव (बिहार) : सर, हमें सोमवार को बुलवाइए।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप मंडे को बोलिए। श्री येचुरी जी, बोलिए ...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, after JD(U) with 12 MPs is Trinamool Congress with 12 MPs. So, where are you going now to...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I am only saying this.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, he will speak on Monday. And my colleague will speak now just 10 minutes before Mr. Yechury. ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Derek, let me say one thing. ...*(Interruptions)*.... देरेक जी, आप जरा सुनिए। Please listen to me. See, now it is the turn of Sharad Yadavji. He said he would speak on Monday. His turn only I am giving to Yechuryji. Why should you object? Because he wants to go, such adjustments should be done. ...*(Interruptions)*.... शरद जी ने Monday को बोलने के लिए कहा है। ...(**व्यवधान**)... If an hon. Member wants to go, we should make such adjustment. Always it is done like that. Everybody will be given time. Don't worry. ...*(Interruptions)*....

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we have two speakers from our Party.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Both will be given time, I am telling you.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am not making any issue. All I am saying is, you have requested Sharadji to speak. After that, it is the Trinamool Congress...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I did not make this request. I requested Sharadji,...

SHRI DEREK O'BRIEN: One second, Sir. There is no confusion. If he is not speaking, then, we have 35 minutes. We want to speak for 10 minutes now; Sukhenduji will speak. That is all.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, let him speak for 10 minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN: That is all; finished. ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the next is AITC. Sharadji will be speaking on Monday. So, you want 10 minutes for Shri Sukhendu Sekhar Roy. Okay. You have 33 minutes; you are asking to give him 10 minutes. Okay, no problem. After that, Shri Yechury will speak. Okay, no problem. Then, Mr. Navaneethakrishnan, I want your consent also.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN(TAMILNADU): It is okay, Sir.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY(WEST BENGAL): Let it be settled first.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is settled now. Now, Shri Sukhendu Sekhar Roy.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, at the outset, I would like to convey the greetings of our leader, Ms. Mamata Banerjee, to the hon. Members of Parliament. *...(Interruptions)....* मैं जो बोल रहा हूं, आप उसको सुन लीजिए। **...(व्यवधान)...** I would like to convey the greetings of our leader, Ms. Mamata Banerjee, to the hon. Members of Parliament on this solemn occasion when this great parliamentary institution is celebrating the Constitution Day and the 125th Birth Anniversary Year of the main architect of the Constitution of India and also the champion for the emancipation of the Backward Classes and the downtrodden of our country in a befitting manner.

Sir, when I look back through the eyes of my mind at the date how behind this august House, I can visualize the day, *i.e.*, 25th of November, 1949, Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar was presenting the Constitution of India to the Chairman of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. It took two years, 11 months and 17 days to finalize the Constitution, containing 395 Articles and 8 Schedules, after disposing of 273 amendments to the Constitution, which were moved. Since then, the Constitution is being amended from time to time to keep pace with the demands of the nation.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair)*

Sir, all of us know that four guiding principles of governance – justice, liberty, equality and fraternity -- were embodied in the Preamble to the Constitution. After 66 years of the adoption of the Constitution, we, as parliamentarians, must introspect how much the nation has achieved while implementing the constitutional mandate in the matters of social justice, economic justice and political justice; in the matters of liberty of thought, expressions, belief, faith and worship; in the matters of equality of status and of opportunity.

On the 25th of November, 1949, Dr. B.R. Ambedkar, while presenting the draft Constitution for adoption *inter alia* commented, and I quote: "....principles of liberty,

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

equality and fraternity are not to be treated as separate items in trinity because these are the principles of life". Hence, Dr. Ambedkar taught us that denial of liberty, equality and fraternity leads to denial of life. If we want to preach or practice some agenda against the principles of liberty, equality and fraternity for the sake of politics or for any reasons whatsoever, that would be end of the road built up by our ancestors after hundreds of years of subjugation, deprivation, intolerance and exploitation for ushering in a dignified nation, qualified to enjoy liberty, acquire equality and maintain fraternity amongst ourselves, irrespective of caste, creed, religion, sex, language or territorial boundaries. Looking at the bewildered situation prevailing today, I am sorry to say that we are still at the crossroads of 'one step forward and two steps backward', so far as tolerance and social, economic and political justices are concerned. I say so because when Articles 51A (e), (f) and (h) demand from every citizen to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, these articles, no doubt, are not mere synthesis of words, but require devoted action by all citizens towards that goal.

The hon. Leader of the House, in his eloquent speech, has mentioned about federalism and separation of powers. There is no doubt that certain pillars of our democracy are thriving for more and more authority. But authority has been given by our Constitution framers to perform certain duties effectively, not to enjoy for themselves, nor to misutilize such authority, endangering the very existence of its independent, neutral and constitutional character. It is high time that conflicts among the constitutional institutions must be avoided to desist all forms of authoritarianism.

So far as the Centre-State relations are concerned, we know that two Commissions were set up – the Sarkaria Commission and the Punchhi Commission. While some of the recommendations of the Sarkaria Commission have been implemented, the Government is sitting idle on the Punchhi Commission Report, submitted to the Government in March, 2010, and it is yet to be considered by the Government, not to speak of its implementation. I demand that if the Government is serious about co-operative federalism, it must accept the Punchhi Commission Report and implement its recommendations in letter and spirit. Sir, recently, the first citizen of India, being the Constitutional Head of the State, was first amongst us who expressed his deep concern and anguish over certain untoward incidents culminating into a sordid state of affairs, which no citizen or the functionaries of the Government can ignore. I am only referring to the statements which are in public domain. On 8th October, 2015, a Press Communique was released from

the Rashtrapati Bhavan, which referred hon. President *inter alia*, saying and I quote: "... tolerance and co-existence are basic tenets of our civilization. We hold them very dear to our hearts... We should not permit religion to be used as a mask to satisfy hunger for power and control of some individuals..."

Then, again, on 23th October, 2015, while addressing a gathering at his native place, the hon. President, referring to teachings of Lord Ramakrishna Paramahansa, said -- in Bengal it is said -- " Jato Mat Tato Path...." meaning, as there are a number of beliefs, there are a number of ways. "The Indian civilization has survived for 5,000 years because of its tolerance. It has always accepted dissent and differences. A large number of languages, 1600 dialects and 7 religions coexist in India.

We have a Constitution that accommodates all these differences." Are we listening to the first citizen of India? Have we thought as to what prompted the first citizen to advise all to be tolerant? Let us introspect.

मैं नेता प्रतिपक्ष की बात पर एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर विषय पर सभा का ध्यान आकृष्ट किया, उसी बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि in 1924 Mahatma Gandhiji appealed to all those Indians who had received awards and titles from the British rulers to give up their awards and titles. There were about 4,500 Indians who had the British titles and awards. Out of them, only a few responded to the clarion call of Gandhiji.

Today, there is no bapuji, there is no call from any quarter, no appeal from any corner, yet, more or less, 450 intellectuals comprising of scientists, writers, academicians, social activists, film personalities, journalists who had the credentials of receiving national awards have relinquished all those awards and titles to protest, in principle, the growing incidence of intolerance. Should we ignore these intellectuals and hurl abuses at them? If an actor expresses the fear and helplessness of his wife, should he become a victim of rue or hate campaign of any political outfit? Isn't it a complete madness suddenly encompassing our conscience, our culture, our legacy, or, our civilisation? Should we debate on food habits of ourselves when we are growing as a matured nation in the 21st century? If we want to respect our Constitutional ideals, if we would seriously like to pay homage to Babasaheb Ambedkar, we must introspect, as otherwise everything what has been said shall only remain to be a expression of words, meaning nothing.

Sir, this is the solemn occasion when we must recall and recapitulate the debates of eminent Indians who manned the Constituent Assembly – compared to whom we are pigmis–, particularly, Babasaheb Ambedkar, of thoughts and expressions they perceived

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

to arrive at a consensus in presenting the Constitution of India, which is unique and unparallel to all other contemporary constitutions of the world.

Sir, we must also remember the words of caution of Dr. Ambedkar and I quote: "... In India, bhakti or what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero-worship is sure road to degradation and to eventual dictatorship."

"Times are fast changing. People are getting tired of Government by the people. They are prepared to have Governments for the people and are indifferent whether it is Government of the people and by the people.

Sir, if we wish to preserve the Constitution in which we have sought to enshrine the Government of the people, for the people and by the people, let us resolve not to be tardy in the recognition of the evils that lie across our path and which induce people to prefer Government for the people to Government by the people, not to be weak in our initiative to remove them. That is the only way to serve the country. I know of no better". So said Dr. Ambedkar.

Sir, now the question is: Are we serving the country in all constitutional directions that Baba Saheb desired? Whenever I put this question to myself, pat comes the reply - "Possibly, no". Because we are still pursuing a cause to divide. We are encouraging the divisive forces in one form or the other, knowing it fully well that forces of destabilization can never contribute in any manner to the task of nation building.

Sir, this is pathetic to note that some of the responsible people have also forgotten to act responsibly and reasonably, as otherwise we would not have heard, after 40 years of incorporation of the word "Secularism" in our Constitution through 42nd Amendment, a very responsible person holding a high and important position saying 'secularism was not within the scheme of Constitution at the very beginning'. Everybody knows that. There is no denial of that. Then, he says, 'Baba Saheb did not want to include 'secularism' in the Preamble'. What is new about this? What he has not said is that Baba Saheb, while expressing freedom of religion in our Constitution, said and I quote, "The State is neither religious, nor anti-religious, nor irreligious. It is totally detached from religious dogmas".

सर, जो लोग गा रहे हैं - "हम दिल दे चुके सनम", हम उनको मजबूर न करें कि दोबारा उन्हें एक दूसरा गाना गाना पड़े - "दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या-क्या न किया, दिल दिया, दर्द लिया"।

उन पर ऐसी मजबूरी न आए कि उन्हें ऐसा गाना गाना पड़े, इस बात को हमें देखना होगा।

Sir, on this solemn occasion, my party, the All India Trinamool Congress, led by Ms. Mamata Banerjee, once again resolves to rededicate ourselves for the cause of the nation and to help strengthen all constitutional schemes, mechanisms and institutions in achieving the cherished goals of the Indian Constitution.

Sir, in fine, I would like to refer to a few lines from Tagore's Nobel Prize famed 'Song Offerings" or Geetanjali.

Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

Thank you.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Shri Sharad Yadav. ...*(Interruptions)*.... There is a certain amount of confusion. Why?

SHRI SITARAM YECHURY: He had earlier agreed that ...

MR. CHAIRMAN: Is an interchange taking place or not taking place with consent? ...*(Interruptions)*.... शरद जी, क्या आप बोलेंगे?

श्री शरद यादव (बिहार): जी हाँ, सर। महोदय, आज का दिन संविधान की बाबत और उसकी याद में आपने रखा है, जिस पर हमारे बहुत से मित्रों ने बोला है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि देश में 68 वर्षों में हमारे संविधान के दायरे में जो अच्छा और बुरा हुआ, उसके ऊपर लोगों ने बहुत विस्तार से यहाँ बोला है, लेकिन इसके नतीजे क्या निकले? हम आज कहाँ खड़े हैं? आज का दिन इस बात को भी तोलने का है, आत्म आलोचना का है कि हम खड़े कहाँ हैं? मैं मानता हूँ कि देश आज़ाद हुआ, उसके बाद के जो हालात हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग ...**(व्यवधान)**... मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का आशय यह है कि अगर देश की geography को, देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो पायेंगे कि एक साइज़ेबल आबादी है, जो आगे बढ़ी है। उसकी भी एक संख्या है। मैं मानता हूँ कि बरतानिया और यूरोप के छोटे-मोटे देशों के लगभग 25-30 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहतर बनी है।

[श्री शरद यादव]

जिस तरह आदमी का शरीर है, वैसे ही राष्ट्र का भी शरीर होता है। राष्ट्र का जो शरीर है, मान लीजिए कि यदि उसमें एक जगह पर भी कमजोरी आ जाये, तो टोटैलिटी में जो शरीर है, उस पर असर पड़ता है। वैसे ही जो पूरा भारत देश है, उसके शरीर को भी देखना चाहिए। इस देश के गरीब की क्या हालत है, इस देश के बेकार और बेरोज़गार लोगों की क्या हालत है? जो भाषायी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वे कन्नड़ के हों, मलयालम के हों या गुजराती के हों, जो भारतीय भाषायें हैं, उनमें से किसी भी भाषा को ले लीजिए, उनके द्वारा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आज सबसे बड़ी समस्या यह हो गयी है कि आप तो कहते हैं कि पढ़िए, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं और वह भी भाषायी स्कूलों में जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी हालत यह है कि वे बेकारी और बेरोज़गारी के समुद्र में तैर रहे हैं। यही हालत इस देश के किसान की है। वह कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है? 68 वर्षों में संविधान के दायरे में जो काम किये गये, उनके नतीजे में कुछ जगहें तो ऐसी हो गयीं कि आप उनकी तुलना किसी बड़े विकसित देश से कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी नहीं हैं। यही दिल्ली है, यहाँ 21वीं शताब्दी है, जहाँ हम और आप बैठे हैं, लेकिन थोड़ा यमुना के पार चले जाइए, तो यमुना को पार करने के बाद 19वीं शताब्दी आ जायेगी, थोड़ा और आगे चले जाइए तो 18वीं शताब्दी आ जायेगी, इसके थोड़ा और आगे झुग्गी-झोंपड़ियों में चले जाइए, तो 17वीं शताब्दी आ जायेगी। यह दिल्ली भी शताब्दियों में खंड-खंड है। संविधान के जो दायरे थे, उनमें गलती क्या हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इसके नतीजे में इस देश की जो हालत है, इसकी जो शक्ल है, वह बहुत भयावह है। वह इतनी भयावह है कि चाहे जो अपनी पीठ थपथपा लो और मैं यह कह रहा हूं तो किसी के ऊपर आरोप लगा कर नहीं कह रहा हूं। यह जो बात मैं कह रहा हूं, वह इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, संविधान के दायरे में, संविधान के अनुसार मोटा-मोटा हम चले हैं। लेकिन देश जो है, वह तभी मजबूत होगा, जब देश के पूरे के पूरे शरीर को हरसम्भव ताकत मिलेगी। जब आप बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो मैंने गरीब के बारे में कहा, बेकारी के बारे में कहा, इस देश के किसानों ने सदियों में कभी आत्म-हत्या नहीं की। बाजार जब से आया तब से आत्म-हत्या शुरू हुई है। मैं नहीं कह रहा कि बाजार नहीं आना चाहिए। बाजार चीन में भी आया है लेकिन जब चीन में बाजार आया तो चीन ने हाथ मिलाया और बाजार के ऊपर, उसकी छाती पर बैठकर दिखाया। एक हम हैं जो यह बाजार आया है, इस बाजार के चलते भारत का जो गरीब आदमी है, वही मैंने कहा कि 25 करोड़ लोग ही इसका भोग कर रहे हैं। उन्हीं का जिक्र है, उन्हीं के बीच बहस है। आज की बहस का भी, तमाम तरह की जो बहस हुई, उसका एक ही दायरा है कि संविधान कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन है, उनकी यशगाथा हमने गाई, लेकिन उनके सपने क्या थे? बाबा साहेब अम्बेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। वहां महात्मा गांधी भी उसी गोलमेज सम्मेलन में थे। भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी और मजबूरी और हिन्दुस्तान का जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसके ऊपर उन्होंने जो ललकार लगाई तो पूरे सेकंड गोलमेज कांफ्रेंस में महात्मा जी का मन तब से बदला। वे समझते थे कि जाति व्यवस्था ठीक है, लेकिन सेकंड गोलमेज कांफ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिन्दुस्तान के सारी धार्मिक और सब चीजें बताई। तो यह भी जान लेना कि भारत का सम्पूर्ण विकास और सम्पूर्ण ताकत जो उसकी है, वह हिन्दू है, और यदि हिन्दू है तो वह कोई हिन्दू नहीं है, वह कास्ट सिस्टम है और जाति व्यवस्था अकेले हिन्दू में नहीं है, मुसलमानों में भी वैसी ही है, सिखों में भी वैसी ही है, ईसाइयों में भी वैसी ही है। हिन्दुस्तान में धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदली जा सकती। इसके बाद जब एक गोष्ठी की गई तो उसमें बाबा साहेब ने बोलने का काम किया और उसके बाद महात्मा गांधी को जब बोलने को

कहा तो उन्होंने सिर्फ यह कहा, थैंक्यू वेरी मच। इससे ज्यादा नहीं बोले। उसके बाद ही महात्मा जी का मन बदला।

सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक मामूली चीज नहीं है। दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस के बाद हिन्दुस्तान की तस्वीर और हिन्दुस्तान की सब चीजों की बीमारी का, जो सबसे बड़ी बीमारी है, उसका पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट क्या कहता है? पूना पैक्ट महात्मा जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में हुआ था। उसमें हिन्दुस्तान की जो सामाजिक विषमता है, जो जाति व्यवस्था है, उसकी बाबत ही समझौता हुआ था कि हिन्दुस्तान का जो दलित है उसकी क्या जगह होगी, हिन्दुस्तान का जो ट्राइबल है उसकी क्या जगह होगी? उस पूना पैक्ट में हिन्दुस्तान की आजादी के जितने लोग थे, उनके सबके दस्तखत थे। अकेले बंगाल के लोग दस्तखत करने के बाद जाकर बदल गए थे लेकिन बाकी पूरा देश, मदन मोहन मालवीय से लेकर, सरदार पटेल से लेकर सारे लोगों के दस्तखत पूना पैक्ट पर थे। सभापति जी, यह भी जान लीजिए कि पूना पैक्ट के चलते ही महात्मा जी के मन में आया कि यह जो पैक्ट हुआ है, देश बंट रहा था, उनको दिख रहा था लेकिन हिन्दुस्तान का जो दलित है, वह कह रहा था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हमारे साथ किसी को मत रखो। हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था ऐसी है कि हमको अलग से, हमारे लोगों को हमारे लोग ही वोट दें, उनको आगे लाओ।मैं मानता हूँ कि बाबा साहेब की राय ठीक थी। आज मैं देखता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में, सारी पार्टियों में जो दलित हैं, उनकी ज़बान बंद है। कोई भी दर्द के साथ बोल नहीं सकता है। आज इस सदन में इस देश की जो हालत है, उसके दर्द को ... सदन चलता है तब भी, चाहे इस पार्टी में दलित नेता हो, चाहे उस पार्टी में आदिवासी नेता हो, यहां रहता हो या वहां रहता हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि उसके मन में जो तकलीफ है, उसको वह कह सके। इसलिए मैं यहां कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ठीक बात कर रहे थे। पार्टी सिस्टम के चलते यह हालत हो गई कि दलित जो है, वह पार्टियों का बंधक हो गया है। वह अपने वर्गों के हक में बोल नहीं सकता है। वैसे वह सीधा है।

सभापति जी, उसका एक तरह का शोषण नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर का, उसके मन का, उसकी बुद्धि का, उसके विवेक का शोषण हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, जिसमें यह जो जाति व्यवस्था है, यहां उसके शोषण की इन्तिहा है। उनका सिर्फ मानसिक शोषण नहीं, आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि शरीर से लेकर हर चीज का शोषण हो गया। हजारों वर्ष से उसकी बोली बंद हो गई। न खेत बोलता, न खलिहान बोलता, न पशु बोलता, न पक्षी बोलता, उसकी ज़बान बंद रहती है। यहां भी उसकी ज़बान बाबा साहेब ने खोलने का काम किया था, लेकिन वह नहीं हो पाई। आज हालत क्या है? क्या हुआ दलित का?

कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब यहां से नहीं गए। बाबा साहेब से पहले भी हिन्दुस्तान में बहुत लोग हुए, जैसे महात्मा फुले, साहू महाराज, डा. लोहिया, गुरु नानक, आदि। हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था के खिलाफ जितना भारत के इतिहास में संग्राम हुआ है, बसबन्ना को रगेद करके, खदेड़ करके नदी के बीच में उसको डुबोने का काम हुआ। हिन्दुस्तान की सामाजिक विषमता के खिलाफ जो संग्राम हुआ, उस संग्राम को ठीक करने के लिए महात्मा गांधी ने किसी एक आदमी का नाम सुझाया, उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर था। संविधान बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसका चेयरमैन बाबा साहेब को क्यों बनाया? "हिन्दुस्तान", हिन्दी के चन्दूलाल चंद्राकर थे, महात्मा जी के मन में था कि इनको हिन्दुस्तान का लॉ मिनिस्टर बनना चाहिए। इनको कानून मंत्री बनना चाहिए और

[श्री शरद यादव]

संविधान सभा में संविधान का पूरा का पूरा ढांचा इनके द्वारा तैयार होना चाहिए। महात्मा जी ने दो लोगों का नाम दिया था - एक बाबा साहेब अम्बेडकर का और एक इनके अध्यक्ष थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने बाबा साहेब का नाम इसलिए दिया था, क्योंकि हिन्दुस्तान में जो 'पूना पैक्ट' किया, उसको incorporate करने का काम कोई आदमी करेगा, तो उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर है। जिसने जिंदगी भर दर्द से, तकलीफ से इस विषमता के खिलाफ संग्राम किया और किसी के सामने नहीं झुका, उसने जो संविधान बनाया, उसकी हालत आज क्या है? यहां आर्थिक विषमता के बारे में तो बहुत चर्चा होती है, गरीबी के बारे में बहुत चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक पहिए पर गाड़ी नहीं चलती है। सभापति जी, हम सिर्फ आर्थिक विषमता के मामले में दिन-रात जूझते रहे हैं, लेकिन आर्थिक विषमता मिटी नहीं है। आर्थिक विषमता कभी मिटी नहीं, हिन्दुस्तान के 80 फीसदी आदमी का मन मरा हुआ है और वह मरा हुआ इसलिए है, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में यह बताया है कि कैसे जाति व्यवस्था खत्म होगी। इसको बताने में समय लगेगा, मैं पढ़ कर बताता हूँ। उनका एक ही मकसद था और वह था to eradicate the caste system. जो उन्होंने विशेष अवसर का सिद्धांत लगाया, वह एक संभव कदम था। संभव कदम नहीं उठा सकते थे, लेकिन क्या हुआ? आज भी जाति बनी हुई है और जाति के आधार पर जो 80 फीसदी लोग हैं, उनको जो आरक्षण मिला हुआ है, विशेष अवसर का मौका मिला हुआ है, उस विशेष अवसर के मौके के सिलसिले में आपने इस संविधान के दायरे में क्या किया? सदन के चारों तरफ के लोग, आप जरा मन को ठीक करके रखिए, क्योंकि 80 फीसदी लोगों को विकलांग करके देश मजबूत नहीं हो सकता है।आप दुनिया में बड़ी शान से कहते हैं कि देश आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप यह गलत बोलते हैं। जो देश अपने 80 प्रतिशत लोगों को लूला और लंगड़ा रखेगा, लाचार और बेबस रखेगा, वह मुल्क दुनिया में कभी भी हैसियत और इज्जत नहीं पा सकता।

मान्यवर, आज हमारे देश की हालत यह है कि आप दुनिया में चारों तरफ कटोरा लेकर घूम रहे हैं। हम दुनिया में चारों तरफ कटोरा लेकर घूम रहे हैं और यह आज ही नहीं, बल्कि 68 वर्ष से हो रहा है। हम कभी रूस की तरफ जाते हैं और कभी अमरीका की तरफ जाते हैं। हमें जो राह महात्मा गांधी जी ने दिखाई थी, जो राह हमें संविधान ने दिखाई थी, हम कभी भी उस राह पर नहीं चले। हमने हिन्दुस्तान के 80 फीसदी लोगों को मजबूत नहीं किया। हमने कभी देश के किसान, मजदूर, पिछड़े, आदिवासी और दलितों को मजबूत नहीं किया।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा लाचार, बेबस, सबसे ज्यादा पीछे यदि कोई इंसान है, तो वह हिन्दुस्तान का आदिवासी है। उसका कोई नेता नहीं है। उसकी कोई आवाज नहीं है। जब वह सदन में आता है, तो पार्टियों की दहशत से उसकी जुबान नहीं खुलती, क्योंकि पार्टी पैसा देती है, पार्टी टिकट देती है और पार्टी उसका चुनाव लड़ती है।

महोदय, जो पूना पैक्ट था, वह अच्छी नीयत से बनाया गया था, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि उसे बनाने वाले दोनों बड़े लोग थे, लेकिन वह नीयत और जो इस देश का सिस्टम है, जो इसकी व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं, तो मेरा मतलब कास्ट सिस्टम से है।

इस देश की जितनी 64 मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें बताइए कौन दलित जाति का सैक्रेट्री है? यहां से नेता सदन भी चले गए और प्रधान मंत्री जी भी मौजूद नहीं हैं। आज उन्हें यहां बैठना चाहिए था, क्योंकि जो सच है, वह कभी-कभी निकलता है। भारत के जितने भी मंत्रालय 64 या 70 हैं, उनमें बताइए, किसी भी मिनिस्ट्री में एक भी दलित सैक्रेट्री है? आज 68 वर्ष के बाद भी ऐसी स्थिति है कि कोई भी दलित सैक्रेट्री भारत सरकार की किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं है। एक बार उत्तर प्रदेश के एक श्री माता प्रसाद, भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री में सैक्रेट्री बने थे। आज पिछड़ी जाति का एक भी सैक्रेट्री नहीं है। देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों में दलित जाति का एक भी सैक्रेट्री नहीं है। हां, इस बार एक सैक्रेट्री बना है। मैं जानता हूं कि एक सैक्रेट्री इस बार बना है।

महोदय, आज यहां लोहिया नहीं हैं, मधु लिमये नहीं हैं और मधु दंडवते नहीं हैं। इसलिए मुझे यह कहते हुए तकलीफ हो रही है कि यदि आप में से कोई आदमी यहां इनके बारे में बोल रहा होता, तो मैं यहां बोलने के लिए खड़ा नहीं होता। मैंने हिन्दुस्तान के हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कोई 'मीसा' में दो वर्ष जेल में रहने की बात करता है, लेकिन मैं हिन्दुस्तान की जेल में चार वर्ष रहा हूं। मैंने हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट से दो बार इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे तकलीफ है कि आज यहां मधु लिमये नहीं हैं और लोहिया नहीं हैं। मैं यहां आज खड़ा हूं, तो डा. राम मनोहर लोहिया जी के कारण खड़ा हूं। क्या हुआ इस सामाजिक विषमता को?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं और आप से भी कहना चाहता हूं कि जो सामाजिक विषमता है, वही सारी चीजों की जननी है। वही सारे गुनाहों की जननी है। उसी के कारण सारी विषमता, उसी के कारण सारा अन्याय, उसी के कारण सारा जुल्म और उसी के कारण सारा शोषण होता है। देश की गाड़ी का एक पहिया सामाजिक विषमता, दलितों की आजादी और आर्थिक विषमता का है। उसमें बोली की आजादी सब कुछ है, लेकिन सब से ज्यादा उसकी आत्मा आर्थिक और सामाजिक विषमता के कारण दुखी है। इस देश में जो सिर्फ आर्थिक विषमता की बात चलती है, वह गलत है।

महोदय, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता की बेटी है। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता की बेटी है। आप जाति का ग्राफ खींच लें, ऊंची जाति से नीचे चलते आएं, जैसे-जैसे ऊपर से नीचे चलते जाएंगे, वैसे-वैसे गरीबी बढ़ती जाएगी।

महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफ सफाई कर्मचारियों की है। आप कहते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है। इसी पार्लियामेंट के भीतर, जो सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें कितनी तनख्वाह मिल रही है, जरा पता लगाइए। आपने उन्हें कांट्रैक्ट लेबर के रूप में रखा हुआ है। यहां एक सफाई कर्मचारी को केवल रु.7,500/-मिलते हैं। आप कहते हैं कि भारत को 'स्वच्छ भारत' बनाएंगे। आप यहां रोजाना वॉश-रूम में जाते हैं। जरा आप पता लगाना कि उन्हें कितने रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं? यानी, हिन्दुस्तान का जो सबसे ज्यादा लाचार और बेबस आदमी है, जो मां का काम करता है, वह सिर्फ पेट के काम को छोड़कर बाकी माता के जितने भी काम हैं, उन सभी कामों को करता है। वह इस देश का बाल्मीकि समाज है। वे सब के सब कितने रुपए में भर्ती हैं? आपके यहां कितने रुपए में भर्ती हैं? महोदय, आप भी बैठे हैं और वहां पर भी मैडम बैठी हैं, आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। आप सफाई की बात करते हैं! मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया कि यह पाखंडी देश है, पाखंड से भरा हुआ है। हिन्दुस्तान में आपने जो

[श्री शरद यादव]

आरक्षण लगाया, 68 बरस में उस आरक्षण की क्या हालत हुई? भारत सरकार के 62 डिपार्टमेंट्स हैं – ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 65,414 employees हैं जिनमें से शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को 7,890 पद मिले जो कि 12.06 परसेंट है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स को 3,324 मिले, जो कि 5.08 परसेंट है और ओबीसी को 5,477 मिले, जो कि 8.37 परसेंट है। यह आंकड़ा है, आउट ऑफ 27 परसेंट। तो 68 बरस में यह हालत है। आदिवासियों का ढाई फीसदी बैकलॉग है। शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को 15 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए, उनका 3 परसेंट बैकलॉग है। उन्हें 12 परसेंट मिला और तीन फीसदी अभी भी उनके पेट का कटा हुआ है। आप क्या बात करते हैं? आप संविधान की बात करते हैं? संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना मत इसी बात के लिए दिया था? महात्मा गांधी जी का पूरा का पूरा पढ़ लो। उनको जो संविधान बनाने का जिम्मा दिया गया था, उसके पीछे हिन्दुस्तान की जाति व्यवस्था और विषमता को तोड़ने की उनकी मंशा थी, उनका सपना था। उस सपने का क्या हुआ? अब ग्रुप बी देखिए। जब ग्रुप बी आएगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। ग्रुप बी में 1,41,305 में से शैड्यूल्ड कास्ट्स को 22,233 पद मिले, जो कि 15.73 परसेंट है। इस प्रकार परसेंटेज बढ़ गया, कोटा पूरा हो गया। अब मैं आपको ग्रुप सी के बारे में बताना चाहता हूं, जो 17.53 परसेंट है। इस प्रकार जब ग्रुप सी आया तो कोटा पूरा हो गया। चपरासी बनना है, बन जाओ, क्लर्क बनना है, बन जाओ, बाबू बनना है, बन जाओ लेकिन कलेक्टर या एसपी मत बनो, उसमें बैकलॉग रहेगा। यह व्यवस्था है, यह सिस्टम है। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया है कि केवल एक सेक्रेटरी है। यहां पर पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हैं। नक़वी साहब समझ रहे हैं कि फालतू चीज़ चल रही है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप बताइए कि जो मैंने कहा कि बैकलॉग है और जो मैंने कहा कि एक भी मिनिस्ट्री में दलित सेक्रेटरी नहीं है...(**व्यवधान**)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : सभापति महोदय, माननीय शरद जी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। जो उन्होंने कहा, उसके बारे में जो factual position है, उसकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं कि चार एससी, एसटी से संबंधित सचिव हमारी सरकार के समय में रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनके नाम भी दे देता हूं।

श्री सीताराम येचुरी : यह सब जरूरी नहीं है।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको उसके पहले की कोई जानकारी हो। हमारे समय में चार एससी, एसटी से संबंधित माननीय सचिव हैं।...(**व्यवधान**)... दूसरी चीज़ सचिव या इस तरह के प्रशासनिक पदों पर लोक जिम्मेदारी और उनकी ...(**व्यवधान**)... योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती है।...(**व्यवधान**)... अगर आपको नाम चाहिए तो मैं नाम भी बता दूंगा।

श्री सभापति : आप उन्हें नाम दे दीजिएगा।

श्री शरद यादव : वे साउथ के लोग होंगे।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : वे साउथ के नहीं हैं। देवेन्द्र चौधरी उत्तर प्रदेश के हैं, वे प्रशासनिक सुधार के सचिव हैं। सुरजीत सिंह चौधरी टेक्सटाइल के सचिव थे, अभी 15 दिन पहले शायद रिटायर हुए हैं। श्री पी.डी.मीणा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर के सचिव हैं।

श्री शरद यादव : ये आप ट्राइबल के बता रहे हैं।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : ट्राइबल के नहीं हैं। मैंने आपको इससे पहले सारे एससी बताए।...(**व्यवधान**)... मैं इसमें कोई विवाद नहीं कर रहा हूं हो सकता है कि आपको कहीं से जो फीडबैक मिला हो, वह सही न हो।

श्री शरद यादवः उपसभापति जी, मैं यह कह रहा हूं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में तो पूरा कोटा हो गया, लेकिन जो मैं कह रहा था कि सेक्रेटरी, जहां से सिस्टम चलता है, उसके बारे में फिर से आप पता लगा लीजिए। जो आपने मीणा नाम लिया है, लेकिन मीणा को छोड़कर हिन्दुस्तान के दस करोड़ आदिवासी हैं, उसका एक सेक्रेटरी यहां नहीं है और केबिनेट सेक्रेटरी की बात तो छोड़ दीजिए, वह तो कभी नहीं बनेगा।

उपसभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो सामाजिक विषमता थी, उस सामाजिक विषमता के जो बने हुए लोग हैं, जो लोग सदियों से पिछड़ रहे हैं, आप सोचते हैं कि देश आगे बढ़ जाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वे ही उत्पादन करने वाले लोग हैं, वे ही मेहनत करने वाले लोग हैं, वे ही सम्पत्ति पैदा करने वाले लोग हैं और उनको ही आपने हक देने में इतनी कोताही की है कि आपको नम्बर बताना पड़ रहा है। उनकी आबादी 80 फीसदी है और आप उनका हिस्सा एक-दो नाम का बता रहे हैं। आप बैकवर्ड क्लास का भी पता लगा लेना, जो आधी आबादी से ज्यादा है, उनका सेक्रेटरी भारत सरकार में कितनी बार बना, यह भी पता लगा लेना।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) : मैं आपसे माफी चाहती हूं, आप बड़े हैं, लेकिन सेक्रेटरी देश के हैं।

श्री शरद यादवः आप तो बड़ी होशियार हैं। आप बहुत होशियार हैं।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानीः मुझे पता है कि मैं होशियार हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करती हूं कि सेक्रेटरी पूरे देश के हैं।

श्री शरद यादवः मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन आप मेरी बात समझेंगी नहीं। मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान पूरी तरह से कई अंतर्विरोधों से, कई विषमताओं से भरा हुआ है, उस विषमता के पीछे कोई और कारण है और कोई एक बात है तो यह जाति व्यवस्था है। इसके बारे में हमें जितना रिजर्वेशन और अफरमेटिव एक्शन करना था, उतना अफरमेटिव एक्शन हमने 68 वर्ष में नहीं किया है। आप अकेले एक आईएएस और आईपीएस का उदाहरण दे रहे हो, लेकिन बैंक है, यूनिवर्सिटी है, एम्स है, यहां एक दलित महिला एक जनरल सीट पर जीत गई, डॉक्टर बन गई, आज भी वह बाहर बैठी है। एस.सी. कमीशन के चेयरमैन पुनिया जी यहां पर बैठे हैं, ये जब बोलेंगे तो बताएंगे कि कदम-कदम पर यदि अन्याय नहीं होता, जुल्म नहीं होता तो इतना बड़ा समाज आगे बढ़ता, परन्तु पूरा समाज इसलिए आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि इस जाति व्यवस्था के बारे में हमने कोई बहस नहीं की। इसके ऊपर हमें

[श्री शरद यादव]

4.00 P.M.

बहस करनी चाहिए। सबसे ज्यादा युद्ध, सबसे ज्यादा संग्राम यदि कोई हुआ है, तो जाति व्यवस्था के eradication पर हुआ है, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ है। अभी भी हमारा जो रिजर्वेशन है, वह 49.5 परसेंट है। जो लड़का अंतर्जातीय शादी कर रहा है, उसके लिए हम पूरे देश में आज तक इंतजाम नहीं कर पाए कि जो अंतर्जातीय शादी कर रहा है, वह देश का महान काम कर रहा है। उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सरकार को उसे हर जगह नौकरी देनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जाति व्यवस्था का राक्षस है, इस राक्षस से बहुत से लोगों को फायदा है, बहुत से लोगों को नुकसान है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान बनाने वालों ने जो सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया था, उसमें एक आर्थिक सवाल पर हम जरूर जूझते रहे हैं, लेकिन सामाजिक विषमता के बारे में हमने कोई काम और कोई ऐसी चीज़ नहीं की, जिससे कि यह देश आगे बढ़ सके।

यह देश एक पहिए पर नहीं चलेगा, एक पक्षी एक पंख पर नहीं चलेगा। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी और सामाजिक विषमता है। ये दोनों जुड़े हुए सवाल हैं, इन दोनों जुड़े हुए सवालों को हल करने का एक भी प्रयास ईमानदारी से नहीं हुआ। सच्चाई से इसके बारे में कोई प्रयास नहीं हुआ। अगर सच्चाई से प्रयास हुआ होता, तो आज हिन्दुस्तान का 80 फीसदी आदमी विकलांग नहीं होता, लाचार और बेबस नहीं होता। वह हर तरह से पीछे है, वह हर तरह के मामले में पीछे है। यह व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं।

इस संविधान का मतलब यह है कि यह व्यवस्था सब लोगों द्वारा चलाई जाए, सब लोग मजबूत और ताकतवर हों। महोदय, हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था के बारे में आप दो दिन की बहस रखिए। इस सदन में बहुत से लोग हैं, जो कि इस की गंभीरता के बारे में नहीं जानते। यह ऐसी बीमारी है, जो दुनिया में सिर्फ इसी देश में पाई जाती है और इस बीमारी के चलते हमारे देश का जितना विकास होना चाहिए था, देश जितना आगे बढ़ना चाहिए था, उतना आगे नहीं बढ़ पाया । महोदय, इस के पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम लोगों ने सिर्फ economic disparity को लेकर कार्यक्रम बनाए हैं। इस बीमारी को हम हमेशा ignore करते रहे और इसलिए हमारा देश जितना मजबूत और ताकतवर होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे पहले किसी ने इस बात को नहीं उठाया है, इसलिए मैंने इस बात को बहुत वेदना के साथ उठाया है। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को जो जिम्मा दिया गया था, वह इसलिए दिया गया था कि देश के सब से ज्यादा छोटे और सब से ज्यादा निचले तबके, छोटी जाति व वीकर सेक्शन के लोगों की जिंदगी कैसे ठीक होगी, कैसी संवरेगी, उन्हें बनाने का देश का यही मकसद था। उसमें बाकी सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन वे बड़े लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की इस बीमारी को पहचानकर, इस विषमता के संबंध में एक बड़ा प्रावधान किया था। महोदय, वह प्रावधान आज लागू नहीं होता है। मैंने यहां आईएएस/आईपीएस की बड़ी नौकरियों का जिक्र किया, लेकिन आज न उन लोगों को बैंक्स में नौकरी करने का हक मिलता है और न उन्हें एजुकेशन में हक मिलता है। महोदय, आज सुप्रीम कोर्ट की

नौकरियों में भी रिजर्वेशन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट यहां के बनाए हुए कानूनों को रोकता है, वही सब से ज्यादा social justice को बढ़ाने के काम में रुकावट डालता है। इसलिए इस संविधान पर चर्चा के दौरान यदि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने इस चर्चा को छेड़ा।

उपसभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Okay. Navaneethaji, after all, we all are comrades. We may belong to different parties. I leave it to you. I will not enforce anything. But if one Member requests that he has an early flight, accommodating him is a practice of the House. ...*(Interruptions)*.... Then, you do what you want to do. ...*(Interruptions)*.... That is a practice. After all, we all are comrades, this side or that side. ...*(Interruptions)*....

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please use some other word.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are allergic to the word 'comrade'.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please use some other word like 'colleague'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You give me a better word. I am not a master of English. ...*(Interruptions)*.... So, don't you concede for Mr. Yechury? He wants to go. ...*(Interruptions)*.... I can use my discretion, but I am not using that. I only want to do it with your consent. I can use my discretion. I am not doing that.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN(Tamil Nadu): Sir, I will be in trouble. ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is advising you. ...*(Interruptions)*.... You will be in trouble! ...*(Interruptions)*.... My God! ...*(Interruptions)*.... What can I do? ...*(Interruptions)*.... I can use my discretion which I am not using. Okay. It is up to you. I said that I am not enforcing and it is up to you. Okay. Please do not take too much time.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Thank you, Sir. At the outset, I would thank my revered leader, Puratchi Thalaivi Amma, for giving me this opportunity to stand before this august gathering for the discussion on "the Commitment to India's Constitution as part of 125th Birth Anniversary Celebration of Dr. B.R. Ambedkar". It is very fitting that 26th November every year is proposed to be celebrated as Constitution Day, marking the anniversary of the day on which, in 1949, the Constituent Assembly adopted the Constitution of India. This occasion also gives us an opportunity to remember and revere the memory of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar who, as Chairman of the Drafting Committee, played the greatest role in giving to the nation our founding charter. The Constitution of India is widely recognised as a very progressive document

[Shri A. Navaneethakrishnan]

which established in what was, at that time, a poor, largely illiterate country, a modern democracy. It has also accommodated a wide range of diversity in terms of region, religion, language, socio-economic status, aspiration and political opinion. Inclusiveness was a major attribute of the Indian Constitution. This robust founding charter for India has stood the test of time. It has fostered institutions. Whereas many newly independent countries and nations floundered into authoritarianism and anarchy; the Constitution was the bedrock that enabled India to integrate and bound the nation together.

The Constitution of India's greatest success lies in the fact that it has provided the latitude for diversity. It has provided the space for aspiration. And it has been flexible enough to be amended whenever the need was felt. The judiciary has also played its part in interpreting various provisions of the Constitution in a constructive, creative and progressive manner. It has indeed been a living document and we, as citizens of this country, have every right to be justifiably proud of the manner in which we have worked the Constitution.

For Tamil Nadu, located as it is at the southern tip of the Indian peninsula, with a hoary and distinct cultural and linguistic tradition, it is this inclusivity and scope for giving expression to local aspirations which has led to all shades of responsible political opinion in the State to have the highest respect for and faith in the Constitution of India and the institutions created under it, including the Legislature, the Judiciary, the Finance Commission, Election Commission of India, C&AG and the Union Public Service Commission to name a few.

As we observe the 125th Birth Anniversary of Bharat Ratna B.R. Ambedkar, we cannot but highlight the emphasis on social justice which he imbued the Constitution of India with. Article 15 (4) provides for the State to make special provisions for the advancement of the socially and educationally backward classes of citizens or for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Article 15 (5) specifically provides for special provisions for such disadvantaged groups in admissions to educational institutions. Similarly, Article 16 (4) permits the State to make special provisions for reservation in public employment for any backward class of citizens which is not adequately represented.

The State of Tamil Nadu, has been a forerunner in the area of social justice and affirmative action and the policy of reservation has been in vogue since 1927. The quantum of reservation in educational institutions and in public employment for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes was increased from 49 per cent to 68 per cent in 1980. In 1990, the High Court of Madras ordered for providing a separate quota of one per cent for Scheduled Tribes increasing the total reservation to 69 per cent.

In the Indira Sawhney *Vs*. Union of India (Mandal cases) the hon. Supreme Court ordered that the quantum of reservation should not ordinarily exceed 50 per cent; if at all the quantum of reservation has to exceed 50 per cent, the State has to make out a special case showing the extenuating circumstances. Further, the creamy layer from amongst the backward classes should be identified and excluded and a permanent mechanism in the form of Committee/Commission should be established by the State to review the lists of Backward Classes. Tamil Nadu had constituted a Backward Classes Commission.

For a State where 87 per cent of the population belong to socially and educationally backward classes, for whom reservation of 69 per cent had been extended for a number of years, the hon. Supreme Court's orders staying reservation exceeding 50 per cent had created a huge social crisis in the State. As a progressive measure to secure social justice and to protect the quantum of reservation already prevailing in the State, my revered leader, Puratchi Thalaivi Amma, who was then the hon. Chief Minister of Tamil Nadu brought before the Tamil Nadu Legislative Assembly the Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of seats in Educational Institutions and Appointments or Posts in the Services under the State) Bill, 1993, to preserve and maintain 69 per cent reservation. The assent of the President of India was obtained on 19.7.1994. The Act was placed in the Ninth Schedule of the Constitution by the Constitution (76th Amendment) Act, 1994, on 31.8.1994.The Government of Tamil Nadu has continued to stoutly defend its stance on reservation before the Supreme Court of India against several legal challenges and has effectively secured social justice for the people of the State to this day. All this has been possible due to the exceptional and brilliant efforts undertaken by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma. To us, in Tamil Nadu, so far as the features of the Indian Constitution are concerned, we cherish most of those which imbibe the spirit of federalism. Autonomy of the States and federal structure of the Centre has been the firm credo of successive governments in Tamil Nadu. The present Government in Tamil Nadu under the leadership of hon. Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma, has been a strong defender of the federal spirit in every sphere of State action and governance, that is, legislative, judicial, administrative and above all, in fiscal matters. The position that Tamil Nadu, under the leadership of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, has taken on a number of proposed Central legislations, namely, the National Security Act, the new Land Acquisition Bill, the National Judicial Appointments Bill, and the Road Safety Bill, to name just a few such legislations, is based, primarily, on the principle that the federal features of the Constitution of India require to be protected and preserved against recurrent attempts to encroach on them. Even in the administrative sphere, my revered leader and the hon.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

Chief Minister of Tamil Nadu, has emphasized that the maintenance of internal security in the country is an exercise that requires functional cooperation and understanding between the Central Government and State Governments and pre-supposes relationship based on equality. The States are equal partners with the Centre in protecting the nation from internal strife. My revered leader strongly opposed the erstwhile UPA Government's attempts at increasingly taking unilateral steps and creating top-down sections and parallel authorities that encroached upon constitutional domain of the State Government. This ill-informed and counter-productive approach of the UPA Government was best illustrated by the ham-handed manner in which the National Counter Terrorism Centre was sought to be established. My revered leader fiercely opposed this assault on State autonomy and the federal structure of governance in this country and her opposition was instrumental in ensuring that such a mechanism was not created. My revered leader correctly observed that in a federal democracy like ours, democratically elected State Governments are as interested in the territorial integrity and unity of the country as the Union Government. In that context, terrorism is threatening to become a global threat which affects India as well. To protect federalism inherent in the Constitution, the Government of India should seek the active cooperation of all the State Governments as its equal partners in our fight against the common enemy. The Government of Tamil Nadu, under the leadership of Puratchi Thalaivi Amma, has held a consistent and principled stance on the defence of the State's autonomy even in the context of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition (Rehabilitation and Resettlement) Bill. Right from the time that the previous UPA Government introduced the Bill, based on the twin tenets of the need to preserve State autonomy within our federal structure and to protect the interests of the agriculture and of our farmers, we had pointed out that the Government of India, in replacing the colonial era Land Acquisition Act, 1894, with the Land Acquisition (Rehabilitation and Resettlement) Bill, 2011, is exceeding its legislative competence under the Constitution of India and extending to the legislative competence of State Governments. Land is a state subject under Entry 8 of List II of the Seventh Schedule. States are much closer to the people and hence the Constitution-makers logically provided for the State Governments to deal with matters connected with land. Even administratively, all records and related matters are dealt with by State Government authorities. Hence, it would be appropriate for the field to have been left to States to legislate. Fiscal federalism is another key element of India's Constitutional framework. The makers of our Constitution recognized that for reasons of administrative efficiency and convenience, more taxation powers had

to be vested with the Central Government, while the responsibilities for actual delivery of many resource-intensive public services like maintenance of public order, public health, agriculture, education to name just a few, were logically vested with the States, since that was the appropriate delivery level. This arrangement was no doubt occasioned by many considerations which were valid when the country had just become independent, namely, the overall level of economic development of the country, the wide variation in the sophistication of administrative institutions found in different States and regions of the country, and above all the political situation at that time. The scars of the traumatic partition of the country were still fresh. The memory of the herculean efforts that had to be undertaken to integrate the erstwhile princely States into the Indian Union and consolidate the nation were too recent and democracy in the country too nascent.

Over the last 65 years since we adopted our Constitution, the scenario has changed considerably and for the better. India is now a confident nation and a mature democracy. Undoubtedly economic challenges remain, but those are of a different order—not those of overcoming food scarcity and starvation or of overcoming the handicaps created by a few centuries of colonial rule including a highly skewed pattern of industrialization and the absence of a modern industrial base.

Over the last two and half decades in particular, we have also seen a steady shift in real political and economic power away from the Centre. The political parties in States and political leaders at the State level are becoming much more important players. These should not be seen as centrifugal or fissiparous forces that have to be curbed, but as a manifestation of India's maturing as a nation and as a democracy – after all it would be strong States that will make a strong nation.

The resource needs of the States have increased significantly. More importantly, State Government, which are engaged in the direct provision of many of these services have also demonstrated their greater efficiency and effectiveness in the delivery of such services. But in a context where the nation has grown more politically and economically confident, a federal policy has become more entrenched, the States have demonstrated their administrative capacity and State level interventions have become much more important for economic development, Centre-State fiscal relations have clearly not kept pace. Sir, it is very important. The States do not receive the predictable, non-discretionary and non-discriminatory flow of resources from the Centre that the Constitution envisages.

The States have been placed at the whim and mercy of different Ministries in Delhi to receive assistance for many Centrally-sponsored schemes.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

While Tamil Nadu may be more efficient in ensnaring more funds for its needs in such a mechanism, we sincerely believe that such discretionary transfers are not just a sub-optimal solution, but deeply humiliating for the States as the elected State Governments are not regarded as equal partners in the development process, but as mere local supplicants. Such a design is completely flawed and violative of the spirit of the constitutional scheme where States, being closer to the people, have been accorded a key role in development related activities.

That is why, Tamil Nadu under the leadership of my leader is a very strong votary of the idea that the greatest proportion, if not the entire, fund flow from the Centre to the States should be on the basis of the recommendations of the constitutionally mandated Finance Commission rather than through other mechanisms.

It is on this basis that the hon. Chief Minister of Tamil Nadu proposed to the Fourteenth Finance Commission to exclude discretionary expenditure of the Centre including as Gross Budgetary Support to the Plan from the committed liabilities of the Central Government when the resources available with the Centre for devolution to the States are assessed. Out of the aggregate resources available with the Centre, 50 per cent should be made shareable with the States, which would appropriately balance expenditure needs of the States and Centre and help considerably diminish the scope for discretionary and discriminatory transfers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many more pages?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Only seven pages. I am having 30 pages. If I am able to complete it quickly, another Member may be accommodated tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, there is no rule. Otherwise, I would have asked you to place it on the Table of the House. You proceed.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: I think these are all the important points. The Fourteenth Finance Commission recommended a substantial enhancement in the share of the States in the divisible pool of Central taxes from 32% to 42%, heeding the suggestion of our revered leader Puratchi Thalaivi Amma. While we welcome this increase in non-discretionary and assured transfer of resources from the Centre to the States, it is important to note that the Commission's recommendations do not represent an aggregate increase in the gross transfer of resources from the Centre to the States.In fact the Commission expects the gross transfer to be 49 per cent of the gross tax receipts of the Centre, which is less than the 53.4 per cent level reached in 2011-12.

Our revered Leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma had suggested a simple, robust, well-balanced and equitable formula for distribution of resources amongst States with one-third weight for each of the following criteria: Population based on 1971 Census, fiscal discipline including tax effort and fiscal capacity distance. But distressingly, despite the very strong case made out for fair and equitable treatment by our revered leader Puratchi Thalaivi Amma, Tamil Nadu has been singled out for the sharpest reduction in its share in the divisible pool of taxes. As against 4.969 per cent share in the divisible pool of Central Taxes recommended by the 13th Finance Commission, Tamil Nadu's share has come down to 4.023 per cent in the 14th Finance Commission's recommendations. The unbalanced formula adopted by the 14th Finance Commission has virtually singled out Tamil Nadu for the most adverse treatment. The reduction in the *inter se* share of Tamil Nadu of 19.14 per cent represents the biggest loss in share amongst all States. A very large drop in Tamil Nadu's share in the divisible pool is barely compensated by the increase in the overall devolution pool by 10 per cent. Tamil Nadu's overall share in the Central taxes has increased by just 0.1 per cent from 1.59 per cent to 1.69 per cent. Tamil Nadu has been doubly penalized for its prudent fiscal management as it has not received revenue deficit grants. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR(Himachal Pradesh): Sir, I am on a point of order. I would like to know whether a written speech is allowed to be read in the House.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: These are all the figures. I cannot keep them in my memory.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is reading it. It is not that I have allowed him.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Tamil Nadu has been doubly penalized for its prudent fiscal management as it has not received revenue deficit grants.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, there is no rule to place it on the Table of the House; otherwise, I would have allowed it.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: These are all figures. I cannot keep it in my memory. I do not want to give incorrect figures.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, you are a senior leader. You should know that reading a speech like this is not to be permitted in the House.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: My friend wanted me to complete it. This is the whole problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then complete immediately.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: The Finance Commission has also recommended no special purpose grants and State specific grants, of which Tamil Nadu received ₹ 4,669 crores during the 13th Finance Commission period. The loss to Tamil Nadu, due to the reduction in its share in the divisible pool and the discontinuance of special purpose and state specific grants is estimated at ₹ 6,000 crores per annum. With the inevitable reduction in Central Plan assistance, Tamil Nadu will stand to lose even more. Hence, Tamil Nadu has cause to be seriously aggrieved with the recommendations of the 14th Finance Commission, which have not served the cause of fiscal federalism as much as they could have.

The Union Budget 2015-16 has piled on more distress on Tamil Nadu through some of its proposals. In the Union Budget, the Central Government has found numerous ways to claw back the increased devolution recommended by the 14th Finance Commission. These include the following: (i) The conversion of ₹ 4 per litre out of the specific duty of petrol and diesel into road cess takes that much of revenue out of the divisible pool and it becomes the exclusive revenue of the Central Government. (ii) Similarly, while the abolition of wealth tax and its replacement with a surcharge of 2 per cent on the super rich will fetch significant additional revenues to the Government of India, this is not shareable with the States. (iii) A number of schemes supported with Central funding have been delinked from Central Assistance and the State's share for many Centrally-sponsored schemes, including National Agricultural Development Programme, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Swachh Bharat Abhiyaan, National Health Mission, National Livelihood Mission, Smart Cities Programme, Housing for All and Integrated Child Development Service (ICDS) is being enhanced.

The States being required to take on additional burden of expenditure on Central Government priorities is an unfair expectation and outcome.Further, as my revered leader, Puratchi Thalaivi Amma, has already stated on a number of occasions in the past, in Centrally Sponsored Schemes, the States' share should be limited to a maximum of 25 per cent of the scheme cost in order to ensure that the States' own expenditure priorities are not distorted. This is a key element of fiscal federalism and State autonomy, which ought to be preserved.

The proposed Goods and Services Tax is another key issue with a significant bearing on fiscal federalism. Tamil Nadu is primarily concerned about the impact the GST, in its present form, will have on fiscal autonomy of States and the huge revenue loss the GST is likely to cause to a manufacturing and net exporting State like Tamil Nadu. In fact,

the hon. Chief Minister of Tamil Nadu had suggested an alternative radical approach of delegating the levy and collection of the substitutes for VAT, Central Excise Duty and Service Tax within a State completely to the State machinery, with the Central machinery focusing on interstate taxation. Such an approach would have addressed issues of fiscal autonomy and adequate compensation and could help implement the tax reform measures. Even now, Tamil Nadu continues to have some concerns with the GST structure. The GST Council as a constitutional body impinges on the legislative sovereignty of both the Parliament and the State Legislature and completely jeopardizes the autonomy of the States in fiscal matters. We strongly object to the provision of the GST Council. The existing mechanism of the Empowered Committee of State Ministers, which dealt with VAT issues, is adequate. Ideally, no statutory GST Council is required. Furthermore, the decision making role and voting pattern in the proposed Council are completely unacceptable. They give the Government of India an effective veto in the GST Council and no distinction is sought to be made amongst the States in weightage. Hence, if at all a Council is formed, the weightage of the vote of the Central Government should be reduced to one-fourth of the total votes cast and that of the States should be increased to three-fourths of the total votes cast. Further, the weightage of each State's vote should be in proportion to the representation of each State in the Council of the States. This is important as the changeover to GST has different implications for different States based on their size and reliance on own tax revenues. There is a need to enable the States to levy higher taxes on tobacco and tobacco products on par with the Centre, as States like Tamil Nadu already levy a higher rate of tax on tobacco and tobacco products on account of the public health concerns. In lieu of the proposed additional levy of 1 per cent tax on inter state supply of goods, it is suggested that the origin States may be allowed to retain 4 per cent of the Central GST part of the Inter-State GST that would be leviable on inter-State supply of goods and services as this would ensure speedy recompense for a portion of the revenue loss and will reduce the amount of compensation payable. Further, as this comes out of the CGST component, it does not affect the destination, State's revenue, or cause any cascading. We would urge that our concerns are adequately addressed to ensure that the Constitutional Scheme of federalism is preserved.

The Constitution of India offers protection to the use of regional languages in the States and grants them official status in the Eighth Schedule. This is one of the key Constitutional protections for Tamil Nadu. Our revered leader, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, has strongly reiterated a longstanding request, voiced on behalf of the people of the State of Tamil Nadu about the use of Tamil language in the High Court of Madras. Clause 2 of Article 348 of the Constitution, read with

[Shri A. Navaneethakrishnan]

Section 7 of the Official Languages Act, 1963, clearly envisages the usage of the State Official Language in judgments, decrees and proceedings of the High Court with the prior concurrence of the President. This practice is already being adopted in four States. However, our repeated requests to authorize the use of Tamil in the High Court of Madras have not been responded to favourably. A communication received in January, 2013, from the Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs, Government of India, has indicated that the request of the State was considered by the Full Court of the Supreme Court of India in the meeting held on 11.10.2012 and that the Full Court, after due deliberations, reiterated its earlier Resolutions adopted on 07.05.1997 and 15.10.1999 not to approve the proposal. If we are to take the administration of justice genuinely closer to the people, then, it is absolutely imperative that the local language is used in the High Court, as is already being done in the State Government and in the State Legislature. We urge upon the Government of India and the Supreme Court to reconsider their stand in this matter and fulfil the long standing aspiration and demand of the State to authorise the use of Tamil in the High Court of Madras.

The greatest tribute we can pay to Dr. Ambedkar is to reaffirm our commitment to the Constitution, uphold social justice at any cost, act in a manner that enhances greater federalism in Indian polity, and accord equal importance to all languages in the Eighth Schedule of the Constitution.

Sir, I once again thank hon. Chief Minister, Amma, for giving me this opportunity and I also thank the Chair for giving me this opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, there is the Chairman's direction, which is as valid as the rules, that Members should not be allowed to read their speeches.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Hereafter, I will not do it. This is a very important matter. That is why I read it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, everything is on record. Don't worry. Now, Shri Sitaram Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, thank you for giving me this opportunity.

सर, जब सेशन की घोषणा हुई थी, उससे पहले हमारी पार्टी ने यह मांग की थी कि डा. अम्बेडकर के 125वीं जयंती पर आप स्पेशल सेशन बुलाइए, ताकि कुछ नए कानून जो हमारे हिसाब से

जरूरी हैं, उन कानूनों को लागू करें। अभी हमारे मित्र शरद यादव जी ने बड़े विस्तार से पूरे आंकड़े बताए कि यह हालत आज क्या है? दलितों की और आरक्षण की जो बात हुई, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज देखिए, सिर्फ आरक्षण का ही सवाल नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसके आंकड़े भी आप देखिए। इसी सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं, दलितों के ऊपर 2014 में जब से यह सरकार आई है, 19 प्रतिशत हमले बढ़े हैं। 2015 में हम खुद देख चुके हैं कि फरीदाबाद में, अहमदनगर में किस तरीके के अत्याचार दलितों के ऊपर हुए हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि जो कानून आज हमारे हाथ में है, उसको मजबूत करना है, नया कानून लाना है और उसके चलते हुए हमने कहा था कि नए दस कानूनों की जरूरत है, जिसके अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में जो यह निजीकरण हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, शिक्षा में और रोजगार में जो आरक्षण का प्रावधान आपने पब्लिक सैक्टर के लिए दिया था, उसको आप बढ़ाकर प्राइवेट सैक्टर में ले आइए। प्राइवेट सैक्टर के अंदर यह आरक्षण हो कम से कम उसके बारे में चर्चा तो हो और कानून बने। हम यह चाह रहे थे कि एस0सी0, एस0टी0 के लिए statutory status मिले। हम यह चाह रहे थे कि जो आज रिजर्वेशन है वह प्रोफेशनल और हॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो। हम यह चाह रहे थे कि National Mission for Eradication of Untouchability हो। जैसा अभी शरद जी ने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे सफाई कर्मचारियों की क्या हालत है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। तो एक नए कानून की जरूरत है जिससे यह दुरुस्त हो सके। So, what we wanted was enactments of all the legislations on the basis of which we can carry forward the vision of social justice that Dr. Ambedkar stood for. Now, instead, we have a situation where the Government has come forward saying that we reaffirm our faith in the Constitution. Where is the question of reaffirming? You are here, I am here, and all of us are here on an oath on this Constitution. What is this drama of reaffirming? If the Constitution is not there, then, you won't be here. The Government of the day must know, the Leader of the House – he is not here now – should know that they are there only because we affirm this Constitution. What is this quesiton of now saying, "We will reaffirm"? And what is this Constitution Day, Sir?Go through the history. On 26th of November this Constitution was signed by the President of the Constituent Assembly. It was voted upon and the draft was adopted and in the draft you have said explicitly 'that on the 26th of January India shall be a Republic in 1950 when this draft will turn into a Constitution and we shall enact.' Can this Government answer? I want our esteemed lawyer, the Leader of the House, to tell us what law governed India from 26th of November, 1949 to 26th of January, 1950? Was it this Constitution? Is it known, Sir? The law that governed India during those two months after you adopted this Constitution was India Independence Act, 1947 moved by the British Prime Minister Attlee in the House of Commons in London. What is this Constitution then? You were under the British law for these two months. You adopted and enacted this Constitution on the 26th of January. Now, what is this new thing that you are finding now 65 years later on the

[Shri Sitaram Yechury]

Constitution Foundation Day? You please explain to me, Sir. You are sitting on the Chair. Maybe, you have greater knowledge, but you please explain to me that when Dr. Ambedkar himself says that on 26th of January we are enacting this Constitution and we shall be a Republic, what is this 26th November? Yes, that day the Constituent Assembly adopted this draft, but that was not the Indian Constitution yet. That was not the law of our land yet. It became the law of the land on the 26th of January, 1950. Lawyers are talking like this, Sir, on the Constitution Foundation day! You want some day or the other to find yourself so that you can celebrate one more event. The Constituent Assembly met again on the 24th and 25th of January, 1950. The Jana Gana Mana as the National Anthem was adopted on the 24th of January and on the 24th and 25th all Members of the Constituent Assembly signed this Constitution and on the 26th of November only 15 out of the 395 clauses in our Constitution came into operation. Sir, 26th of January, 1950 was when the entire Constitution came into operation. So, what is this new item that we have, Sir? ...*(Interruptions)*... You may call it item song or whatever. It is a new item now in the Indian Constitution. A senior leader of the ruling party has described our Prime Minister, charitable or uncharitable, I don't know, it is up to their party to decide, he called him an excellent event manager. One event after another, London and after that Malaysia, after that Asia and after that Constitution Day and from tomorrow it will be Paris. They showed us an old film in my youth, "Paris ke range shyam". That will be the event from tomorrow.

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): It cannot be in the name of a film.

SHRI SITARAM YECHURY: I don't know. So, what is this event to event to event? What are we observing, Sir? I am sorry, but I think the entire, what in Hindi we call, garima of this House, of the Parliament is being undermined by these sorts of flippant events that are coming in. Yes, for 26th of November we have the highest respect for Dr. Ambedkar and for everybody else. Does this Government today know that Constituent Assembly began its work on a Resolution moved by Shri Jawaharlal Nehru called the 'Objectives Resolution'? Does this Government know that out of the eleven sittings of the Constituent Assembly six of the sittings were devoted to the 'Objectives Resolution' and not to this draft? A majority of the discussions in the Constituent Assembly was on the objectives put forward by Shri Jawaharlal Nehru. Sir, that is our history. Yes, the victor always scripts the history. But, here, the victor is also trying to change the past history! Now, this is the history we have inherited. Like the hon. Leader of the House, I was also born after Independence. I think, many of us are born after Independence. And, for all of us, this is inherited history; this is our legacy. You cannot now tamper with that history

and tell us a new history! Now, why this Constitution Day? I can only come to the conclusion that this is an attempt to try and worm their way into the national movement when they had no role to play at all. This is the way they want to worm themselves into the national movement and how they want to worm themselves I want to know.

How this order is given? Sir, it is a Gazette Notification saying that 'it has been decided to celebrate 26th day of November every year as the Constitution Day.' It is a Gazette Notification. If you want I will place it on the Table of the House. It is a notification in the Indian Gazette, dated 19th November. It is issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Does the Ministry of Social Justice and Empowerment decide a national day to be observed every year?

AN HON. MEMBER: The hon. Minister is here.

SHRI SITARAM YECHURY: Yes, I have noticed that hon. Minister is coming in here. Hon. HRD Minister was a good fried of mine before she became a Minister. After that she does not have time and she has got very onerous responsibilities. But, I just want to know how the Gazette Notification comes on 19th and the HRD Ministry issues a circular to schools on 10th of November saying 'observe 26th November as the Constitution Day.' This is a Gazette issued on 19th. What is happening, Sir. Items in Indian politics. That is the only thing I can say – events. You have event management. You want to worm into the national movement when you had no role. Here, I wish to put it on record the fact that often we have heard and we will hear also, I am sure, in the course of this discussion, the role of Communists, etc., in the Freedom Struggle. That is an old charge.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी:उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि श्री सीताराम येचुरी जी की आपत्ति है कि 'National Constitution Day' क्यों मनाया जा रहा है। इस संबंध में, मैं केवल उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... सुन लीजिए। अभी तक 26 नवम्बर प्रति वर्ष 'National Law Day' के रूप में मनाया जाता रहा है। अगर हम उसे 'National Constitution Day' के रूप में मना रहे हैं, तो हम मना रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम अपने संविधान निर्माताओं को याद कर रहे हैं, उनके प्रति यदि हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति यह सदन नत-मस्तक हो रहा है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you have to protect me. In the name of clarification, he cannot give his own interpretation. Constitution Day मनाओ। हम डा. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे, सलाम देते रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन आप यह बताइए कि आपने यह नया दिवस खोजकर क्यों निकाला? हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपने यह दिवस खोजकर क्यों निकाला है, उसकी पृष्ठभूमि हम बता रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): इसमें गलत क्या है?

श्री सीताराम येचुरी: जी हां, हम यही बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन में भूमिका नहीं थी, इसलिए उस भूमिका को जुड़वाने के लिए आप यह बोलना चाहते हैं और **...(व्यवधान)...**

SHRI TARUN VIJAY (Uttarakhand): Sir, I have a clarification to seek. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. Are you yielding, Mr. Yechury?... *(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: No...*(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding...*(Interruptions)*....He said that he is not yielding...*(Interruptions)*.... तरुण जी, यदि मैम्बर यील्ड नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इसमें क्या करूं? **...(व्यवधान)...** तरुण जी, आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** तरुण जी, आप बैठिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tarunji, please ...*(Interruptions)*... Tarunji, nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Tarunji, please sit down. Those who want to respond to the points Mr. Yechury is raising can do it when their turn comes, without interrupting others. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Deputy Chairman, Sir, whatever has been said now must not go on record--otherwise, it can be contested and challenged --because he has not yielded. This House has to be governed as per the Rules of this House. This is our request. Otherwise, what has been said will be contested here and now because that is a statement...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is okay, please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Tarun, don't do that. Please sit down.

श्री सीताराम येचुरी : सर, देखिए। अब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के बारे में बोल रहे हैं। हम कहेंगे, तरुण विजय जी, आप ज़रा सब्र कीजिए। आपने बहुत सारे सवाल यहां भी पूछे और बाहर भी पूछे, मैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हमारी पृष्ठभूमि के बारे में आपने सवाल उठाया है कि कम्युनिस्टों की जो पृष्ठभूमि है या आपकी जो है, उसके बारे में मैं आपको दो चीज़ें पढ़कर सुनाता हूं। ...*(Interruptions)*... Sir, please don't deduct the time of these interruptions from my time and start pressing the bell. Please don't do that. The British Bombay Home Department, in 1942, during the Quit India Movement observed, "The Sangh has scrupulously kept itself within the law and in particular has refrained from taking part in the disturbances that broke out in August, 1942." ..*(Interruptions)*.. This is the record of the British Government.

Now, Tarunji made a charge against the Communists. यह भी सुन लीजिए।...(**व्यवधान**)... सर, 1992 में एक स्पेशल सैशन सेंट्रल हॉल में रात के 12 बजे हुआ था। 1942 की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में उस स्पेशल सैशन में बोलते हुए हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने भाषण में, जो यहां पर रिकार्ड में मौजूद है, कम्युनिस्टों के बारे में जो कहा, उसे मैं यहां पढ़कर सुना रहा हूं।

> "After large scale strikes in mills in Kanpur, Jamshedpur and Ahmedabad, a despatch from Delhi dated September 5, 1942, to the Secretary of State, in London, reported about the Communist Party of India: 'the behaviour of many of CPI members proves what has always been clear, namely, that it is composed of anti-British revolutionaries.'"

This is the President of India telling this in the Central Hall of Indian Parliament. अब तो यह इल्ज़ाम बंद करिए। अब मैं आपको बताऊं।...(**व्यवधान**)...

SHRI TARUN VIJAY: Can we not have the right to seek clarifications? *...(Interruptions)...*

श्री सीताराम येचुरी : आपको आपत्ति हो रही है when I say 'worm into'; श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का नाम लिया। वे भले नेता थे, नेहरू जी की कैबिनेट में थे। वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया। वे राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए खोज रहे थे। आप बताइए कि आरएसएस के रिकॉर्ड में यह बात है या नहीं कि जब वे एक नयी पार्टी बनाने के लिए खोज रहे थे, आपके गुरु गोलवरकर साहब ने चार स्वयंसेवकों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास भेजा कि आप एक नयी राजनीतिक पार्टी बनाएं। ये लोग कौन थे? यह आप ही का रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसमें कौन लोग थे? दीन दयाल उपाध्याय जी, एल.के.आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्याम सुंदर भंडारी जी। इन चारों को आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को मदद देने के लिए भेजा, नयी पार्टी बनाने के लिए भेजा और यह कब हुआ, जब सरदार पटेल ने अपने communique में यह कहा था और आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के बाद बैन किया था।वह जो बैन हुआ था, उस बैन से वापस निकलने के लिए कई शर्तें सरदार पटेल ने लगाई थीं। उनमें से एक शर्त यह थी कि आर.एस.एस. राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी। उसके राजनीति में हिस्सा न लेने की वजह से उन्हें एक राजनीतिक अंग चाहिए था और वह अंग उस समय जनसंघ बना था, जिसका आज का अवतार है-आप सभी लोग, भाजपा। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा मत कहिए। Worming your way into the national movement की बात पर आपने आपत्ति जताई। ...(**व्यवधान**)... सर, इन बातों को छोड़िए। हमारे इस हाउस के माननीय नेता सदन ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कुछ अंश पढ़कर सुनाए। He read out Article 44 of the Constitution, Sir, which deals with it. I have the copy of the Constitution and this is the copy that belongs to the Chamber. So you cannot accuse me of any personal or fudged copy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you think there are different copies of the Constitution?

SHRI SITARAM YECHURY: No, no. Sir. They may accuse me. They may accuse me, so I am reading out only from the Chamber's copy. Even that is challanged. So you don't argue for authentication; it is marked as Chamber's Copy. It says, 'the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code.' It was quoted. It was also quoted on the question of organisation of agricultural and animal husbandry. I pointed out then that these are Directive Principles of State Policy, which are not justiciable and enforceable, and these Directive Principles also have other things, Sir, which are not quoted. What do they say? They say, 'the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people.' What did Babasaheb Ambedkar say? The same thing; that is Article 46. Article 47 says, 'the State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living.' Isn't it a shame that today, the largest number of children malnutritioned are in India? Isn't it a shame that majority of the stunted children in the world are from India, today? This is the Constitutional Directive, Article 47. What has been done? You only pick and choose what you want to do and that is where the suspicion comes as to what is your actual motive. Here in the section on Fundamental Duties that are supposed to be enforceable -- you please look at your copy in your hand, Sir -- Article 51A says, 'it shall be the duty of every citizen of India.' If you read Article 51A (f), it says, 'to value and preserve the rich heritage of our composite culture.' Is it the composite culture that we are preserving, Sir? I will come to that again. What does 51A(h) say? It says, 'to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.' Sir, if we hear that Lord Ganesha was the creation of plastic surgery or Karna in the Mahabharata was the creation of stent technology and test tube babies, is that scientific temper? And it comes from no less than hon. Prime Minister. What is happening? What are you implementing? What are you wanting to implement and what not? You are only reviving the hardcore Hindutva agenda. Cow protection, you are wanting to revive. Then the entire question of equality of all citizens to liberty in life. He has quoted Article 30. He is not here, unfortunately, so I cannot request him also. He has quoted this Article 30 -- you can also help me, Sir, in finding that Clause -- and said that these are contradicted by Articles 29 and 30. Article 15 says, 'the State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.' This is Article 15, Fundamental Rights.He says, "Articles 29 and 30 are in contradiction". Sir, any lawyer would know, any right always comes with what is called reasonable restrictions. I hope, Mr. Parasaran is here; there is no right which does not come without reasonable restrictions. The reasonable restrictions through Article 15 have been detailed in Articles of the Constitution, 29 and 20, where the rights of the minorities to their religion are given. Minorities here meaning not only religious but also linguistic minorities. So, it is said, "This is a contradiction.

Don't we want to remove it?" What would Dr. Ambedkar say today if you were talking about this contradiction, about this Constitution? He would say precisely the same thing that the duties of a citizen would be the spread of tolerance, and not the spread of any one particular intolerant point of view. And that is the bone of contention today, Sir. I read in the media the hon. Home Minister saying that secularism is the word that was injected into the Constitution, and, therefore, that is the cause of all problems. He has also referred to, I believe, poor old Aamir Khan; our actor is getting lampooned. He said, "Ambedkar did not leave the country. But he stayed here and struggled". And that is what Aamir Khan also said, Sir. He did not say that he is leaving. I am glad he is staying and struggling, and then you accuse them saying that Left is sponsoring all that. Thank you for putting all those people with us. Our tribe is increasing. That is what you are doing. *...(Interruptions)...* But remember, Ambedkar did not leave the country. He was a patriot. But, Ambedkar renounced Hinduism and embraced Buddhism. You remember that. You remember that, and why was that? That is where the intolerance issue comes in. Sir, these are matters again of history. You cannot erase it, and if you want the question of intolerance, take the same speech of Dr. Ambedkar of 25th November, which the hon. Leader of the House was quoting. This is the same speech, and what does Dr. Ambekar say? He was talking about 'history will repeat itself'. "Will we lose our Independence again...", hon. Leader of the House quoted that. After that, he did not quote the rest of it. What does it say? I am quoting from that Speech of Dr. Ambedkar. "Will history repeat itself"? That is, will we lose our Independence once again? "Will Indians place the country above their creed or will they place creed above the country, I did not know". As the Leader of the House said, if Dr. Ambedkar was here today, what would he say? He would not pose this question. He will say, "Indians are being forced to place their creed above the country". And that is the intolerance that is happening in the country today. Then, what did Dr. Ambedkar say? "But this much is certain – this is the speech, Sir, which was quoted in the morning – if the parties place creed above country, our Independence will be put in jeopardy a second time – after all the instances he gave, which were quoted by the leader – will be put in a jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our Independence with the last drop of our blood".

Today, when I stand up against this intolerance, I am doing exactly what Dr. Ambedkar asked us to do. Anybody who wants to say what Dr. Ambedkar said must be done, we will do exactly what Dr. Ambedkar asked us to do, i.e., raise ourselves against this sort of intolerance. This is the same Ambedkar in the same speech.

[Shri Sitaram Yechury]

5.00 P.M.

Then, we heard the question of social justice. The essential point of Dr. Ambedkar is missed out. I have quoted this a number of times in this august House, but I can't stop myself from quoting this again.

Now, I quote it in the full. It says, "On 26th of January, 1950" – please note once again, it is the Constitution Day, the Republic Day – "we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will give equality and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of 'one man one vote', 'one vote one value'. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structures, continue to deny the principle of 'one man one value'." That is the contradiction. Then, he continues to say, "If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest. Or else, those who suffer from this inequality will blow up the structure of political democracy that this Assembly has so labouriously built". This is Dr. Ambedkar in the same speech. What is the situation today? A hundred multi-billionaires in our country, whose asset value is close to one-half of my country's GDP. And, according to the latest census, ninety per cent of the households in my country, today, have an income of less than ₹ 10,000, a month. Is this contradiction being resolved or are you only accentuating it further? Are we discussing issues of how we should reduce the gap in this contradiction? Instead, every foreign trip, we find a new concession to foreign capital. Fifteen new areas have been opened up to the FDI. Free Trade Agreements are ruining our domestic cultivation of commercial crops! The agrarian distress is growing. Farmers are committing suicides. Your industrial production index, as per this Government's own statistics, this month has shown a drop from about six per cent plus to about three per cent. Manufacturing has dropped to 2.4 per cent from over 6 per cent. Industrial production is declining. Agrarian distress is deepening. 'हर-हर महादेव' की जगह अब लोग शिवजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि 'अरहर' महादेव, ताकि खाने को दाल तो मिल जाए। अरहर की दाल 200 रुपए प्रति किलो मिलती है, जो कि मुर्गी से भी महंगी है। अब "घर की मुर्गी दाल बराबर" नहीं है, बल्कि अब 'घर की दाल मुर्गी बराबर' है। अब ये हालत कर दी है। अब इस पर कोई चर्चा है? कांस्टिट्यूशन दिवस का मतलब क्या है? Where are we on the social justice vision of Dr. Ambedkar? I have mentioned about the atrocities on SCs and STS and about reservation. On the question of growing inequalities, the condition of our people is deteriorating. What is this contradiction? You see the reality. Are we paying homage to Dr. Ambedkar? Is this the way Modern India is actually fulfilling the vision of social justice. Forget about the political parties. Forget

to which party I belong, to which party you belong. As an Indian, when you are talking about these things, are we being honest to ourselves? Are we doing justice to Dr. Ambedkar and all of that generation – Nehru, Gandhi, Abul Kalam Azad, Sardar Patel – that gave us Independence and this Constitution? What had they exhorted all of us to do? Are we doing it? And, you say, "I reaffirm my faith in the Constitution." Without reaffirming that faith, you won't be here. What is this reaffirming of faith?

Come to the federalism. What did Dr. Ambedkar say on federalism?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please try to conclude.

SHRI SITARAM YECHURY: Yes, Sir. But how can I conclude federalism and intolerance and all that? *...(Interruptions)....* You are asking to conclude what the Government is doing. In a federal structure, on Centre-State relations, what did Dr. Ambedkar say? He said that the Centre and the States are coequal in this matter. Sir, I am reading from the same speech. "It is difficult to see how such a Constitution can be called centralism. That is, the basic principle of fedearlism is that the legislative and executive authority is partitioned between the Centre and the States, not by any law to be made by the Centre but by the Constitution itself." That is the essence of this Constitution. Is the principle of federalism followed, Sir? You are talking about the misuse of Article 356. That is only one part of it. We, the Kerala Government, were the first victim of Article 356, way back in the 1950's. I don't know how many of you were there. Second time, we were victim in 1960s; twice, we were victim in Bengal, in 1967 and 1969. *...(Interruptions)...*

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Antony is here. He was the hero.

SHRI SITARAM YECHURY: Hon. Antony is here. He was a hero of one of the... *(Interruptions)..* But, Sir, all that apart, what is fedearalism? Not merely equality, that independent respect of the States, are we granting it today? Then, you talked of judiciary. Let me tell you, what Dr. Ambedkar said about judiciary is very, very interesting. I am quoting from the same speech, " Courts may modify, they cannot replace", please note, "Courts may modify, they cannot replace, they can revise earlier interpretations as new arguments, new points of view are presented. They can shift the dividing line in marginal cases, but there are barriers they cannot pass, definite assignments of power they cannot reallocate. They can give a broadening construction of existing powers, but they cannot assign to one authority powers explicitly granted to another." The separation and the complementarity of the Executive, the Judiciary and the Legislature are hallmarks of our Constitution. Now, this is as far as your Judiciary is concerned.

[Shri Sitaram Yechury]

But what worries me about is you are paying homage to Dr. Ambedkar. Remember, Sir, from 1946 to 1950, what was the condition of the world? Millions of people were under colonial subjugation. When these countries became independent, what we did in India was, actually, a revolutionary step then. We granted universal adult suffrage, which nobody else of these countries granted. ...*(Interruptions)*... Europe did not grant and not even the United States of America. President Obama came here. All of us were very excited in the Central Hall, both sides. Everybody was saying, wah wah, President Obama came here, and, then, he wrote in the Golden Book -- there is no gold in that book -- of our Parliament, "Greetings from the world's oldest democracy to the world's largest." This was his message. Yes, this was the message he gave. I had to point it out later that evening at the President's banquet. I said, "Sir, I think, this is a wrong definition that you are the world's oldest democracy." He said, "Why'? I said, "Sir, you got the right to vote, that is, American-Africans, universally in the United States of America in 1962, one year after you were born. The universality of adult franchise in the United States of America came only in 1962; in India, we gave it in 1950." Whether you are a dalit, you are a landlord, whether you are a Muslim, whether you are a Hindu, we gave it in 1950. And, today, Sir, what is happening? In Haryana, 86 per cent of the people will be kept out of their right to vote and right to contest elections because of various conditions. The State Government has said that unless you fulfil these conditions, you cannot contest or you cannot vote.In Rajasthan, you put conditions whereby more than half the people are excluded from the universal suffrage. In Gujarat, you have said, 'unless you have a toilet, a pucca toilet, in your house, you cannot vote or contest in local elections'. All these three States have got a BJP State Government. You come here to pay homage to Dr. Ambedkar and the one important thing that has been done by the Indian Constitution on universal adult suffrage, you deny it to people in the States which have a State Government that is led by the BJP. ...*(Time-bell rings)*...

Sir, I know you will press the bell. But the point is that you please consider all these things. The Ruling Benches are empty. I don't know who will convey, what and to whom when the reply comes on Monday.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Ministers are there. ...*(Interruptions)*... They will do it. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I sympathize with my friend, Shri Mukhtar Abbas Naqvi. How much burden can he carry, Sir? How much can he go and report upstairs saying that this is all that has been said and you please answer that? And, even the

officers have deserted the officials' block. So, I don't know if anybody is taking note of all this. We understand many of these things. They ignore us normally. ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: This shows their commitment.

SHRI SITARAM YECHURY: But, Sir, since you are pressing the bell, let me come down to my final points. The Leader of the House made an interesting and a very interesting reference to the Third Reich and Germany. Wonderful, Sir. We are happy, and I must pay my gratitude to the Leader of the House for having reminded me of the Third Reich and Germany and the dangers of authoritarianism. Sir, in 1939, when the debate in the country was going on as to what should be the character of Independent India, there was a book, which was not thought that it would be very important but a book which had a very, very important implication for Indian politics and India's future, and that was a book called 'We, or our Nationhood Defined' by Madhav Sadashiv Golwalkar. He is called the RSS Guru. And, since the Leader of the House mentioned the Third Reich, I only want to quote from that book about the Third Reich. That book is, 'We, or Our Nationhood Defined'. Who is 'we'? In Hindi 'Swaraj.' "स्व" का मतलब क्या है? किसका राज है यह? हम कौन हैं? हम एक हिन्दू राष्ट्र हैं। That is the entire import of that book. उस समय हिटलर के बारे में, जर्मनी के बारे में चर्चा करते हुए he talked saying that 'only Hindus and Hindus alone are inhabitants of this country'. And, then, what does he say about the Third Reich? I am quoting, "To keep up the purity of the Race and its culture, Germany shocked the world by purging the country of the semitic Races, the Jews". I will take a break here, Sir, for a moment. You please draw the parallels in India -- who is that instead of the Jews and who is that for the Race and the culture and its purity. I continue with the quote. "Race pride at its highest has been ..." ...*(Interruptions)*...

SHRI V.P. SINGH BADNORE(Rajasthan) : Sir, which book is he referring to? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: From which book are you quoting? ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: He is quoting from scriptures of your party. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You say from which book you are quoting. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, my good friend, Mr. V.P. Singh Badnore, may not be so much in tune with the RSS as he is a BJP M.P. But let me tell him that the

[Shri Sitaram Yechury]

name of the book is: 'We, or Our Nationhood Defined'. I am quoting from page no. 35. This book was published in 1939 by Bharat Prakashan, republished by Bharat Prakashan, Second Edition, again in 1944. That is the authenticity. That book must be available in library if it is not already removed. I mean, they have this habit also of removing all these books. But otherwise, this book should be in the Parliament library. Otherwise, I will help you. I will give you a copy. Now, it is in this book, on page 35. I repeat that quote; it says, "To keep up the purity of the race and its culture, Germany shocked the world by purging the country of the semetic races, the Jews. Race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole. A good lesson for us…." Please understand this.

SHRI V. P. SINGH BADNORE: We cannot do that. That is why! What is that commentary?...*(Interruptions)*... We cannot do it. What is wrong in it? ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN(West Bengal): He is not saying anything wrong. Why are you getting agitated? ...*(Interruptions)*...

SHRI V. P. SINGH BADNORE: We cannot do that. That is why he has said so. What is wrong in that?...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: He is not saying anything wrong, Mr. V.P. Singh. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, let me complete. ...*(Interruptions)*.... Sir, let me complete. ..*(Interruptions)*...

SHRI V. P. SINGH BADNORE: We cannot do that. That is why he has said... *(Interruptions)*... What is wrong with that? ...*(Interruptions)*... What is he trying to do? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, you would get a chance. You may reply to that; you would get your chance....*(Interruptions)*... You can reply to that. You would get your chance. You say that he is misinterpreting. When you get your chance, you may correct it. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: I am quoting verbatim. And if you want, shall I re-quote the whole thing?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; there is no need for that. It is all on record. *...(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: Have you followed so far?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Now, you need to conclude also. There is no time. *...(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, let me conclude with just one sentence – "A good lesson for us in Hindustan to learn and profit by." This is about the Third Reich that the hon. Leader of the House was reminding us about.

SHRI V. P. SINGH BADNORE: We thought this is wrong. That is why we... *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. *...(Interruptions)...*

SHRI SITARAM YECHURY: This is exactly what this Hindu Rashtra is all about, Sir. That is why, if you want to pay homage and our shraddhanjali to Dr. Ambedkar, please remember what he said in the speech finally. I would like to quote to you what he said about creed: "Without equality, you cannot have liberty. Without fraternity, you cannot have equality and liberty. Without equality and fraternity – fraternity means sadbhavna – ...you cannot have liberty." If you are celebrating India's freedom and its liberty, equality and fraternity are the two things on which there can be no compromise. And that is precisely what is being compromised in this furtherance of the atmosphere of intolerance.

Sir, finally, let me end by quoting Dr. Rajendra Prasad. When he was about to put his signatures on this draft, the future President of India, quoted these lines. He was not yet the President of India; he became the President of India only on the 26th of January and, then, it was said that the Governor General, Dr. Rajagopalachari, cannot administer an oath to our President because the Governor General is an appointee of the British. So, the Chief Justice was called, in this Central Hall, and he administered the oath. After that Dr. Rajendra Prasad administers the oath for an interim Government, adopts this Constitution, administers the oath and directs that under this new Constitution, fresh elections be held after delimitation is completed. That election was held in 1952. And today, we hear, Sir, that Sardar Patel was being denied from being India's first Prime Minister. Unfortunately, poor Sardar died in 1950; the first election was in 1952. …*(Interruptions)*… Is that understood, Sir? Now, if there is some magic and some tantra through which like Lord Ganesha somebody who is dead and gone can be brought back alive, unfortunately, to be the Prime Minister, I can understand! That apart, what did Dr. Rajendra Prasad say? I am

[Shri Sitaram Yechury]

quoting this and ending, Sir. Dr. Rajendra Prasad, in his address, hailing that we adopted this Constitution, says, "After all, a Constitution, like a machine, is a lifeless thing It acquires life because of the men who control it and operate it. India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them." I am sure when Dr. Rajendra Prasad and Dr. Ambedkar talked about 'men', they included the 'women' also. So, please don't take offence; I am sure, at that time, women were also part of it. "There is a fissiparous tendency arising out of various elements in our life", said Dr. Rajendra Prasad on November 26, 1949. He said, "We have communal differences, caste differences, language differences, provincial differences and so forth. It requires men of strong character, men of vision, men who will not sacrifice the interests of the country at large for the sake of smaller groups and areas and who will rise over the prejudices which are born out of these differences. We can only hope that the country will throw up such men in abundance." Is that the case? I rest my case by asking you the question. What are we seeing today? Have we produced such men in abundance? If not, I think it is time to correct the notion. If you want to do actual reaffirmation to our Constitution and pay our homage to Dr. Ambedkar, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI SITARAM YECHURY: Please don't okay me here, Sir, you will also be a part of it. All of us will have to sincerely pay homage to this, and that is what we need to do. Thank you, very much for giving me time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Dilip Kumar Tirkey or Shri Bhupinder Singh, one of you may speak.

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, यह हमारे लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है कि **...(व्यवधान)...**

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, you have been very indulgent to all the large parties. I hope it will not be at the cost of small parties later on. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Viploveji, don't do this. ...*(Interruptions)*... What are you doing? This is the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, if you permit, she was reminding me that the idea of the Constituent Assembly was first given by the Communist leader Shri M.N. Roy, and that is correct. In 1934, he gave the idea. That is a communist contribution. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Dilip Tirkey.

श्री दिलीप कुमार तिर्की :उपसभाापति महोदय, यह हमारे लिए अत्यंत खुशी और गर्व की बात है कि देश जब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा है, भारत की संसद और राज्य सभा में उन्हें याद किया जा रहा है और सभी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। इस बात में कोई दो मत नहीं हो सकते कि बाबा साहेब आधुनिक भारत के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं, इसलिए संविधान पर चर्चा करते समय उनके पूरे जीवन पर चर्चा जरूरी है। वे न सिर्फ एक महान समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री थे, कानूनविद और राजनेता थे, बल्कि सार्वजनिक जीवन में उनकी तरह विद्वान व्यक्ति शायद ही कोई और दिखाई देता है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर**) *पीठासीन हुए]*

उनकी विद्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि चार-चार बार पीएचडी की थी। इसके अलावा उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं। यही नहीं, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में पचास हजार से ज्यादा किताबें थीं। अपनी जवानी के दिनों से उन्होंने समाज में दलितों और वंचितों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई शुरू की थी। 'मूक नायक, 'बहिष्कृत भारत' और 'इक्वेलिटी जनता' नामक पत्रों के जरिए उन्होंने दलित अधिकारों के लिए पैरवी की।

उन्होंने कुएं से पानी पीने और मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया था। बाबा साहेब की सोच उदार, प्रगतिशील और अपने समय से आगे की थी। वे न सिर्फ हिन्दू धर्म की छुआछूत बल्कि किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता के आलोचक थे। आज के समय में जब हम अपने चारों तरफ धार्मिक कट्टरता का माहौल देख रहे हैं तो बाबा साहेब का संदेश बहुत प्रासंगिक हो गया है। देश की आजादी के बाद उनके ज्ञान, अनुभव और योग्यता को देखते हुए उन्हें देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद 20 अगस्त, 1947 को उन्हें भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। संविधान सभा की बैठक के दौरान हुई बहस में बाबा साहेब ने न सिर्फ दलितों और वंचित समाज के अधिकारों की वकालत की, बल्कि महिलाओं के लिए बराबरी की भी जोरदार पैरवी की। बाबा साहेब की दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से हम एक ऐसा संविधान बनाने में सफल हुए हैं, जिसमें हर प्रकार की छुआछूत और सामाजिक भेदभाव को खत्म किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।

महोदय, आज जब हम बाबा साहेब को उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं तो हमें उनके सपनों को याद करना चाहिए। बाबा साहेब एक समनत्व पर आधारित समाज बनाना चाहते थे, जिसमें कोई भेदभाव न हो और सब के लिए समान अवसर हों। इसके अलावा वे सभी प्रकार की धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ थे। देश ने आज़ादी के बाद काफी प्रगति की है, लेकिन बाबा साहेब के सपने अभी अधूरे हैं। आज इस मौके पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके महान आदर्शों को पूरा करने की दिशा में साथ मिलकर काम करेंगे, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (1): I think, Mr. Chowdary is not here; Shri Praful Patel is not here; Shri Tulsi is not here.

I will request Shrimati Smriti Irani, the Minister of Human Resource Development, to intervene.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. As a Member of Parliament, I think, this is a sign of divine paradox that on one bench sat two eminent men - one who blessed me with his friendship publicly, though they tried to have a knock at me as the HRD Minister, and on the same bench now is seated Pramodji, however before him, sat a gentleman who told me, "हां, पता है कितनी अकल है, बैठ जाओ।" I remember the words of Mr. Yechury who said that without equality and fraternity, there truly can't be any liberty. But possibly, it is a sign of the liberal and tolerant mind of an individual, who sits here, who is shushed in a patronising manner, from possibly a Member of Parliament who has made comments about female parliamentarians and women at large in the country, can patronisingly say that oh, पता है कितनी अकल है। The gentleman in question is not in this House today. But, as someone who has witnessed that how the wheels of democracy turn in this very House, let me, as a woman, say today that irrespective of which ideological shore we stand at, irrespective of the political debate and deliberation we delve in, this side or that, whenever the dignity of a woman is challenged, we speak in one voice. And today, surprisingly, the dignity of a notification was challenged. It was waved in our faces and a question was posed, "How is it that you notify a Constitution Day for educational institutions in this country?" Never could we imagine that a day, which seeks to celebrate the very history of how this Constitution came into being, a day that seeks to enrich the young, the future generation of this country as to what sacrifices were made so that these values, which are dear to humanity, can be enshrined in this living Constitution, is a celebration, which I, as an HRD Minister, will be compelled to explain, and hence, Sir, the following explanation. And, hence, Sir, the following explanation. On the 26th August, there was a notification, which rightfully indicates a notification dated 30th May, 2015, a notification, which included in it the need to increase awareness about the Constitution among citizens, particularly, children on the 26th of November. There has been a debate that this was the day when the draft was adopted but it was actualized in January, 1950. But, as Indians, we cannot ignore the fact that this is the rock on which we sought to build the political salvation of our country, and, I feel today, as many before me have turned the pages of history, to support what they have said. I too shall follow their lead. In 1999, Justice Verma worked with a group of Indians to operationalise how fundamental duties are to be seen in the education sector, and, one of the recommendations, which Justice Verma made, was that when students understand their obligations, they are likely to learn their own

way of fulfilling the obligations. Hence, he said, presentation of the values inherent in each clause of Article 51A through anecdotal talks at morning assemblies in schools should be organized. This, Sir, is the notification, which was subsequently given to the Central Board of Secondary Education, which said, amongst the events for the day, the School Head may address the students briefly about the significance of celebrating this day, and, also recite the Preamble to the Constitution.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): You should have said that a clarification... *(Interruptions)*...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I do not yield my position to speak now for I equally enjoy the Right to Freedom of Speech under this very Constitution. Though I have no copy of the office of the hon. Chairman, I do here, Sir, have, in my hand, the Constituent Assembly Debate, Volume 11, to quote what Dr. Baba Saheb Ambedkar said, and, I cast no aspersion here. Dr. Baba Saheb Ambedkar said, "The condemnation of the Constitution largely comes from two quarters - the Communist Party and the Socialist Party. Why do they condemn the Constitution? Is it because it is really a bad Constitution? I venture to say, 'no'. The Communist Party want a Constitution based upon the principle of Dictatorship of the Proletariat. They condemn the Constitution because it is based upon Parliamentary democracy." And, as Indians....

SHRI T.K. RANGARAJAN: There are certain differences. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I do not yield, Sir. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Hon. Member is not yielding. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: As an Indian, I think that this is a day of celebration that irrespective of the ideological divide, irrespective of the personal views that Dr. Baba Saheb Ambedkar had about those that he felt do not support the Constitution, we, as a united House, discuss that very Constitutional journey. I dare say, Mr. Yechury quoted from a book and so do I, possibly, the significance of this book might be understood after I recite the following. This is an oration called the 'Warrior Prophet of India' about Netaji in 1967. This oration was by Shri S.K. Majumdar, Barrister-at-law, Advocate Patna High Court and Supreme Court of India. His son, in the year 1996, 7th January, writes -- whose name, by the way, is Air Commodore S.K. Majumdar -- that this 'Netaji Oration 1967', a lecture delivered by my

[Shrimati Smriti Zubin Irani]

late revered father, addressed particularly to the youth of our country was virtually blacked out. And I, a bit intrigued when approached by the grandson of this very man, who said that you in Parliament shall discuss the political, Constitutional journey of our country. Let this be read, if you deem fit, amongst eminent parliamentarians so that it gets highlighted as to what sacrifices were made, not only by men who donned the political hat but also men and women who served the nation nonetheless. In this book he says, I quote, Sir, "Upon being told that he shall be expelled from the Congress party, Netaji said the following: Do they object to me because I would not be a tool in their hands? Or, do they object to me because of my ideas and principles?" This too is a part of history which we can learn from. Sir, in this very House we have had many heated debates on our history, our education system. Babasaheb had said, "They cannot make history who forget history". And, when I turn the pages of how this man cherished as the architect of the Indian Constitution, saw his contribution in the making of this living document which gives us liberty, equality and fraternity, he said that these three terms did not come from me as scholar of political science. These three terms come to me from my master, the Buddha. I think that is the beauty of our Constitution that such great men and women knew where to separate their personal religious beliefs from the documents that they signed which told us what kind of a destiny we can carve out for ourselves as a nation. I think it is paradoxical that today Sharadji, a very senior parliamentarian, yet again told me बैठो-बैठो। Imagine if such a politician was a part of the Drafting Committee. Mr. Yechury is right, as a woman in India, I celebrate the fact that women in many nations across the world had to struggle to get their right to vote; I got it because my Constitution gave it so at the birth of this very nation as a Republic in 1950. But imagine, as the Leader of the House said today, what kind of restrictions such a senior parliamentarian would have imposed on a woman like me while this was being drafted. Would I have been told सांवली हो, तो वोट का अधिकार नहीं है? Would I have been told पर कटी को वोट का अधिकार नहीं है? I see that some are disturbed by what I say. But apart from the social realities that were counted in this very House today, this also is a realty we must embrace, for the victims of such reality do not reside only outside this House, but we have witnessed this in this very House. Let's look at what Babasaheb Ambedkar felt with regard to education. In the year 1945, he established the People's Education Society. Till this date two living monuments exist in the field of education which are his legacy, one in Aurangabad, which is the Milind Mahavidyalaya, set up in 1950, and the other is the Siddharth Law College in Mumbai, set up in 1956. And the very thrust with which Babasaheb set up these institutions was to bring about intellectual moral and social democracy, and he insisted that men and

women of this country will study in these institutions together shoulder to shoulder. Another part of history, Baba Saheb said: 'I would like that the right to free and compulsory education to children be given as a fundamental right while we draft this Constitution'. But the Government of the day said, let us have a Committee which can sit and look into this issue and citing costs, the advice given was, don't make it a fundamental right, put it in the Directive Principles. As I read through the Constituent Assembly debates, there were many who cautioned then that the Directive Principles are not justiciable; they cannot be enforced. They provide an architecture of good governance. But Baba Saheb felt, let us not thrust upon the future of this nation how governance should be, let us tell them how governance ought to be. And in the year, when Shri Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister of this country, he brought the Eighty-Sixth Amendment which gives children from the ages of six to fourteen free and compulsory education and this is the rock on which was built the Right to Education Act enforced on the 1st of April, 2010.

Baba Saheb fought for equity in education for those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He made provisions for them in the Constitution but as a Parliamentarian – just not as a BJP representative – I say proudly that irrespective of the challenges of this House or the other, we rose unanimously through the Sarva Shiksha Abhiyaan to give us a framework for equity in education for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, yes, यह देश विषमताओं का देश है, लेकिन इस देश में इतनी भी क्षमता है कि जब समय की मांग हो, पुकार हो, तब हम धर्म और जाति तो छोड़िए, अपनी राजनीति को परे रखकर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना जानते हैं। There are many who make a mockery of our history, our culture, civilisation. Rightly so, it is their democratic right and I don't deny that democratic right to any Indian citizen as is mine to read the following.

Gandhiji in Chatham House, possibly in 1931, when asked about the Indian education system, said and I quote: "I say without fear of my figures being challenged successfully that today – in the 1930's – India is more illiterate than it was fifty or a hundred years ago, because the British administrators when they came to India, instead of taking hold of things as they were, began to root them out. They scratched the soil and began to look at the root and left the root like that and the beautiful tree perished." Gandhiji was challenged and told to produce empirical evidence. A Gandhian named Dharampalji, went back to the Madras Presidency, took out papers just to prove with empirical evidence, he went before the British and said what Gandhiji said was right. Madras Presidency had ninety per cent literacy before the British came to India. That

[Shrimati Smriti Zubin Irani]

is a fact. That is a fact not enunciated or written by a Bhartiya Janta Party worker. It is written by a Gandhian called Dharampal. So, what do we need today? Yes, we need that this tree of enlightenment bear fruit for our future generations by embracing the scientific temper of the new and also embracing some of our rich cultural history. I pay homage to the journey of Dr. Karan Singh, he is seated before me. I have had many a conversation, even when I was not a Minister, with him. When people look at Dr. Karan Singh, they speak about his love for Sanskrit. I pay homage to the contribution you made, Sir. As, somebody who is just 39, I might be told that कि मैं चार बार जेल गया, तुम कभी नहीं गयीं। मेरी 1976 की पैदाइश है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन इतना सत्य है कि आज भी पॉलिटिकल डिवाइड्स के बावजूद संस्कृत पर हम वार्तालाप कर सकते हैं। कुछ लोग शायद अचम्भित हों और मुझसे बेहतर डा. कर्ण सिंह जी बोलेंगे। In September, 1949, Ambedkarji sponsored Sanskrit as the official language of the Indian Union and supporting him, amongst many, was a gentleman called Naziruddin Ahmed. A correspondent went to Babasaheb and said, "Why Sanskrit?" He turned around – he was quoted in two newspapers on September 11, 1949, namely, the Statesman and the National Herald – and said, "What's wrong with Sanskrit?" It is ironical that six-and-a-half decades later, I too get posed that question and I have a similar response. But, this is the very evidence and the essence of a thriving Constitution which allows debates to permeate over decades till such time a consensus emerges.

Sir, I know that there is a limitation of time, but I can proudly say that I am joined by all parliamentarians here today that we have unlimited admiration for the work of Dr. Babasaheb Ambedkar. Does that mean we shall brush aside what is fundamentally challenging in our country? No. If I look at the figures here, the percentage of out-of-school children of the Scheduled Castes has declined from 2009 to 2014. Does that mean the journey is complete? No. But, the reason we celebrate a living Constitution, a living document, is because it enables us to continue that journey till such time a collective destination of equality, liberty and fraternity is reached.

Sir, though there were questions asked as to how dare we asked schools to celebrate and possibly on what basis. Let me read a message of Babasaheb Ambedkar to his fellow citizens as I come to a close. He said, "I do not want that our loyalties as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty, whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indians first, Indians last and nothing but Indians." Sir, I humbly submit that in all CBSE schools yesterday, children flocked the morning assemblies to take oath to preserve the very values enshrined in the Constitution to celebrate the journey of this Constitution and

the future it envisions for these children. And, these children of our nation – today in this august House I can't identify by religion, creed, culture, sex – resolutely said that we all want to be Indians first, Indians last and nothing but Indians. Thank you, Sir.

DR. KARAN SINGH (NCT of Delhi): Thank you, Mr. Vice-Chairman.

Sir, our Constitution is indeed a marvellous document; surely, one of the most comprehensive in the whole world. It reflects the hopes and aspirations of one-sixth of the human race. We pay homage to the founding fathers of our Constitution, a gathering of one of the most outstanding thinkers, lawyers and political leaders in our history. Sir, it is important to remember that the Constitution was a collective endeavour over a long period, a culmination of our whole freedom movement, and for two-and-a-half years there were intensive debates on a whole variety of subjects. It is fascinating. If you look at the debates of the Constituent Assembly, every single aspect is studied thoroughly and it has stood the test of time for 65 years. It has given us a vibrant democracy, a totally free judiciary and an independent press. It has given us a place of pride in the comity of nations. We are indeed very proud of our Constitution.

This is a good occasion to pay homage to the founding fathers, particularly today on the 125th Birth Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, who was Chairman of the Drafting Committee, an outstanding scholar, a great social reformer, and his team in the Drafting Committee, which really did an extraordinary job. But I am also rather surprised that my good friend, the Leader of the House, failed to mention the fact that it was Pandit Jawaharlal Nehru who presented in 1946 the objective principles resolution to the Constituent Assembly. It was a glaring omission because that can not be overlooked. As was pointed out by the leader of the opposition that became the basis upon which the Preamble, the Fundamental Rights and the whole Constitution was based. So, I regret that in his very interesting speech he failed to mention Pandit Jawaharlal Nehru who not only introduced the objectives resolution but who, as the first Prime Minister, all the time was there to see that the idealism and the idealistic framework, the ideological framework of the Constitution as adumbrated in these principles were followed.

There were other great people. Sardar Patel was there. He was not very well. I remember, I stayed as his guest for 15 days in Dehradun in 1949. He was very kind to me. I stayed there. He was very ill. But none the less he played a major role, not only in the freedom movement, but even his last years in the framing of the Constitution. Maulana Azad, a great scholar, he was there. We can not forget Dr. Rajendra Prasad. He presided over the Constituent Assembly for 2 ½ years in the Central Hall with great dignity and grace.

[Dr. Karan Singh]

Sir, I must point out that the people who have actually drafted the Constitution B.N. Rau and Alladi Krishnaswamy Iyer, today nobody has mentioned them. In fact, Dr. Ambedkar has said that people say that it is my Constitution, it is B.N. Rau's Constitution. I knew him also, I knew all these great people luckily. I knew B.N. Rau because in my father's time, he was the Prime Minister in Jammu and Kashmir, from 1944 to 1945.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): It is history.

DR. KARAN SINGH: He was the finest draftsman in the world. So, B.N. Rau and ably aided and assisted by Alladi Krishnaswamy Iyer, I think those two people also should be remembered, because as I said, it was a collective endeavour. Dr. Ambedkar will always have the credit of chairing the Drafting Committee and of giving the thrust towards social justice. We must remember other people also on this occasion.

My colleague, the Leader of the Opposition has already made an elaborate speech; I would touch only on two points.The highly controversial (42nd Amendment), which was revoked, but there were two items that were not revoked. One was the words 'socialist' and 'secular' in the Preamble. The other were the 'fundamental duties'. Those are the two points upon which I would like to briefly touch today, because there was a total consensus. If despite all the tensions of the (42nd Amendment) of that whole period where it was revoked, these two remained, it meant that there was national consensus on these two points.

Smritiji has just now mentioned my love for Sanskrit. I will not go into the definition of 'political science'. There are many varieties of socialism ranging from Fabian socialism to Marxism-Leninism and various other types. But I think the best definition of socialism is found in our culture.सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग्भवेत्। What better definiton! 'May all people be happy, may all people be healthy, may all people see auspicious sight, may no one have to undergo suffering." That is what we mean by socialism. The last person also should not suffer.

As far as secularism is concerned, Sir, all sorts of definitions have been given. In the other House a definition was made yesterday, I do not think it sounds very nice. I have a better definition than धर्म निरपेक्ष or पंथ निरपेक्ष। Actually the definition of secularism is सर्वधर्म समभाव. We remember even our Prime Minister used to say that सर्वधर्म समभाव 'equal respect and regard for all religions.' is what we call secularism in India. It is not a European concept. In Europe there is the church and the state, and there is a distinction between the two. That doesn't exist in India. What is meant by

secularism is that every religion must be given due respect, and that again, is based upon the great Rig Vedic dictum – "एकम् सद् विप्रा बहुधा वदन्ति" The truth is one. The wise call it by many names. That is the basis of the Indian civilization and that is the basis of our secularism. So, both socialism and secularism continue to be in the Preamble and are very important factors.

Now, let us talk about the Fundamental Duties. They are an integral part of the Constitution, but, unfortunately, they are totally neglected. When I address universities, I tell students, 'I would like you to raise hands and say how many of you know that there is a Chapter on Fundamental Duties in the Constitution?' Hardly half a dozen hands are raised. Sir, the Fundamental Duties are extremely important. I was on the Drafting Committee on the Fundamental Duties, the Sardar Swaran Singh Committee. We sat together; we drafted the fundamental duties and very briefly, I want to read them out.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.)*

It won't take very long. "It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideas and institutions, the National Flag and the National Anthem; to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for Freedom; to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India; to defend the country and render national service when called upon to do so; to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women; to value and preserve the rich heritage of our composite culture; to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures; to develop a scientific temper, humanism and spirit of enquiry and reform; to safeguard public property and abjure violence; to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement."

These are such excellent principles. Why are they not known? Sir, these Fundamental Duties should be hung in every classroom. They should be hung in every office. They should be hung in every Panchayat Ghar.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Every student should be taught.

DR. KARAN SINGH: They should be taught. Why are they not taught? And that is what I want to say. When Shri Atalji was the Prime Minister, he set up a Committee to Operationalize the Fundamental Duties. I was on that Committee, headed by Justice

[Dr. Karan Singh]

J.S. Verma. We came up with two volumes of suggestions regarding how they can be operationalized. Those reports have disappeared.

So, on this occasion, I would like to urge that we must rediscover these Fundamental Duties. After all, I have the privilege of chairing the Ethics Committee of the Rajya Sabha. We have our differences. We have our sharp disagreements. We have our divergent political ideologies. But if the ethical foundations of our society, as adumbrated in the Constitution and in the Fundamental Duties, continue to erode, the nation will pay a very heavy price in the years and decades ahead. Let us, therefore, Sir, take this opportunity to rededicate ourselves to the greater good and glory of India, as enshrined and envisaged in our Constitution.

MR. DEUPTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, is Mr. Ram Kumar Kashyap there? …*(Interruptions)*… Shall we adjourn, as it is 6 o'clock already?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः अभी कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए adjourn कर दिया जाए। हम Monday को इसे ले लेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We may adjourn now, but there are a large number of speakers.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Yes, Sir. But we can extend it. If Members are ready to participate and debate, we are ready to extend it.

SOME HON. MEMBERS: Sir, let it be taken up on Monday.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. If that is the sense of the House, then let me adjourn.

The House stands adjourned till 11.00 a.m. on Monday, the 30th of November, 2015.

The House then adjourned at six of the clock till
eleven of the clock on Monday, the
30th November, 2015.